



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229599  
CG-DL-E-14092021-229599

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943

No. 266]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2021

मामला सं. (एसएसआर) 05/2021

**विषय:** चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से “अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

**फा. सं. 7/5/2021-डीजीटीआर -** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

1. प्राधिकारी ने दिनांक 11 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/9/2016-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों” के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1

अगस्त, 2016 के प्राथमिक जांच परिणामों द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जो दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या 44/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/9/2016-डीजीएडी द्वारा जारी की गई थी जिसमें चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) (शुद्धिपत्र दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा यथासंशोधित) द्वारा लगाए गए थे।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पूर्व में न हटाए गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी होना बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

*"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग या उनकी ओर से किए गए विधिवत पृष्ठकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"*

3. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
4. और जबकि, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, इंडियन स्टील एसोसिएशन (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पाॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) की ओर से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया जिसमें चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकों ने आवेदन पत्र में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई।
5. आवेदक ने चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) जारी रखने की मांग की। यह अनुरोध इस आधार पर था कि उपाय की समाप्ति से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने की संभावना है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने तथा वास्तविक क्षति बार-बार होने की संभावना है।
6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य से युक्त विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के मद्देनजर और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 31 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 7/5/2021-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
7. जांच के निष्कर्ष निकलने तक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 29 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या 36/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 15 दिसंबर, 2021 तक और उसे मिलाकर बढ़ाए गए थे।

8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 10 अप्रैल 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/9/2016-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

**ख. प्रक्रिया**

9. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में 31 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 7/5/2021-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ख. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातक तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 31 मार्च, 2021 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- ग. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- घ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- ङ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों को उनके प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। 3 मई, 2021 के पत्र द्वारा समय 20 मई, 2021 तक बढ़ाया गया था। 17 मई, 2021 के पत्र द्वारा समय फिर 3 जून, 2021 तक बढ़ाया गया था।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
  - (i) रिझाओ स्टील होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
  - (ii) बाओटौ आयरन एंड स्टील ग्रुप जिआंगसु शगांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
  - (iii) अंगांग स्टील कंपनी
  - (iv) नानजिंग आयरन एंड स्टील
  - (v) वुहान आयरन एंड स्टील
  - (vi) झानजियागांग हांगचांग स्टील प्लेट कंपनी लिमिटेड
  - (vii) जिआंगसु शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कं.
  - (viii) नानजिंग आयरन एंड स्टील ग्रुप इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
  - (ix) वुयांग न्यू हैवी एंड वाइड स्टील प्लेट कंपनी लिमिटेड
  - (x) वुयांग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
  - (xi) निप्पाँन सुमितोमो
  - (xii) जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन
  - (xiii) मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड

- (xiv) सुमितोमो कॉर्पोरेशन
- (xv) कनेमात्सु कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (xvi) टोयोटा त्शुशो कॉर्पोरेशन
- (xvii) मेटल वन कॉर्पोरेशन
- (xviii) पोसको
- (xix) डोंगकुक् स्टील मिल कर्नल लिमिटेड
- (xx) सैमवू कंपनी लिमिटेड
- (xxi) पी एंड ए निगम
- (xxii) जीएस ग्लोबल कॉर्प
- (xxiii) पोसको देवू कारपोरेशन
- (xxiv) सेवस्टील
- (xxv) ईवीआरएजेड
- (xxvi) आर्सेलर मित्तल
- (xxvii) पीटी क्राकाटाऊ पोसको, इंडोनेशिया

छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिए और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और/ अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत/दायर किए:

- क. पोसको, कोरिया गणराज्य
- ख. पीटी क्राकाटाऊ पोसको
- ग. ताइचांग स्टील कं, लिमिटेड
- घ. विनस्टील कं, लिमिटेड
- ङ. पीटी पोसको इंडोनेशिया इंटि, इंडोनेशिया-निर्यातक
- च. पीटी पोसको इंटरनेशनल इंडोनेशिया,
- छ. पीटी क्राकाटाऊ स्टील (पसेरो) टीबीके, इंडोनेशिया-निर्यातक
- ज. ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन
- झ. ह्योसुंग जापान कं, लिमिटेड
- ञ. जपोसको एशिया कंपनी लिमिटेड
- ट. पोसको इंटरनेशनल कार्पोरेशन
- ठ. सैमसंग सी एंड टी कॉर्पोरेशन
- ड. जीएस ग्लोबल कॉर्प
- ढ. जीएस ग्लोबल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
- ण. निप्पांन स्टील कॉर्पोरेशन
- त. जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन
- थ. कोबे स्टील लिमिटेड
- द. होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

- ध. जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन  
 न. कनेमात्सु कारपोरेशन  
 प. मारुबेनी-इतोचु स्टील इंक.  
 फ. मेटल वन कॉर्पोरेशन  
 ब. मित्सुई एंड कं, लिमिटेड  
 भ. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन  
 म. हिताची जोसेन कॉर्पोरेशन  
 य. आईएचआई कॉर्पोरेशन  
 कक.निसान ट्रेडिंग कं, लिमिटेड  
 खख. ओहमी इंडस्ट्रीज, लिमिटेड  
 गग. सातो शोजी कॉर्पोरेशन  
 घघ. सुमितोमो कॉर्पोरेशन  
 डड. सुमितोमो कॉर्पोरेशन ग्लोबल मेटल्स कंपनी लिमिटेड  
 चच. टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन  
 छछ. टेत्सुशो कायाबा कॉर्पोरेशन  
 जज. हुंडई स्टील कंपनी  
 झझ. हुंडई कॉर्पोरेशन  
 ञञ. सैमसंग सी एंड टी कॉर्पोरेशन  
 टट. एसके नेटवर्क्स कंपनी लिमिटेड  
 ठठ. जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन  
 डड. हनवा कं, लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:

- (i) आर्सेलर नील टेलर्ड ब्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- (ii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- (iii) भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (iv) सी.आर.आई. पंप्स प्राइवेट लिमिटेड
- (v) डेनिस प्लास्ट लिमिटेड
- (vi) फाइन फोर्ज लिमिटेड
- (vii) फ़्लैट (इंडिया) लिमिटेड
- (viii) गेम्सा विंड टर्बाइन प्रा. लिमिटेड
- (ix) हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
- (x) कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- (xi) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

- (xii) लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xiii) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
- (xiv) पोसको इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xv) सुपीरियर स्टील इंडस्ट्रीज
- (xvi) ट्रेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- (xvii) टीआरएफ लिमिटेड
- (xviii) सनग्रीन वेंटिलेशन सिस्टम्स (पी) लिमिटेड
- (xix) मेटल शाइन रूफिंग
- (xx) ओरिएंटल मेटल इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xxi) एम. के. के मेटल सेक्शन प्रा. लिमिटेड
- (xxii) व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड
- (xxiii) हुंडई स्टील इंडिया लिमिटेड
- (xxiv) हाइली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xxv) फेरम एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड
- (xxvi) राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमिटेड
- (xxvii) हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड
- (xxviii) मोबिस इंडिया लिमिटेड
- (xxix) टीआई मेटल फॉर्मिंग
- (xxx) म्युओंग शिन इंडिया ऑटोमोटोव प्राइवेट लिमिटेड
- (xxxi) क्वांगजिन इंडिया ऑटोसिस्टम्स प्रा. लिमिटेड
- (xxxii) टोयोटा किलॉस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड
- (xxxiii) वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड
- (xxxiv) बॉम्बे आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन
- (xxxv) फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (एफएएम)
- (xxxvi) ऑल इंडिया इंडकशन फर्नेस एसोसिएशन
- (xxxvii) एसोचैम
- (xxxviii) कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
- (xxxix) इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स
- (xl) ऑटो कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए)
- (xli) सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएमए)
- (xlii) इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईसीईएमए)
- (xliii) इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए)
- (xliv) प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीपीएमएआई)
- (xlv) कोल्ड रोलड स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओआरएसएमए)

झ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिए और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए तथा/अथवा हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया:

- क. पोसको-इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
- ख. पोसको-इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
- ग. पोसको-महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- घ. होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
- च. जेएफई शोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- छ. मारुबेनी-इतोचु स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ज. मेटल वन कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड
- झ. निष्पॉन स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
- ञ. टीटी स्टील सर्विस इंडिया प्रा. लिमिटेड
- ट. कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लियांसेस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीईएएमए)
- ठ. पीओएस हुंडई स्टील एमएफजी (आई) प्राइवेट
- ड. हुंडई स्टील अनंतपुर प्राइवेट लिमिटेड
- ढ. हुंडई स्टील इंडिया प्रा. लिमिटेड
- ण. हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
- त. हुंडई स्टील पाइप इंडिया प्रा. लिमिटेड
- थ. स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई)
- द. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, (एसआईएम)
- ध. थीस प्रिसिजन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- न. स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्रा. लिमिटेड
- प. रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड
- फ. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
- ब. वाईएसआई ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड
- भ. हवाशिन ऑटोइंडिया प्रा. लिमिटेड
- म. रेनॉल्ट निसान ऑटो इंडिया पीवीवाई लिमिटेड
- य. इंडियन पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- कक.जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन
- खख. मायोंग शिन इंडिया ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड
- गग. पीएचए इंडिया प्रा. लिमिटेड

ज. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 माह) है। क्षति जांच अवधि अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019, और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।

- ट. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने और क्षति विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ठ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 2 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो उन्हें दायर करें। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें सलाह दी गई थी कि उन पर अपने खंडन पेश करें।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल तक वास्तविक रूप से पहुँच नहीं थी।
- ढ. इसके अतिरिक्त, आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- ण. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ पर आधारित क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध सामानों का आयात विभिन्न ग्रेडों/ आकारों/आयामों में किया जा रहा है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद और मूल जांचों में दिए गए दृष्टिकोण के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन-दर-पीसीएन तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) को अंतिम रूप दिया। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन-दर-पीसीएन तुलना की है।
- थ. वर्तमान जांच के लिए संगत साक्ष्य से समर्थित और मानी गई सीमा तक जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर इस प्रकटन विवरण में विचार किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान यह संतुष्टि की कि क्या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना परिशुद्ध है जो संभावित सीमा तक इस प्रकटन विवरण का आधार बनती है और संगत मानी गई सीमा तक एवं संभावित सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- न. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया है।
- प. इस प्रकटन विवरण में \*\*\* गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।



फ. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 73.17 रुपए है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद (विचाराधीन उत्पाद) और समान वस्तु**

10. विचाराधीन उत्पाद "अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद" है जिसे मूल जांच में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"2100 मिमी तक की चौड़ाई और 25 मिमी तक की मोटाई की काँइलों में अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और 4950 मिमी तक की चौड़ाई और 150 मिमी तक की मोटाई के काँइल रहित 10 अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (सामान्य रूप से शीट्स और प्लेटों के रूप में जाने जाते हैं)।"

विचाराधीन उत्पाद में वे उत्पाद शामिल हैं जिनमें हॉट रोल्ड से आगे कार्य नहीं किया जाता है और 'एज़-रोल्ड' एज अथवा 'ट्रिम्ड' एज अथवा 'स्लिट' एज अथवा "मिल्ड" एज अथवा "शियर्ड" एज अथवा "लेजर-कट" एज अथवा "गैस-कट" एज अथवा किसी अन्य किस्म की एज वाली आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील, प्राइम अथवा नॉनप्राइम स्थिति में, के फ्लैट उत्पाद हैं। ये उत्पाद पिकल्ड और नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास अथवा टेम्परिंग अथवा उसके बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, नॉर्मलाइज़्ड अथवा इन-नॉर्मलाइज़्ड, अल्ट्रा-सोनिकली परीक्षित अथवा अपरीक्षित अथवा ऑयल्ड अथवा नॉन-ऑयल्ड आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद "एज़-रोल्ड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकल रोल्ड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकल कंट्रोल्ड रोल्ड" अथवा "कंट्रोल रोल्ड" अथवा "नॉर्मलाइज़्ड रोल्ड" अथवा "नॉर्मलाइज़्ड" अथवा किसी अन्य समान प्रक्रिया के अध्यधीन हो सकते हैं। ये उत्पाद हॉट रोलिंग के दौरान सीधे ही तैयार की गई विभिन्न किस्मों के रिलीफ/चेकर्ड पैटर्न में हो सकते हैं। ये उत्पाद पिकलिंग, ऑयलिंग, रिवाइंडिंग, रीकोइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्ररूपान्तर चरणों के अध्यधीन हो सकते हैं। ये उत्पाद सैंड ब्लास्टेड अथवा शॉट ब्लास्टेड अथवा समान प्रक्रिया के अध्यधीन हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स और अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील की प्लेटें, चाहे रिवर्सिबल प्लेट मिल सहित यूनिवर्सल प्लेट मिल से रोल्ड हो अथवा नहीं अथवा हॉट स्ट्रिप मिल अथवा टेंडेम मिल अथवा स्टेकल मिल अथवा 2-हाई, 3-हाई, 4-हाई, क्लस्टर मिल के रोलिंग आकार की विभिन्न किस्मों के साथ किसी अन्य समान प्रक्रिया अथवा किसी समान हॉट रोलिंग प्रक्रिया शामिल होती है। विचाराधीन उत्पाद में हॉट रोलिंग प्रक्रिया से या तो सीधे ही उत्पादित अथवा हॉट रोल्ड काँइल से काटी गई/शीयर की गई शीटें और प्लेटें शामिल होती हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

1. स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।
2. स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड होते हैं।
3. स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद अन्यथा प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड।
4. क्लैडेड स्टील।"

11. निर्णायक समीक्षा होने के नाते, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद के उपर्युक्त क्षेत्र को अपनाया।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा याचिका में किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया था। तथापि, यह नोट किया गया था कि मूल जांच में, घरेलू उद्योग द्वारा पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया गया था, और प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन-दर-पीसीएन की तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) निर्धारित की थी। अतः, प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए मूल जांच में वर्णित उन्हीं पीसीएन को अपनाने का प्रस्ताव किया और 14 अप्रैल तक पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।
13. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने उचित तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाया है और हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने का अनुरोध किया:

हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के पीसीएन				
क्रम सं.	गुणधर्म	अंकों की संख्या	विवरण	कोड
1	से उत्पाद	1	काँइल	सी
			लंबाई में कटस्लिट-, शीट और प्लेट्स	एल
			प्लेट मिल प्लेट	पी
2	गुणवत्ता	4	कोल्ड रोलिंग/गेल्वनाइजिंग क्वालिटी	क्यू01क्यू
			पाइप और ट्यूब गुणवत्ता	क्यू02क्यू
			एचएसएलए सहित उच्च तन्यता	क्यू03क्यू
			हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील (वाईएस)350 एमपीए और ऊपर)	क्यू04क्यू
			स्ट्रक्चरल स्टील (वाई एस 350 एमपीए और ऊपर)	क्यू05क्यू
			जाँच की गई गुणवत्ता	क्यू06क्यू
			ड्राइंग फ़्लैंगिंग/बनाने/गुणवत्ता वाले स्टील	क्यू07क्यू
			एपीआई ग्रेड X52 और उससे अधिक की गुणवत्ता वाले स्टील	क्यू08क्यू
			X52 गुणवत्ता वाले स्टील से कम एपीआई ग्रेड	क्यू09क्यू
			क्वेंचटेम्पर्ड गुणवत्ता/	क्यू10क्यू
			कोरोजिन रेसिस्टेंट स्टील क्वालिटी	क्यू11क्यू
			बॉयलर/प्रेसर वेसेल क्वालिटी	क्यू12क्यू
			शिप बिल्डिंग क्वालिटी	क्यू13क्यू
			एलपीजी सिलेंडर क्वालिटी	क्यू14क्यू
			मध्यम/उच्च कार्बन स्टील क्वालिटी	क्यू15क्यू
			सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील	क्यू16क्यू
			अन्य गुण जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं	क्यू17क्यू
3	मोटाई	1	1.6 मिमी. तक	टी
			1.6 मिमी से अधिक 2 मिमी. तक	यू
			2 मिमी से अधिक 10 मिमी. तक	वी
			10 मिमी से अधिक 25 मिमी. तक	डब्ल्यू
			25 मिमी से अधिक 40 मिमी. तक	एक्स
			40 मिमी से अधिक 100 मिमी. तक	वाई
			100 मिमी से अधिक 150 मिमी. तक	जेड
4	चौड़ाई	1	600 मिमी. तक	1
			600 मिमी से अधिक 1500 मिमी. तक	2
			1500 मिमी से अधिक 2500 मिमी. तक	3

			2500 मिमी से अधिक 3000 मिमी. तक	4
			3000 मिमी से अधिक तक .	5
5	लांगिट्यूडिनियल एज्स	2	रोल किया हुआ	ईबी
			शेयरड/ट्रीमड/मिल्ड/गैस-कट आदि	ईडी
6	सरफेस ट्रीटमेंट/सरफेस प्रीपेरेशन	1	पिकल्ड	एच
			सैंड ब्लास्ट/शॉट ब्लास्ट	I
			पेंटेड	J
			नो सरफेस ट्रीटमेंट/नो सरफेस प्रीपेरेशन	K
7	हीट ट्रीटमेंट	1	अन-नॉर्मलाइज्ड	8
			नॉर्मलाइजिंग	9
उदाहरण: चेकर्ड गुणवत्ता की एक प्लेट मिल प्लेट, इन-नॉर्मलाइज्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट वाले पिकल्ड रूप में 750 मिमी शीयर्ड एज की चौड़ाई वाले 80 मिमी मोटाई, पीसीएन (II अंक): पीक्यू06क्यूवाई2ईडीएच8 होगा।				

14. हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उपर्युक्त पीसीएन ढांचे के आधार पर सूचना उपलब्ध कराई।
15. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड-रोलिंग, पाइप और ट्यूब विनिर्माण, अवसंरचना और निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और निर्माण, अर्थ-मूविंग और खनन उपस्करों, भंडारण टैंकों, कम दबाव वाले हीटर, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों आदि के लिए संयंत्र और प्ररूपान्तर उपस्करों जैसे कई अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है।
16. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन मदों को हटाकर जो उत्पाद के क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़े निकालने हेतु डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया।
17. जबकि हितबद्ध पक्षकारों से अलग-अलग कंपनियों के आंकड़ों का पीसीएन वार ब्यौरा उपलब्ध था, आधिकारिक डीजीसीआईएस आंकड़ों को पीसीएन के संदर्भ में परिवर्तित नहीं किया जा सका क्योंकि डीजीसीआईएस आंकड़ों में दिया गया विवरण आयात लेनदेनों की भारी संख्या मिलाने के लिए पीसीएन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त नहीं था।

#### ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

18. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
  - क. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।
  - ख. उपभोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और संबद्ध देशों के उत्पादकों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं।
  - ग. निर्णायक समीक्षा में, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहेगा जो मूल जांच में निर्धारित किया गया था।
  - घ. पीटीकेपी और एनएससी द्वारा उत्पादित ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा भी उत्पादित किए जाते हैं। इस संबंध में साक्ष्य अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।
  - ङ. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में ईएन एस-355/आईएस ई-350 ग्रेडों की आपूर्ति की है। विशेष रूप से, \*\*\*, पूरी क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान उपर्युक्त ग्रेडों की आपूर्ति करता रहा है और इस संबंध में साक्ष्य अलग से प्रस्तुत किया गया है।

- च. निप्पाँन स्टील कॉरपोरेशन ("एनएससी") ने आरोप लगाया है कि उसके द्वारा उत्पादित कुछ ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बेचे जाते हैं क्योंकि वे उनके ब्रोशर में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एनएससी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के साथ तुलना करने की अनुमति देने के लिए विभिन्न ग्रेडों के पर्याप्त तकनीकी मानदंड नहीं दिए हैं। प्रदर्श अलग किए जाने की मांग किए गए उत्पाद किस्म और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के बीच तकनीकी अंतर को स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं करता है। साथ ही, पाटनरोधी जांच में गुणवत्ता किसी उत्पाद किस्म को अलग करने के लिए मानदंड नहीं है। घरेलू उद्योग हर प्रकार की मोटाई के सभी ग्रेडों के स्टील की आपूर्ति करता है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं और उन्हें सत्यापित किया जा सकता है।
- छ. चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमिनियम फॉयल (फा. सं. 06/21/2020-डीजीटीआर), चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न (फा.सं. 6/11/2019-डीजीटीआर) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लोर इलास्टोमेर' (एफकेएम) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने माना कि विशिष्टियों में गुणवत्ता अथवा छोटे से अंतर विचाराधीन उत्पाद को अलग करने के लिए प्रासंगिक संगत नहीं थे। माननीय सेसटेट ने डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में भी यह माना कि 'समानता' सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता में अंतर संगत मानदंड नहीं है जिस पर प्राधिकारी द्वारा यह मानने के लिए कि गुणवत्ता में अंतर मानदंड नहीं है, चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पाउडर रूप में ब्लैक टोनर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में विश्वास किया था।

## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

19. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- क. एएमएनएस को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग (डीआई) का हिस्सा नहीं माना गया है और उनके द्वारा विशेष रूप से निर्मित विचाराधीन उत्पाद के ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना है।
- ख. उत्पादों की समानता का आकलन अंतिम प्रयोग, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, उत्पाद गुणधर्मों, प्रकृति और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन अपीलिय निकाय द्वारा जापान – एल्कोहॉल बेवरेजेस, कनाडा - पत्रिकाएं, इंडोनेशिया में विश्व व्यापार संगठन पैतल - ऑटो द्वारा और सीमा कर समायोजन संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट 1970 में उल्लिखित किया गया है।
- ग. निप्पाँन स्टील कॉरपोरेशन ("एनएससी") विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करता है जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों में वाणिज्यिक रूप से अथवा तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। एनएससी के उस ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। पूर्व पाटनरोधी परिपाटी, डीजीटीआर एसओपी और प्राधिकारियों के जांच परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं।
- घ. प्राधिकारी द्वारा किए गए कई जांच परिणाम हैं जहां डीजीटीआर ने कुछ ग्रेडों को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा क्योंकि घरेलू उद्योग ने निर्यातक के इस दावे का खंडन नहीं किया था कि वे उक्त ग्रेडों का उत्पादन नहीं कर सके।
- ङ. एनएससी के ग्रेड अलग-अलग गुणधर्मों के साथ भिन्न होते हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों में वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हो सकते। घरेलू उद्योग के उत्पाद ब्रोशर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
- च. एएमएनएस को घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किया जा सकता और परिणामस्वरूप जेएसडब्ल्यू और सेल को छोड़कर उनके द्वारा विशेष रूप से विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के किसी भी ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए।

- छ. पीटीकेपी द्वारा भारत में विनिर्मित और निर्यात किए जाने वाले विभिन्न उत्पाद ग्रेड हैं जिनका घरेलू उद्योग ऐसे किसी विकल्प का उत्पादन या बिक्री नहीं करता है जो वाणिज्यिक अथवा तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हो। प्राधिकारी द्वारा अपने कई जांच परिणामों में भी यही पाया गया है। इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता।
- ज. अन्य के साथ अंतिम प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए आयातित उत्पादों की समानता को देखते हुए; उपभोक्ता की प्राथमिकताओं; उत्पाद गुणधर्मों, प्रकृति और गुणवत्ता और तदनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले ग्रेडों को अलग नहीं किया जा सकता।
- झ. ईएन एस-355/आईएस ई-350 के अनुरूप दोहरी विशिष्ट एचआर प्लेटों के विशेष ग्रेड को इस जांच के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग तुलनीय गुणवत्ता के उत्पादों का विनिर्माण नहीं करता। पीटीकेपी द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले स्पेशलिटी ग्रेड प्लेटों का उत्पादन पूरी तरह से भारतीय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। उत्तरदाता द्वारा विनिर्मित एचआर प्लेट्स यूरोपीय और भारतीय मानकों (एन/आईएस विशिष्ट) में निर्धारित तकनीकी उच्च गुणवत्ता से कहीं अधिक हैं जो केवल आरंभिक आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। इन विशिष्टताओं और परीक्षण परिणामों का वर्णन भारतीय उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए प्रत्येक मिल परीक्षण प्रमाणपत्र में किया जाता है, जिन्होंने विभिन्न अंतिम प्रयोगों के अनुसार अनुरोध किया था। विशेषता ग्रेड जो विशेष विशेषताओं के साथ ईएन/आईएस में दोहरे प्रमाणित हैं, भारतीय बाजार में सामान्य हॉट-रोलड कॉइल की तुलना में समान वस्तु नहीं हैं।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि पहले की गई जांच में परिभाषित किया गया था। फिर भी, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को अलग करने की मांग करने वाले कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों की जांच की है।
21. पीटी. क्राकाटाऊ-पोसको, इंडोनेशिया ने एचआर स्टील जो कॉइल एन एस-355/आईएस ई-350 ग्रेड में नहीं है, को अलग करने की मांग की है क्योंकि घरेलू उद्योग में इसका उत्पादन करने की क्षमता नहीं है और उनकी तकनीकी उच्च गुणवत्ता में उससे कहीं अधिक हैं जो यूरोपीय और भारतीय मानक (ईएन/आईएस विशिष्टता) में निर्धारित है। निष्पान स्टील कॉरपोरेशन ने उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न ग्रेडों को अलग करने की मांग की है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड में वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना से, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग ईएन एस-355/आईएस ई 350 ग्रेड का उत्पादन कर रहा है। अतः, प्राधिकारी इन दोनों ग्रेडों को अलग करने का कोई कारण नहीं पाते।
22. जापान के उत्पादक और निर्यातक अर्थात् एम.एस. एनएससी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग उत्पाद के क्षेत्र में शामिल उन ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है; ii) घरेलू उद्योग कुछ ग्रेड का निर्माण करता है परंतु गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है; और iii) कुछ ग्रेडों के लिए, घरेलू उद्योग के पास ग्राहक की मंजूरी नहीं है। घरेलू उद्योग ने इन हितबद्ध पक्षकारों के दावों का समाधान करते हुए एक विस्तृत उत्तर दायर किया है।
23. विचाराधीन उत्पाद को हटाए जाने संबंधी मुद्दों की वस्तुपरक रूप से जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान एनएससी द्वारा निर्यात किए गए पीसीएन और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीसीएन की जांच की। सूचना की विस्तृत जांच से, प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग ने एनएससी द्वारा विनिर्मित प्रत्येक पीसीएन के लिए या तो पूरी तरह से मिलते-जुलते पीसीएन का विनिर्माण किया है या एक समान पीसीएन का विनिर्माण किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि उत्पाद के क्षेत्र से किसी को अलग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
24. प्राधिकारी ने सत्यापित किया कि घरेलू उद्योग उन सभी ग्रेडों का विनिर्माण कर रहा है जिनके लिए उसे ऑर्डर मिले हैं, और भारत में प्रयोक्ताओं को उनकी आपूर्ति भी की है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह स्थापित करता है कि उन्होंने घरेलू उद्योग से किसी विशेष ग्रेड को प्राप्त करने का प्रयास किया है जिसके विरुद्ध संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा बहिष्करण की मांग की गई है लेकिन घरेलू उद्योग इसकी आपूर्ति करने में असमर्थ था।

25. जहां तक गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता में अंतर पाटनरोधी जांच में किसी वस्तु को अलग करने के लिए संगत मानदंड नहीं है जैसा कि पूर्व में की गई कई जांचों में किया गया है जिनमें (क) चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पाउडर के रूप में ब्लैक टोनर" (फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच और (ख) चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (फा. सं. 6/11/2019-डीजीटीआर) शामिल हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गुणवत्ता का पहलू किसी उत्पाद को 'समान वस्तु' के क्षेत्र से अलग करने का कारक नहीं होने के कारण माननीय सेसटेट द्वारा डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माना गया है जिसमें यह माना गया था कि "अपीलकर्ताओं के वकील की दलील तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उन्होंने यह दर्शाने के लिए विनिर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई साक्ष्य/तकनीकी साहित्य पेश नहीं किया कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत में निर्यातित सामानों से भिन्न था। वह यह सिद्ध करने में विफल रहे कि वे समान और परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं, सिवाय इसके कि वे विभिन्न ग्रेड के थे। गुणवत्ता में अंतर किसी वस्तु को भिन्न नहीं बना देगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह टिप्पणी करना सही था कि 'इस तथ्य कि गुणवत्ताएं भिन्न हो सकती हैं, का अर्थ यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं'। हम इस मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए जांच परिणामों में व्यवधान करने का कोई वैध कारण नहीं पाते।"
26. अतः, प्राधिकारी यह पाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी को अलग किए जाने की मंजूरी देने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जैसा कि मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित किया गया है, और साथ ही संबद्ध समीक्षा जांच में उल्लिखित किया गया है जिसे नीचे दिया गया है:

*"2100 मिमी तक की चौड़ाई और 25 मिमी तक की मोटाई की काइलों में अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और 4950 मिमी तक की चौड़ाई और 150 मिमी तक की मोटाई के काइलरहित 10 अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (सामान्य रूप से शीट्स और प्लेटों के रूप में जाने जाते हैं)।"*

*विचाराधीन उत्पाद में वे उत्पाद शामिल हैं जिनमें हॉट रोल्ड से आगे कार्य नहीं किया जाता है और 'एज-रोल्ड' एज अथवा 'ट्रिड' एज अथवा 'स्लिट' एज अथवा "मिल्ड" एज अथवा "शियर्ड" एज अथवा "लेजर-कट" एज अथवा "गैस-कट" एज अथवा किसी अन्य किस्म की एज वाली आयरन, अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील, प्राइम अथवा नॉनप्राइम स्थिति में, के फ्लैट उत्पाद हैं। ये उत्पाद पिकल्ड और नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास अथवा टेम्परिंग अथवा उसके बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, नॉर्मलाइज्ड अथवा इन-नॉर्मलाइज्ड, अल्ट्रा-सोनिकली परीक्षित अथवा अपरीक्षित अथवा ऑयलड अथवा नॉन-ऑयलड आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद "एज-रोल्ड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकल रोल्ड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकल कंट्रोल रोल्ड" अथवा "कंट्रोल रोल्ड" अथवा "नॉर्मलाइज्ड रोल्ड" अथवा "नॉर्मलाइज्ड" अथवा किसी अन्य समान प्रक्रिया के अध्यधीन हो सकते हैं। ये उत्पाद हॉट रोलिंग के दौरान सीधे ही तैयार की गई विभिन्न किस्मों के रिलीफ/चेकर्ड पैटर्न में हो सकते हैं। ये उत्पाद पिकलिंग, ऑयलिंग, रिवाइंडिंग, रीकोइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्ररुपांतर चरणों के अध्यधीन हो सकते हैं। ये उत्पाद सैंड ब्लास्टेड अथवा शाँट ब्लास्टेड अथवा समान प्रक्रिया के अध्यधीन हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स और अलाय अथवा नॉन-अलाय स्टील की प्लेटें, चाहे रिवर्सिबल प्लेट मिल सहित यूनिवर्सल प्लेट मिल से रोल्ड हो अथवा नहीं अथवा हॉट स्ट्रिप मिल अथवा टेडेम मिल अथवा स्टेकल मिल अथवा 2-हाई, 3-हाई, 4-हाई, क्लस्टर मिल के रोलिंग आकार की विभिन्न किस्मों के साथ किसी अन्य समान प्रक्रिया अथवा किसी समान हॉट रोलिंग प्रक्रिया शामिल होती है। विचाराधीन उत्पाद में हॉट रोलिंग प्रक्रिया से या तो सीधे ही उत्पादित अथवा हॉट रोल्ड काइल से काटी गई/शीयर की गई शीटें और प्लेटें शामिल होती हैं।*

*विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:*

1. स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।

2. स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड होते हैं।

3. स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद अन्यथा प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड।

4. क्लैडेड स्टील।”

27. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित सामानों से तुलनीय है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया है और कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

##### घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

28. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पांन स्टील इंडिया लिमिटेड की ओर से आवेदक इंडियन स्टील एसोसिएशन का भारत में संबद्ध सामानों के लिए कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ख. जेएसडब्ल्यू ने विचाराधीन उत्पाद की न्यूनतम मात्रा - [\*\*\*] मी. टन अर्थात् जेएसडब्ल्यू के विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का \*\*\*% आयात किया था।

ग. एएमएनएस, जो 16 दिसंबर 2019 से आर्सेलर मित्तल और निप्पांन स्टील से संबंधित एक कंपनी बना, ने बहुत कम मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया था। इस तरह की छोटी मात्रा नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग होने से दोनों कंपनियों की विशेषताओं में परिवर्तन नहीं करती है। यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि एएमएनएस ने अपनी नीति को संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक से आयातक/व्यापारी की नीति में बदल दिया है। एएमएनएस ने अपनी संबंधित कंपनी निप्पांन स्टील से पाटन में योगदान नहीं किया है। एएमएनएस द्वारा किए गए आयात मात्रा में नगण्य थे क्योंकि यह अपने उत्पादन के (i) [0.2%] से कम है, (ii) भारत में कुल आयात का [1%] है, (iii) घरेलू उद्योग के उत्पादन के कुल उत्पादन का [0.1%] है, और (iv) कुल भारतीय उत्पादन का [0.02%] है। एएमएनएस का जोर और संचालन का क्षेत्र संबद्ध सामानों का विनिर्माण जारी है और संबद्ध सामानों के व्यापार में नहीं लगा हुआ है।

घ. एएमएनएस, 16 दिसंबर 2019 से आर्सेलर मित्तल और निप्पांन स्टील से संबद्ध है। मैसर्स निप्पांन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉरपोरेशन, जापान ("एनएसएसएमसी") की भी एएमएनएस में कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है, परंतु कई मध्यस्थता करने वाले स्वतंत्र कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा अलग की गई एक मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी में एक छोटा सा दावेदार है। एएमएनएस भारत में कानून के तहत निगमित एक कंपनी आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आर्सेलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमिटेड नीदरलैंड से कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी ओके होल्डिंग्स बीवी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एनएसएसएमसी के पास ओके होल्डिंग्स बीवी अर्थात् एएमएनएस लक्ज़मबर्ग होल्डिंग का मूल कंपनी में 40% का अल्प दावा है, जिसमें अधिक दावा एएम बेलवल एंड डिफरडेंज लक्ज़मबर्ग का है। एएमएनएस एक स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी है और अपने शेयरधारकों के व्यक्तिगत हितों को नहीं दर्शाती है। एक घरेलू उत्पादक के रूप में, यह तथ्य कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ मिलकर वर्तमान निर्णायक समीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे आया है, इस बात का प्रमाण है कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों से भिन्न तरीके से कार्य नहीं कर रहा है।

- ड. एएमएनएस ने विचाराधीन उत्पाद के दौरान एनएसएसएमसी से कोई उत्पाद आयात नहीं किया है। एएमएनएस का किसी भी उत्पाद की खरीद या बिक्री के लिए एनएसएसएमसी या उसकी सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों के साथ कोई संविदाएं नहीं है। एएमएनएस की खरीद, उत्पादन और बिक्री नीति किसी मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी में एनएसएसएमसी के शेयर रखने के कारण किसी भी अप्रिय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करती है।"
- च. नियम 2(ख) में 'हो सकता है' शब्द घरेलू उद्योग के क्षेत्र में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है, भले ही संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादक या निर्यातक से उसका संबंध बना रहे, यदि घरेलू उद्योग का जोर घरेलू उत्पादन पर बना रहा है।
- छ. यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि एएमएनएस ने अपनी नीति को घरेलू उत्पादक से आयातक/व्यापारी की नीति में बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, एएमएनएस ने अपनी संबंधित कंपनी - निप्पॉन स्टील से संबद्ध सामानों के पाटन में किसी भी तरह से योगदान नहीं किया है क्योंकि इसके द्वारा किए गए आयात इससे नहीं बल्कि कोरिया से थे।
- ज. ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि एएमएनएस ने संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक की नीति को आयातक/व्यापारी की नीति में बदल दिया है। एएमएनएस ने अपनी संबंधित कंपनी निप्पॉन स्टील से पाटन में योगदान नहीं किया है। एएमएनएस द्वारा किए गए आयात मात्रा में नगण्य थे क्योंकि यह (i) अपने उत्पादन का 0.2%, (ii) भारत में कुल आयात का 1%, (iii) घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 0.1%, और (iv) कुल भारतीय उत्पादन का 0.02% से कम है। एएमएनएस का जोर और संचालन का क्षेत्र संबद्ध सामानों के विनिर्माण पर जारी है और संबद्ध सामानों के व्यापार में नहीं लगा हुआ है।
- झ. चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'बैंबू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 10 अप्रैल 2012 के अंतिम जांच परिणाम में परीक्षण के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एएमएनएस द्वारा किए गए आयातों को उकसाये या कीमतों में गिरावट में योगदान दे या यह कि इसे पाटन के प्रभाव से बचाया गया हो या जहां उन्हें उनसे अनुचित लाभ हुआ हो। एएमएनएस द्वारा किए गए आयात नगण्य थे और वे बाजार पर कीमतों में गिरावट में योगदान नहीं कर पाए या एएमएनएस को उनके प्रभाव से बचा पाए, या एएमएनएस को अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं कर सके। निप्पॉन स्टील के साथ संबंध से एएमएनएस के मूल क्रियाकलाप प्रभावित नहीं हुए जो भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहा है और एएमएनएस ने अपने उत्पादन क्रियाकलापों को कम नहीं किया है या व्यापार में नहीं बदला है। निप्पॉन स्टील के साथ संबंध से न ही उससे एएमएनएस द्वारा कोई आयात किया गया है। निप्पॉन स्टील ओके होल्डिंग्स बीवी में अपनी 40% हिस्सेदारी के कारण एएमएनएस को अपने व्यापार को बदलने और संबद्ध सामानों के व्यापार का सहारा लेने के लिए प्रभावित नहीं कर सकता। अतः एएमएनएस को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग नहीं किया जाएगा।
- ञ. यहां तक कि यदि एएमएनएस को अलग किया जाना जाना था, तो शेष घरेलू उत्पादकों अर्थात् जेएसडब्ल्यू लिमिटेड और सेल का भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन का 35-45% हिस्सा होगा जो नियम 5(3)(क) में उल्लिखित 25% की सीमा से अधिक है और नियम 2(ख) के तहत एक बड़ा अनुपात है जो 50% से अधिक होने की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यूटी/डीएस440/आर - चीन में संयुक्त राज्य अमेरिका और लुब्रीज़ोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से कुछ ऑटोमोबाइल पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट - जहां यह माना गया था कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से एक प्रमुख अनुपात बनने के लिए 50% से अधिक घरेलू उत्पादन के लिए जिम्मेदार होना आवश्यक नहीं था। जेएसडब्ल्यू स्टील लि. और सेल द्वारा कुल उत्पादन में हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए और घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण, गंभीर और काफी हैं।
- ट. इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदन के समर्थकों के साथ अर्थात् टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, आवेदन पत्र के प्रति समर्थन आवेदक द्वारा किया गया है जिसका घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा है।



## घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

29. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. एएमएनएस स्वयं विचाराधीन उत्पाद का आयातक है और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक अर्थात् जापान से निप्पाँन स्टील जो संबद्ध देशों में से एक है, से भी संबंधित है। एएमएनएस ने \*\*\* मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का आयात किया जो एक छोटी संख्या नहीं है और इसे प्रयोक्ता उद्योग को बेचा जाना चाहिए था न कि केवल परीक्षण/नमूना उद्देश्य के लिए।
- ख. एएमएनएस आर्सेलर मित्तल और निप्पाँन स्टील कॉर्पोरेशन के बीच 60:40 का संयुक्त उद्यम है। निप्पाँन स्टील कॉर्पोरेशन, जिसकी एएमएनएस में 40% हिस्सेदारी है, जापान में स्थित है जो एक संबद्ध देश है और भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद का एक ज्ञात निर्यातक है। चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'बैंबू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में यह माना गया था कि जांचकर्ता प्राधिकारी एक संबंधित उत्पादक को अलग कर सकते हैं जहां संबद्ध पक्षकारों ने (क) बाजार पर कीमतों में गिरावट में के लिए उकसाया हो अथवा योगदान किया हो (ख) प्रभावों से उनका बचाव किया गया हो, या (ग) जहां वे उनसे अनुचित रूप से लाभान्वित हुए हों।
- ग. निप्पाँन स्टील कॉर्पोरेशन 40% शेयरधारिता के आधार पर किसी विशेष प्रस्ताव को रोक सकता है और इस प्रकार एएमएनएस के समग्र प्रचालन के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां रखता है। एएमएनएस दिसंबर, 2019 से निप्पाँन स्टील की सहायक कंपनी बन गई जो कि जांच का अवधि का हिस्सा है। इस प्रकार, एएमएनएस, जिसने जांच की अवधि से पहले क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया था, ने जांच की अवधि के दौरान आयात किया। यह दर्शाता है कि एएमएनएस की स्थिति अब घरेलू उद्योग की नहीं है बल्कि वह एक आयातक भी है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी एएमएनएस और निप्पाँन स्टील कॉर्पोरेशन जापान के बीच लेनदेन की प्रकृति के संबंध में घरेलू उद्योग से सूचना प्रकट करने की मांग करें। घरेलू उद्योग के क्षेत्र से एएमएनएस को अलग किए जाने को देखते हुए घरेलू उद्योग का हिस्सा 50% से कम हो जाएगा और शेष उत्पादक 'बड़े अनुपात' की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे।
- घ. टाटा और टाटा बीएसएल से समर्थन रद्द किए जाने योग्य है क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने व्यापार सूचना संख्या 13/2018 के तहत अपना समर्थन दर्ज करने के लिए सूचना प्रदान नहीं की है। टाटा, टाटा बीएसएल और एएमएनएस की अस्वीकृति को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादकों का हिस्सा घटकर 50% से कम हो जाएगा। चूंकि वर्तमान आवेदन पत्र घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 50% बनाने वाले उत्पादकों, समर्थक उत्पादकों और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित नहीं होगा, अतः निर्णायक समीक्षा रद्द की जानी है।
- ङ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में भाग लेने वाली कंपनियों के कुछ हिस्से के लिए इस्पात मंत्रालय की संयुक्त संयंत्र समिति की रिपोर्ट पर विश्वास करता है, लेकिन व्यापार संवेदी सूचना का दावा करने वाला अगोपनीय रूपांतर नहीं दिया। यह देखते हुए कि ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, घरेलू उद्योग को उत्तरदाता को यह देने का निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि उत्तरदाता को इसका उचित खंडन करने का अवसर दिया जा सके।
- च. याचिका के अनुसार, जेएसडब्ल्यू और एएमएनएस द्वारा किया गया आयात भारत में कुल आयात, संबंधित उत्पादक के कुल उत्पादन और कुल भारतीय उत्पादन में 1% से कम है। डीजीटीआर को इन दावों का सत्यापन करना चाहिए। डीजीटीआर को यह जांच करनी चाहिए कि क्या एएमएनएस और जेएसडब्ल्यू द्वारा किए गए आयात समग्र रूप से संबद्ध देशों और प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की तुलना में न्यूनतम हैं। यदि ये आयात न्यूनतम से अधिक हैं, तो वे घरेलू उद्योग के घटक नहीं हो सकते और संबद्ध देशों से अन्य आयातों में अपने आयातों के कारण क्षति, यदि कोई है, को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखितानुसार परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

31. यह आवेदन पत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की ओर से इंडियन स्टील एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है तथा टाटा और टाटा बीएसएल द्वारा इसका समर्थन किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक का कुल भारतीय उत्पादन में 58 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थकों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 79 प्रतिशत है।
32. जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों तथा निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान के साथ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के संबंध के बारे में निम्नलिखित नोट किया:

“तीन आवेदक उत्पादकों में से, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कम मात्रा का आयात किया है। चूंकि उनके द्वारा आयात की गई मात्रा कम है और उनका जोर और प्रचालन का क्षेत्र घरेलू समान वस्तुओं का निर्माण करने पर बना हुआ है, न कि संबद्ध सामानों के व्यापार में लगे रहने पर, अतः प्राधिकारी उन्हें घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानना उचित समझते हैं।

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 02.08.2017 के आदेश द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में स्वीकार किया गया था। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 द्वारा सिद्ध प्रक्रिया के अनुसरण में आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सफल समाधान आवेदक बन गया और 16.12.2019 से कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता पर अधिकार कर लिया। कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किए जाने के अनुसरण में, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर 08.01.2020 से आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित है। यह हॉट रोलड उत्पादों (काइल और नॉट-इन काइल दोनों में) और कोल्ड रोलड उत्पादों का घरेलू उत्पादक है और भारत में उसकी काफी उत्पादन क्षमताएं हैं तथा आगे और विस्तार करने की प्रक्रिया में है। मैसर्स निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान की आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड में कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है, लेकिन कई मध्यस्थता करने वाले स्वतंत्र कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा अलग की गई एक मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी में छोटी शेयरधारिता है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ने पीओएल के दौरान निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड एक स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित कंपनी है और अपने शेयरधारकों के व्यक्तिगत हितों को नहीं दर्शाती है। एक घरेलू उत्पादक के रूप में, यह तथ्य कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ मिलकर वर्तमान निर्णायक समीक्षा साध्य प्राप्त करने के लिए आगे आया है, इस बात का प्रमाण है कि यह अन्य घरेलू उत्पादकों से भिन्न तरीके से कार्य नहीं कर रहा है।”

33. कई हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र में एएमएनएस को शामिल करने का इस आधार पर विरोध किया है कि इसके द्वारा किए गए आयात पर्याप्त हैं और मैसर्स निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान के साथ इसका संबंध भी इसे ऐसा मानने से अपात्र बनाता है।
34. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एएमएनएस घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल होने के लिए योग्य है क्योंकि इसने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी ने एएमएनएस द्वारा किए गए आयातों की जांच की और उन्हें नगण्य पाया क्योंकि वे (i) एएमएनएस के उत्पादन का \*\*%, (ii) भारत में कुल आयात का 1%, (iii) घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का \*\*%, (iv) कुल भारतीय मांग का \*\*% से कम हैं। जांच करने पर, प्राधिकारी

पाते हैं कि इतने कम आयात- (क) बाजार में कीमतों में गिरावट में योगदान नहीं देते; (ख) पाटित आयातों के प्रभाव से घरेलू उद्योग से बचाव नहीं करते, या (ग) घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ प्रदान नहीं करते। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जेएसडब्ल्यू द्वारा किए गए आयात भी नगण्य हैं जो जेएसडब्ल्यू के कुल उत्पादन का केवल \*\*\*% है।

35. निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान के साथ एएमएनएस के संबंध के बारे में, प्राधिकारी ने जांच शुरू करते समय पहले ही नोट कर लिया था कि मैसर्स निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान की आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड में कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है, लेकिन कई मध्यस्था करने वाले स्वतंत्र कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा अलग की गई एक मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी में छोटी शेयरधारिता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। यह प्राधिकारी की सूचना में कोई अतिरिक्त तथ्य नहीं लाया गया है कि जो यह बताए कि निप्पॉन स्टील एंड सुमितोमो मेटल कॉर्पोरेशन, जापान से संबंध के कारण एएमएनएस समान वस्तु के घरेलू उत्पादक से भिन्न व्यवहार करता है अथवा अपने प्रमुख क्रियाकलाप बदलता है जो कि घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन है।
36. अतः, प्राधिकारी ने एएमएनएस और जेएसडब्ल्यू दोनों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना है और इनमें से किसी को भी घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।
37. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि समर्थकों ने संबंधित प्रारूपों में सूचना दायर की है और इसे सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया था और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।
38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का स्वयं और समर्थकों सहित कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
39. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

## **ड. गोपनीयता**

### **ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

40. गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने जांच प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा दायर सभी दस्तावेजों को परिशिष्ट 2 सहित हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया है। 28 जुलाई, 2021 के ई-मेल के माध्यम से, अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर 14 जुलाई, 2021 की मौखिक सुनवाई की सूचना में उल्लिखित सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिशिष्ट 2 के अगोपनीय रुपांतर को पहले ही हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित याचिका के अगोपनीय रुपांतर के संगत भागों में शामिल किया जा चुका है।

ख. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर और अन्य सभी दस्तावेज प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और हितबद्ध पक्षकार इसे किसी भी समय डीजीटीआर द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल से प्राप्त कर सकते थे। अतः उत्तरदाता की शिकायत निराधार है।

ग. आवेदन पत्र के समर्थकों ने अपने उत्तरों के अगोपनीय रुपांतर दायर किए हैं।

घ. उत्तरदाता निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता के दावों का सहारा लिया है जिसने याचिकाकर्ताओं को अपनी टिप्पणी देने से पूरी तरह से रोक दिया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए क्षति विवरण निरपवाद रूप से या तो वास्तविक आधार पर अथवा सूचीबद्ध आधार पर होते हैं। घरेलू उद्योग और उत्तरदाता उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा क्षति संबंधी मानदंड के अगोपनीय रुपांतर की तुलना स्पष्ट रूप से यह दर्शाएगी कि उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता की सीमा कहीं अधिक है।

च. घरेलू उद्योग ने क्षति मानदंडों की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले मापदंडों के सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

छ. निर्यातक ने उत्पाद सूची, वितरण चैनल, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रवाह चार्ट, कच्ची सामग्री का नाम, भारत को निर्यात के संबंध में सूचना, कंपनी के सामानों की बिक्री, बिक्री कीमत संरचना, स्थापित क्षमता दर्शाने वाला विवरण, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सहायक कंपनियों से संबंधित सूचना, तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में सूचना आदि जैसी सूचना का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी सभी सूचनाओं को प्रकट नहीं किया है जिन्हें नियमावली के तहत प्रकट करना उनका दायित्व है। यहां तक कि जो सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, वह अगोपनीय रूपांतर में प्रकट नहीं की गई है।

ज. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार सूचना का अगोपनीय रूपांतर दायर किया है।

## ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

41. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. जैसा कि चीन जन. गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों से देखा जा सकता है, यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की परिपाटी है कि वे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा प्रकट करें। इसे एएमएनएस और जेएसडब्ल्यू द्वारा आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों के साथ उस देश के साथ दिया जाना चाहिए जहां से ऐसे आयात हुए हैं, ताकि वह एक सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान कर सके और पर्याप्त रूप से अपने हितों की रक्षा कर सके।

ख. याचिका व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करती और कई आंकड़े वास्तविक के बजाय एक प्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए गए हैं।

ग. आर्थिक और क्षति संकेतकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के अत्यधिक दावे के कारण, उत्तरदाता को घरेलू उद्योग के दावों का प्रभावी खंडन करने से रोक दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उचित प्रक्रिया अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

घ. घरेलू उद्योग ने याचिका के परिशिष्ट 2 के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित नहीं किया है। समर्थकों द्वारा दायर प्रश्नावली के अगोपनीय रूपांतर को साक्षात् नहीं किया गया है।

## ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

*गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।*

43. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि उसका प्रकटन करने से किसी प्रतिस्पर्धी को काफी प्रतिस्पर्धी लाभ होगा अथवा क्योंकि इसको प्रकट करने से सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है), अथवा जो अच्छा कारण दर्शाए जाने पर किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की जाती है, प्राधिकारी द्वारा ऐसी माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता।
44. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने परिशिष्ट 2 के साथ अगोपनीय रूपांतर तथा याचिका के समर्थकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर परिचालित किये हैं।
45. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई।

## च. विविध अनुरोध

### च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

46. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. एक उचित तुलना सुकर बनाने के लिए पीसीएन पद्धति को अपनाने हेतु आवेदन पत्र में कोई अनुरोध नहीं किया गया था। जांच शुरू करने के बाद, प्राधिकारी ने एक पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव रखा, हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त कीं और उन टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, पीसीएन ढांचे को अंतिम रूप दिया और हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए पीसीएन ढांचे के अनुसार संगत सूचना देने का निर्देश दिया। उक्त निर्देशों के अनुसरण में, घरेलू उद्योग ने संगत प्रारूपों में पीसीएन-वार सूचना दायर की।
- ख. फा. संख्या 14/44/2016-डीजीएडी द्वारा डीजीटीआर में उल्लिखित बैठक के कार्यवृत्त और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के संबंध में, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या परिचालित अनुदेश अब भी लागू हैं क्योंकि वे डीजीटीआर की वेबसाइट पर नहीं पाए जाते हैं जिनमें सभी व्यापार सूचनाएं और कार्यालय ज्ञापन शामिल होते हैं जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा देखे जाने की आवश्यकता होती है। इसे डीजीटीआर द्वारा व्यापार सूचना संख्या 02/2018 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से प्रतिस्थापित किया गया माना जाना चाहिए जो घरेलू उद्योग द्वारा याचिका के लिए प्रारूप प्रदान करता है और उल्लिखित करता है कि यह "याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली याचिका के संबंध में" निदेशालय द्वारा जारी किए गए सभी पूर्व अनुदेशों अथवा व्यापार सूचनाओं, यदि कोई है, का अधिक्रमण करेगा। फा. सं. 14/44/2016-डीजीएडी द्वारा परिचालित निम्नलिखित अनुदेशों का प्रश्न ही नहीं उठता।
- ग. जहां तक डीजीसीआईएस आंकड़ों का संबंध है, उक्त आंकड़ों में दिया गया उत्पाद विवरण पीसीएन ढांचे के अनुसार उसे समूहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगत सूचना की कमी के कारण, आयातों को संपूर्ण रूप से पीसीएन ढांचे के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सका। तथापि, सहयोगी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पीसीएन वार आयात उनके द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर उपलब्ध हैं।
- घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के लिए लाभकारी के रूप में सूचीबद्ध नीतियों में से कोई भी नीति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को रोकने में दूर-दूर तक सहायक नहीं है।
- ङ. 'स्पेशियलिटी स्टील' के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना देश के भीतर विशेष स्टील ग्रेड के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। पीएलआई प्रोत्साहन से विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह योजना जांच की अवधि के दौरान प्रचालन में नहीं थी और इसके 2022-23 से प्रचालन में आने की उम्मीद है।

च. जापान और दक्षिण कोरिया से संबद्ध सामानों के आयात पर शून्य प्रशुल्क है। संबद्ध सामानों पर अधिमान्य आयात शुल्क के कारण, घरेलू उद्योग के सामने उल्टी शुल्क ढांचे की समस्या है क्योंकि कोकिंग कोल जैसी कच्ची सामग्री का आयात 2.5% आयात शुल्क के अधीन है। भारत ने फरवरी, 2021 से स्टील पर एमएफएन आयात शुल्क को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

47. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. संदर्भ मूल्य के आधार पर पाटनरोधी शुल्क (यदि कोई है) लगाया जाना चाहिए। यह उन आयातों पर अनावश्यक दंड को रोकता है जो घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अधिक कीमत पर किए जा रहे हैं और इसलिए, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। मूल जांच में अपनाए गए संदर्भ कीमत आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि उत्पाद ग्रेड जो संदर्भ कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक पर आयात किया जाता है, पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा।
- ख. जनहित की व्यापक और पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, और भारत सरकार को पाटनरोधी उपाय नहीं लागू करने चाहिए, भले ही यह निर्धारित हो कि आयात से क्षति हुई है।
- ग. डीजीटीआर ने लेन-देन-वार आयात आंकड़े उसी रूप और तरीके से प्रदान नहीं किया है जिसमें इसे रिकॉर्ड में लिया गया था।
- घ. सभी कारकों का निर्धारण कॉइल इन एचआर और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए अलग से किया जाना चाहिए क्योंकि मूल जांच में इसके लिए पाटन और क्षति मार्जिन अलग से निर्धारित किया गया।
- ङ. वर्तमान याचिका विधिवत सिद्ध याचिका नहीं है क्योंकि यह संगत पीसीएन-वार सूचना प्रदान नहीं करती है। औसत मार्जिन गणना प्रदान करके, मूल जांच में प्रयोग की गई पद्धति को याचिका में कोई औचित्यपूर्ण कारण दिए बिना विचलन किया गया है। अतः, उक्त याचिका के आधार पर वर्तमान जांच की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए थी। परिणाम, वर्तमान जांच की शुरुआत कानून में गलत है।
- च. डीजीटीआर को न केवल जापानी स्टील मिलों बल्कि भारत में प्रयोक्ता उद्योगों और कंपनियों सहित अन्य हितधारकों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि समग्र रूप से सार्वजनिक हितों को विधिवत रूप से दर्शाया जा सके।
- छ. घरेलू उद्योग अब लाभप्रद है और भारत में बिक्री के अवसरों में वृद्धि हुई है और अंत में दृष्टिकोण भी बेहतर दिख रहा है। भारतीय इस्पात उद्योग में हाल की प्रवृत्तियों और नीतियों जैसे बीआईएस मानकों, एसआईएमएस, पीएलआई योजना, स्टील रीसाइक्लिंग नीति यह दर्शाती है कि अगर पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति बार-बार होने का कोई खतरा नहीं है।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में उपयुक्त स्थानों पर हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- (i) जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी संदर्भ मूल्य के आधार पर शुल्क की सिफारिश करेंगे, प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम पर पहुंचते समय उचित निर्णय लेंगे।
- (ii) जनहित के संबंध में, इस प्रकटन विवरण के एक अलग खंड में इसकी जांच की गई है।
- (iii) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों को लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के प्रावधान का संबंध है, प्राधिकारी ने व्यापार सूचना संख्या 07/2018 का उल्लेख किया है और इसके संदर्भ में, जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने आयात आंकड़ों की प्राप्ति के लिए अनुरोध किया है, प्राधिकारी ने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है।
- (iv) विचाराधीन उत्पाद 'अलाय और नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद' है। उक्त उत्पाद को 'कॉइल्स' और 'नॉट इन कॉइल्स' नाम से दो व्यापक श्रेणियों में रखा गया है। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से क्षति विश्लेषण किया जाए। इस संबंध में,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि 'इन-कॉइल' उत्पादों को आवश्यकता के आधार पर 'नॉट-इन कॉइल' उत्पादों में काटा और स्लिट किया जा सकता है। आवेदक समान आधार सुविधाओं का उपयोग करके 'इन-कॉइल' और 'नॉट-इन-कॉइल' उत्पाद बनाता है। अतः, 'अलॉय और नॉन-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों' के लिए एक साथ क्षति का निर्धारण करना उचित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच के दौरान एचआर 'इन कॉइल' और 'नॉट इन कॉइल' के लिए ऐसी कोई अलग क्षति जांच नहीं की गई थी और इसलिए इस तरह के क्षति विश्लेषण को निर्णायक समीक्षा के दौरान अलग करने का सवाल ही नहीं उठता। तथापि, मूल जांच के समान, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन दोनों की उचित तुलना करने के उद्देश्य से पीसीएन आधारित तुलना लागू की है जो संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक-एक करके तुलना सुनिश्चित करता है।

- (v) बीआईएस मानकों, सिम्स, पीएलआई योजना, स्टील रीसाइक्लिंग नीति की मौजूदगी के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या शुल्कों के बंद होने से घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति को जारी रहने की संभावना होगी अथवा वह बार-बार होगी जिसकी जांच केवल घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटन आयातों के प्रभाव के संदर्भ में की जानी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटन के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- (vi) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीसीएन वार सूचना के बजाय आयातों के औसत पाटन मार्जिन के परिकलनों को स्वीकार किया गया था क्योंकि सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा अलग-अलग कंपनियों के आंकड़ों के पीसीएन वार ब्यौरे उपलब्ध कराये गये हैं, अतः आधिकारिक डीजीसीआईएस आंकड़ों को पीसीएन के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि डीजीसीआईएस के आंकड़ों में दिया गया विवरण भारी संख्या में आयात लेनदेनों के लिए पीसीएन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त नहीं था।

## छ. सामान्य मूल्य, निर्यात और पाटन मार्जिन का निर्धारण

### छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

49. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य (1) कच्ची सामग्री (कोयला और लौह अयस्क) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों अर्थात् 'व्यापार मानचित्र' डाटाबेस से संबंधित संबद्ध देश में इन सामग्रियों के वैश्विक भारित औसत आयात मूल्य को लेकर निर्मित किया गया है। (2) भारत और संबंधित संबद्ध देश के बीच लागत में अंतरों के आधार पर संबद्ध देश में प्रचलित लागतों को विधिवत रूप से दर्शाने के लिए भारत में श्रम लागत को समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर अन्य विनिर्माण लागतों पर विचार किया गया है। (3) घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर एसजीए लागत और वित्त लागत पर विचार किया गया है, (4) सामान्य मूल्य निकालने के लिए 5% के लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है। 28 मार्च, 2021 को दायर याचिका के परिशिष्ट 1 ने स्पष्ट किया कि सामान्य मूल्य की गणना उपर्युक्त तरीके से की गई थी।
- (ii) याचिकाकर्ता ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकाली है। सीआईएफ निर्यात कीमत से, कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए (1) समुद्री भाड़ा (2) अंतर्देशीय भाड़ा (3) समुद्री बीमा (4) कमीशन (5) बैंक प्रभारों (6) पत्तन एवं सारसंभाल व्यय (7) गैर-वापसी योग्य वैट (चीन जन. गण. के संबंध में) के संबंध में समायोजन किये गये हैं।
- (iii) हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की कीमत की सूचना के अभाव में अथवा किसी अन्य तरीके से जिससे इन देशों के लिए कीमत निर्धारित की जा सकती है, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए तरीके से सामान्य मूल्य का निर्मित क्यों नहीं किया जा सका। सूचना के अभाव में जो याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य के विपरीत हो सकती है, उसे सही रूप से विश्वसनीय माना जाएगा। उत्तरदाता याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए समायोजनों की सत्यता का विरोध करने में सक्षम नहीं रहे हैं। अतः इसके संबंध में उठाई गई आपत्ति निराधार है।

- (iv) संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन काफी है और इस तथ्य का एक स्पष्ट संकेतक है कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है, तो संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों के पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने रहने की पूरी संभावना है।
- (v) जेएफई स्टील ने बैंक प्रभारों, पैकेज प्रभारों और कमीशन के लिए कटौती के निमित्त कटौती का दावा नहीं किया है।
- (vi) निप्पॉन स्टील ने बैंक प्रभारों, पैकेज प्रभारों के लिए कटौती का दावा नहीं किया है और स्पष्ट किया है कि क्या कोई संबंधित फर्म भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करती है।
- (vii) होंडा की जापान में घरेलू बिक्री है और सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया जाना है। इसने बैंक प्रभारों और पैकेज प्रभारों के निमित्त कटौतियों का भी दावा नहीं किया है।
- (viii) जेएफई शोजी ने बैंक और पैकेजिंग प्रभारों के निमित्त कटौतियों का दावा नहीं किया है।
- (ix) कोबे स्टील लिमिटेड ने परिशिष्ट ख में प्राधिकार को छोड़कर कोई दस्तावेज अथवा अनुरोध उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्रकार, उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।
- (x) यहां तक कि यद्यपि हिताची जोसेन कॉर्पोरेशन को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तथापि इस व्यापारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिए, उन्हें असहयोगी घोषित किया जा सकता है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

50. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने (क) कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमत, (ख) संबंधित संबद्ध देश में विद्यमान श्रम लागत को विधिवत दर्शाने के लिए समायोजन करने के बाद घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर खपत मानदंड, रूपांतरण लागत और एसजीए लागत और एक उपयुक्त लाभ के आधार संबद्ध देशों (जिनमें जापान भी शामिल है) के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है।
- ख. जांच की शुरुआत के अनुसार, प्राधिकारी ने याचिका में दिए गए सामान्य मूल्य की अपेक्षा सामान्य मूल्य निकालने के लिए भिन्न आधार पर विचार किया है। तदनुसार, यह सिद्ध है कि जांच की शुरुआत आवेदन पत्र/याचिका में साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः जांच की शुरुआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उल्लंघनमें है और कानून में गलत है।
- ग. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित को भी औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया है: ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य और रूस में संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना के संबंध में सूचना प्राप्त करने का कोई प्रयास, कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य कैसे निर्मित किया गया, जापान में उत्पादन लागत दर्शाता है, याचिकाकर्ता का अनुभव घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर, मानी गई परिवर्तन लागत, एसजीए लागत और वित्त लागत के लिए जापान में उत्पादकों के सामान्य मूल्य से कैसे तुलनीय है।
- घ. जापान से एक उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए मलेशिया एक उपयुक्त तीसरा देश कैसे है, इसका कोई रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है।
- ड. याचिका के पृष्ठ 17 पर निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजन किए गए हैं, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
- च. उचित पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सम-सम्मत उचित तुलना की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, याचिका में कथित पाटन मार्जिन का उद्देश्य, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय सूचना पर आधारित नहीं है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(2) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5(2) के तहत पाटन का साक्ष्य नहीं है।



**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

51. 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
  - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
  - (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

52. जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने उन तथ्यों को लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जिन्हें जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त माना गया था, तथापि जांच शुरू करने के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

53. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग किया है:

**कोरिया गणराज्य**

- (i) पोसको
- (ii) हुंडई स्टील कंपनी
- (iii) जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन
- (iv) ह्योसुंग टीएनसी निगम
- (v) ह्योसुंग जापान कं, लिमिटेड
- (vi) पोसको एशिया कंपनी लिमिटेड
- (vii) पोसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
- (viii) सैमसंग सी एंड टी निगम
- (ix) जीएस ग्लोबल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
- (x) हुंडई कॉर्पोरेशन
- (xi) एसके नेटवर्क्स कं, लिमिटेड

जापान

- (i) निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन
- (ii) जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन
- (iii) मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड
- (iv) जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन
- (v) मित्सुई एंड कं, लिमिटेड
- (vi) होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- (vii) होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- (viii) कनेमात्सु निगम
- (ix) मारुबेनी-इतोचु स्टील इंक।
- (x) मेटल वन कॉर्पोरेशन
- (xi) निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
- (xii) निसान ट्रेडिंग कं, लि.
- (xiii) ओहमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xiv) सातो शोजी कॉर्पोरेशन
- (xv) सुमितोमो कॉर्पोरेशन
- (xvi) सुमितोमो कॉर्पोरेशन ग्लोबल मेटल्स कं, लिमिटेड
- (xvii) टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन
- (xviii) टेट्सुशो कायाबा कॉर्पोरेशन

इंडोनेशिया

- (i) पीटी क्राकटाऊ-पोसको
- (ii) ह्योसुंग टीएनसी निगम
- (iii) जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन
- (iv) ह्योसुंग जापान कं, लिमिटेड, जापान
- (v) पोसको एशिया कंपनी लिमिटेड
- (vi) पोसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
- (vii) सैमसंग सी एंड टी निगम

54. रूस, ब्राजील और चीन से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
55. पीसीएन-से-पीसीएन तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) तैयार की। प्राधिकारी ने पहले पीसीएन स्तर पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना करके प्रत्येक पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया। इसके बाद, समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी या बिल्कुल समान पीसीएन की कोई लाभदायक घरेलू बिक्री नहीं थी, वहां सामान्य मूल्य तो उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उचित अभिवृद्धि के आधार पर निर्मित किया गया था, या काफी मिलती-जुलती पीसीएन की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्मित किया गया था।

56. प्राधिकारी ने उन मामलों में निर्यात कीमत में उचित समायोजन किया है जहां यह नोट किया गया था कि भारत में निर्यात श्रृंखला में शामिल संबद्ध या असंबद्ध व्यापारी या भारत में संबद्ध आयातक को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर हानियां हो रही थीं।
57. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

#### छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

##### चीन जन. गण

##### चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दावे

58. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

59. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने संगत प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
60. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित अन्य विधियों के संबंध में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उपयुक्त आधार" पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने (क) कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, (ख) घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर खपत मानदंडों और परिवर्तन लागतों, एसजीए और वित्तीय लागतों तथा (ग) उपयुक्त लाभ के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

## छ.5 निर्यात मूल्य का निर्धारण

61. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः चीन जन. गण. से निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि पीसीएन वार निर्यात कीमत निकालने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मामले में पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एकल भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सारसंभाल प्रभार, कमीशन, बैंक प्रभारों और गैर-वापसी योग्य वैट के निमित्त समायोजन किये गये हैं। कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत तदनुसार निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

## जापान

### (i) जेएफई स्टील कारपोरेशन ("जेएफई")

#### सामान्य मूल्य

62. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध सामानों के एक उत्पादक और निर्यातक जेएफई ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री। अतः प्राधिकारी ने कुल घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
63. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया की। सभी निर्धारण जांच में पूर्व में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पीसीएन के आधार पर किए गए हैं।
64. सभी लाभप्रद लेन-देन 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है, और ऐसे मामलों में, जहां लाभप्रद लेनदेन 80% से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी या कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी या किसी विशेष पीसीएन के लिए पर्याप्तता परीक्षण पूरा नहीं किया गया था, वहां सामान्य मूल्य या तो उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि और लाभ के लिए अथवा निकट रूप से मिलते जुलते पीसीएन के घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्मित किया गया था।

65. जेएफई ने अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सुदूर परस्पर जांच चेक के माध्यम से सत्यापनों के बाद समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार, जेएफई के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **निर्यात कीमत**

66. जेएफई ने अपनी संबद्ध/असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, ओहमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन, जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन, सातो शोजी कॉर्पोरेशन, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मेटल वन कॉर्पोरेशन, और मारुबेनी इटोचु स्टील इंक सहित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया जिन्होंने जेएफई द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों का भारत को निर्यात किया। इसके अतिरिक्त, जेएफई ने अन्य व्यापारियों (जो जेएफई के उपरोक्त व्यापारियों के व्यापारी हैं) के माध्यम से भी कुछ मात्रा का निर्यात किया है, जिन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
67. तथापि, प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किया गया निर्यात भारत को किए गए कुल निर्यातों के संदर्भ में काफी नहीं हैं।
68. उत्पादक मैसर्स जेएफई की निर्यात कीमत निकालने के लिए, प्राधिकारी ने जेएफई और उन सहयोगी व्यापारियों की श्रृंखला के लिए वास्तविक निर्यात मूल्य पर विचार किया है, जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया है और निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में उत्तर प्रस्तुत किए हैं, और जेएफई के उन असहयोगी व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई, जिन्होंने निर्धारित स्वरूप और तरीके से सूचना दायर नहीं की थी। तदनुसार, जेएफई के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में सभी निर्यात चैनलों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है।
69. जेएफई ने अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, जेएफई के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण एचआर कॉइल्स और एचआर नॉट इन के लिए कारखानागत स्तर पर किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **निप्पाँन स्टील कारपोरेशन ("एनएससी")**

#### **सामान्य मूल्य**

70. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, एनएससी ने घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों को संबद्ध और असंबद्ध कंपनियों को बिक्री की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक संबद्ध कंपनी अर्थात् निप्पाँन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अपना उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी संबंधित पक्षकारों को की गई घरेलू बिक्री कुल घरेलू बिक्री की दृष्टि से काफी नहीं है। अतः प्राधिकारी ने कुल घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
71. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। सभी निर्धारण जांच में पूर्व में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पीसीएन के आधार पर किए गए हैं।
72. सभी लाभप्रद लेन-देन 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है, और ऐसे मामलों में, जहां लाभप्रद लेनदेन 80% से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी या कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी या किसी विशेष पीसीएन के लिए पर्याप्तता परीक्षण पूरा नहीं किया गया था, वहां सामान्य मूल्य या तो उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि और लाभ के लिए अथवा निकट रूप से मिलते जुलते पीसीएन के घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्मित किया गया था।
73. एनएससी ने ब्रूट, वारंटी, साख पत्र, अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार, एचआर

काँइल और एचआर नॉट इन काँइल के लिए सामान्य मूल्य कारखाना स्तर पर निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **निर्यात कीमत**

74. एनएससी ने अपनी संबद्ध/असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कानेमात्सु कॉर्पोरेशन, मेटल वन कॉर्पोरेशन, हुनवा कं, लिमिटेड, मारुबेनी-इटोचु स्टील इंक, टोयोटा त्सुथो कॉर्पोरेशन, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सुमितोमो कॉर्पोरेशन ग्लोबल मेटल्स कं, लिमिटेड और मित्सुई एंड कं. लिमिटेड सहित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया जिन्होंने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, एनएससी ने अन्य व्यापारियों (जो एनएससी के उपर्युक्त व्यापारियों के व्यापारी हैं) के माध्यम से भी कुछ मात्रा का निर्यात किया है, जिन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
75. तथापि, प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किये गये निर्यात भारत को किए गए कुल निर्यात के संदर्भ में काफी नहीं है। अपनी असंबद्ध/संबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से एनएसएसएमसी की निर्यात बिक्री एफओबी आधार पर है। अपनी असंबद्ध/संबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से एनएसएसएमसी की निर्यात बिक्री एफओबी आधार पर है।
76. अपनी असंबद्ध/संबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से एनएससी की निर्यात बिक्री एफओबी आधार पर है। एनएससी ने अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, एनएससी के लिए भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण एचआर काँइल और एचआर नॉट इन काँइल के लिए कारखानागत स्तर पर किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **जापान से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मैसर्स कोबे स्टील लिमिटेड ने मूल जांच में भाग लिया था और प्राधिकारी ने उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उक्त कंपनी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया था। तथापि, इस निर्णायक समीक्षा में, कोबे स्टील लिमिटेड ने सहयोग नहीं किया और तदनुसार, प्राधिकारी ने उपर्युक्त कंपनी के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया।
78. असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
79. निर्यात कीमत के संबंध में, उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सारसंभाल प्रभारों, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किये गये हैं। सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का उल्लेख निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

### **कोरिया**

#### **पोसको, कोरिया गणराज्य**

#### **सामान्य मूल्य**

80. पोसको कोरिया गणराज्य में एक सूचीबद्ध कंपनी (संयुक्त स्टॉक कारपोरेशन) है। जांच की अवधि के दौरान, पोसको ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सामान की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया की। यदि विशेष पीसीएन के लिए लाभप्रद लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है और ऐसे मामलों में जहां विशेष पीसीएन के लिए लाभप्रद लेनदेन 80% से कम है, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी या कोई लाभप्रद

घरेलू बिक्री नहीं थी या किसी विशेष पीसीएन के लिए पर्याप्तता परीक्षण पूरा नहीं किया गया था, वहां सामान्य मूल्य या तो उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभ के लिए के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ उत्पादन लागत के आधार पर अथवा निकट रूप से मिलते जुलते पीसीएन की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्मित किया गया था।

81. पोसको ने अंतर्देशीय भाड़ा, भंडारण व्यय, ऋण लागत और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पोसको के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### **पोसको, कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात मूल्य**

82. पोसको ने अपनी संबद्ध/असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों जैसे पोसको इंटरनेशनल कॉर्प, कोरिया गणराज्य, पोसको एशिया कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, जीएस ग्लोबल कॉर्प, कोरिया गणराज्य, जीएस ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, सैमसंग सी एंड टी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, ह्योसुंग जापान कं. लिमिटेड, जापान सहित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है जिन्होंने पोसको द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को किया है। पोसको ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चैनल का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।
83. पोसको ने जांच की अवधि के दौरान पोसको इंडिया पीसी, पोसको आईपीपीसी और पोसको महाराष्ट्र जैसे भारत में पोसको के संबंधित प्रसंस्करणकर्ताओं/आयातकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्यात भी किया है। इन सभी संबद्ध पक्षकारों ने भी आयातकों/अंतिम प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
84. इसके अतिरिक्त, पोसको ने उन अन्य व्यापारियों के माध्यम से भी कुछ मात्रा का निर्यात किया है जिन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात भारत को किए गए कुल निर्यात के संदर्भ में बहुत कम हैं। उत्पादक मैसर्स पोसको के निर्यात मूल्य की गणना करने के लिए, प्राधिकारी ने पोसको और उन सहयोगी व्यापारियों वाली श्रृंखला के लिए वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया है और निर्धारित स्वरूप और तरीके में उत्तर प्रस्तुत किए हैं, और पोसको के उन असहयोगी व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है जिन्होंने निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना दायर नहीं की थी। तदनुसार, पोसको के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण भारत के सभी निर्यात चैनलों के भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है।
85. भारत में उपर्युक्त पोसको सहायक कंपनियों द्वारा दायर किए गए उत्तर से यह नोट किया जाता है कि, उनमें से कुछ को अपनी मूल कंपनी अर्थात् पोसको से उपर्युक्त भिन्न व्यापारिक चैनलों के माध्यम से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानियां हुई हैं। चूंकि संबद्ध सामानों की उनकी बिक्री कीमत उनकी क्रय कीमत से कम है, अतः पोसको की पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजन की अनुमति दी गई है। पोसको के लिए भारित औसत निर्यात कीमत एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

#### **मैसर्स हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य, और उसके प्रतिभागी संबद्ध और असंबद्ध आयातक/अंतिम प्रयोक्ता**

##### **सामान्य मूल्य**

86. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने संबंधित और असंबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभ प्राप्त करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर विचार किया जा रहा है और यदि लाभ प्राप्त करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण

के लिए केवल लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्रियों को ध्यान में रखा जा रहा है। हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य के संबंध में, चूंकि ओसीटी परीक्षण में लाभप्रद बिक्री 80% से कम है, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया है। जहां कहीं भी कोई घरेलू बिक्रियां नहीं थी या लाभ प्राप्त करने योग्य घरेलू बिक्रियां नहीं थी या किसी विशिष्ट पीसीएन के लिए पर्याप्तता परीक्षण को पूरा नहीं किया गया था, वहां सामान्य मूल्य को या तो प्रशासनिक, बिक्री या सामान्य लागतों, उचित जोड़ के आधार पर उत्पादन की लागत के आधार पर या और लाभों के लिए पीसीएन से अत्यधिक समानता रखने वाली घरेलू बिक्री कीमत के साथ - साथ निर्मित किया गया था।

87. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, समुद्री माल भाड़ा और क्रेडिट व्ययों के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **निर्यात मूल्य**

88. हुंडई स्टील कंपनी, जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध सामानों की उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, हुंडई स्टील कंपनी ने तीन असंबद्ध/संबद्ध व्यापारियों अर्थात् जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, हुंडई कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, सैमसंग सी एंड टी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, और एसके नेटवर्क्स कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सामानों का निर्यात किया। प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि उसकी संबद्ध कंपनी को निर्यात बिक्री कीमत और उसी पीसीएन/ग्रेड के लिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात बिक्री कीमत के बीच काफी अंतर था। हुंडई स्टील, कोरिया गणराज्य, एक ही पीसीएन/ग्रेड के लिए संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों के बीच निर्यात बिक्री कीमत ऐसे काफी अंतर के लिए कोई वैध कारण प्रदान करने में अक्षम था। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए केवल असंबद्ध पक्षकारों को निर्यात बिक्री पर विचार किया है। हुंडई स्टील कंपनी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए कारखानागत स्तर पर किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।
90. असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
91. निर्यात कीमत के संबंध में, उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सारसंभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किये गये हैं। सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

### **इंडोनेशिया**

#### **पीटी क्राकाटाऊ पोसको, इंडोनेशिया**

#### **सामान्य मूल्य**

92. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स पीटी क्राकाटाऊ पोसको इंडोनेशिया में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। जांच की अवधि के दौरान, पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को \*\*\* अमे. डॉ. मूल्य के बीजक वाले \*\*\* मी. टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया की। यदि विशेष पीसीएन के लिए लाभप्रद लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य



मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है और ऐसे मामलों में जहां विशेष पीसीएन के लिए लाभप्रद लेनदेन 80% से कम है, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी या कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी या किसी विशेष पीसीएन के लिए पर्याप्तता परीक्षण पूरा नहीं किया गया था, वहां सामान्य मूल्य या तो उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभ के लिए के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ उत्पादन लागत के आधार पर अथवा निकट रूप से मिलते जुलते पीसीएन की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्मित किया गया था।

93. पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीटी क्राकाटाऊ पोसको के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

### **निर्यात कीमत**

94. पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने अपनी संबद्ध/असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों अर्थात् पोसको इंटरनेशनल कॉर्प, कोरिया गणराज्य, पोसको एशिया कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, जीएस ग्लोबल कॉर्प, कोरिया गणराज्य, ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य, ह्योसुंग जापान कं. लिमिटेड, जापान सहित प्रश्नावली उत्तर दायर किया है जिन्होंने पीटी क्राकाटाऊ पोसको द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों का भारत को निर्यात किया है। पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चैनल का प्रयोग करते हुए \*\*\* मी. टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।
95. पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने जांच की अवधि के दौरान भारत में पोसको के संबंधित आयातकों अर्थात् पोसको इंडिया पीसी और पोसको आईपीपीसी को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्यात भी किये हैं। इन सभी संबद्ध पक्षकारों ने भी आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
96. इसके अतिरिक्त, पीटी क्राकाटाऊ पोसको ने अन्य व्यापारियों के माध्यम से भी कुछ मात्रा का निर्यात किया है जिन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपनी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात भारत को किए गए कुल निर्यात के संदर्भ में बहुत कम हैं। उत्पादक की निर्यात कीमत निकालने के लिए, प्राधिकारी ने पीटी क्राकाटाऊ पोसको और उन सहयोगी व्यापारियों की श्रृंखला के लिए वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है, जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया है और निर्धारित स्वरूप और तरीके में उत्तर प्रस्तुत किए हैं, तथा पीटी क्राकाटाऊ पोसको के उन असहयोगी व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है जिन्होंने निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना दायर नहीं की थी। तदनुसार, पीटी क्राकाटाऊ पोसको के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण भारत को सभी निर्यात चैनलों की भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है।
97. भारत में पोसको की उपर्युक्त सहायक कंपनियों द्वारा दायर किए गए उत्तर से यह नोट किया जाता है कि, उनमें से एक को उपर्युक्तानुसार विभिन्न व्यापारिक चैनलों के माध्यम से पीटी क्राकाटाऊ पोसको से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानियां हुई हैं। चूंकि उनकी संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उनकी क्रय कीमत से कम है, इसलिए पीटी क्राकाटाऊ पोसको की पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। पीटी क्राकाटाऊ पोसको के लिए भारित औसत निर्यात कीमत एचआर नॉट इन कॉइल के लिए कारखाना स्तर पर निर्धारित की गई है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

### **इंडोनेशिया से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

99. असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
100. निर्यात कीमत के संबंध में, उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सारसंभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किये गये हैं। इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

### **ब्राज़ील**

#### **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन**

101. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान ब्राज़ील से एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल को कोई आयात नहीं थे। इसलिए, ब्राज़ील के लिए कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सका।

### **रूस**

#### **सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन**

102. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान रूस से एचआर कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के कोई आयात नहीं थे। इसलिए, रूस के लिए कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सका।

### **छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण**

103. संबद्ध देशों, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया था, के लिए संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त संबद्ध देशों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। उपर्युक्त निर्धारित पाटन मार्जिन का उल्लेख निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

क्रम सं.	देश	उत्पादक/ निर्यातक	उत्पाद	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./ मी. टन)	एनईपी (अमे. डॉ./ मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	रेंज %
1	चीन जन. गण.	सभी उत्पादक/ निर्यातक	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	30-40
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	20-30
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	25-35
2	इंडोनेशिया	पीटी क्राकाटऊ पोसको, इंडोनेशिया	एचआर इन कॉइल	***	***	उ. न.	उ. न.	उ. न.
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	10-20
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	10-20
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	उ. न.	उ. न.	उ. न.
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	40-50
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	40-50
3	जापान	जेएफई स्टील कारपोरेशन	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	0-10
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	10-20
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	10-20
		निप्पॉन	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	20-30

		स्टील कारपोरेशन	एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	20-30
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	20-30
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	40-50
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	10-20
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	40-50
4	कोरिया गणराज्य	पोसको	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	0-10
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	0-10
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	0-10
		हुंडई स्टील कंपनी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	0-10
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	30-40
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	10-20
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	35-40
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	40-50
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	40-50

## ज. क्षति का मूल्यांकन एवं कारणात्मक संपर्क

### ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

104. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात स्थिर रहा है और अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक कोई भी गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण मांग में कमी के कारण है। स्थिति में सुधार होने पर यह गिरावट फिर से शुरू हो जाएगी।
- बिक्री पर वास्तविक और संभावित प्रभाव - संबद्ध देशों से पाटित आयातों से बिक्री में अल्पकालिक वृद्धि कम हो गई जो लगाए जा रहे पाटनरोधी शुल्क के कारण उत्पन्न हुई।
- घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि (ए) के दौरान काफी कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का सामना किया है। मौजूदा शुल्क हटाए जाने से ही उपर्युक्त स्थिति में वृद्धि होगी।
- संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों पर लगाए गए संदर्भ मूल्य आधारित पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण नकारात्मक कीमत कटौती नकारात्मक है। किसी भी दशा में, संपूर्ण जांच की अवधि को शामिल करने वाली घरेलू बिक्री कीमत के साथ भारित औसत आयात कीमत की तुलना (क) आयातों और घरेलू उद्योग दोनों की कीमतों में महत्वपूर्ण मासिक अंतर को देखते हुए वास्तविक कीमत कटौती करती है; और (ख) उत्पाद-मिश्रण में महत्वपूर्ण भिन्नता अर्थात् विचाराधीन उत्पाद में कई प्रशुल्क शीर्षकों के तहत कई उत्पाद किस्मों होती हैं और कीमतें उत्पाद किस्मों के अनुसार भिन्न होती हैं तथा विभिन्न किस्मों की मात्रा के संदर्भ में आयात और घरेलू बिक्री की संरचना तुलना के लिए प्रयुक्त भारित औसत कीमतों को प्रभावित करती है। संबद्ध देशों के निर्यातकों को चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमीनियम और ज़िंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के मामले में प्राधिकारी द्वारा नोट किए गए अनुसार अधिक बीजक बनाने में संलग्न होने के लिए जाना जाता है।
- प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान गिरावट को छोड़कर संबद्ध सामानों की मांग स्थिर बनी हुई है जो कि कोविड-19 महामारी के कारण हो सकती है। जांच की अवधि के दौरान अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।
- बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग - आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच, क्षमता उपयोग में 26% तक वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्रमशः 7% और 14% तक कमी आई। क्षमता उपयोग में भी काफी कमी आई है। प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान, लाभप्रदता, नकद

लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट देखी गई। घरेलू उद्योग में प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखी गई। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के लिए मालसूची स्तर जांच की अवधि में बढ़े हैं और काफी हैं। पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से और वृद्धि के लिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- (vii) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और निकट भविष्य में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना पाटित आयातों के कारण है।
- (viii) घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से किसी भी तरह से इसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि क्षति सूचना को अलग कर दिया गया है। घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बनने के लिए न तो प्रौद्योगिकी अथवा न ही उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है। ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। क्षति का एकमात्र कारण संबद्ध देशों से पाटित आयात हैं। विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हुई है।

## ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

105. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जापान से आयातों और घरेलू उद्योग के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की संभावना न्यूनतम है क्योंकि घरेलू उद्योग जापानी मिलों द्वारा बेचे जाने वाले अत्यधिक विशिष्ट ग्रेड से मेल नहीं खा सकता।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (ए) में 56 सूचकांकों तक काफी कमी आई है।
- ग. याचिकाकर्ता मांग में कमी और संबद्ध देशों से पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी के कारण मात्रा में गिरावट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
- घ. संबद्ध देशों से कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के अनुरूप है।
- ङ. जांच की अवधि में सभी संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। पूरे 18 महीनों के भारत औसत के उपयोग का विरोध करने के लिए याचिकाकर्ताओं के तर्क को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि:
  - (i) जापानी मिलों के संदर्भ कीमत और पहुंच कीमत के बीच काफी अंतर है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कीमत वृद्धि वाणिज्यिक विचारों पर आधारित है और संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के कारण कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाई गई है।
  - (ii) आयात कीमतों में मासिक मूल्य भिन्नता विरोध का आधार नहीं हो सकती क्योंकि संबद्ध सामानों में कई उत्पाद किस्में होती हैं जिनकी कीमतों में काफी भिन्नता होती है। मासिक उत्पाद मिश्रण भिन्न हो सकते हैं और फलस्वरूप कीमत भी हर महीने भिन्न हो सकती है।
  - (iii) अधिक बीजक का मुद्दा, यदि कोई हो, वह है जिसका उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों (जो उपयुक्त मंच है) द्वारा निपटाया जाता है, न कि डीजीटीआर द्वारा और वैसे भी समर्थक साक्ष्य का अभाव है।
- च. कोविड-19 महामारी के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संस्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री मूल्य, बिक्री प्राप्ति, मालसूची और पीबीआईटी एवं नकद लाभ में सुधार हुआ है। इसलिए, महामारी के लिए समायोजन का अर्थ यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग काफी बेहतर निष्पादन कर रहा होगा।
- छ. घरेलू उद्योग विशेष रूप से सेल और जेएसडब्ल्यू ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सकारात्मक निष्पादन को स्वीकार किया है। घरेलू उद्योग को क्षति न है, क्योंकि सेल की वार्षिक रिपोर्ट बेहतर ईबीआईटीडीए मार्जिन दर्शाती है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी ईबीआईटीडीए मार्जिन में सुधार की रिपोर्ट दी है और वित्त वर्ष 2019-20 में मामूली गिरावट को बढ़ाए गए मानसून, मोटर वाहन उद्योग में मंदी और कोविड -19 महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

- ज. तथाकथित पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कई कारक हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है:
- (i) घरेलू उद्योग और इस्पात उद्योग पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव/प्रभाव को घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों के साथ-साथ सार्वजनिक पटल पर भी माना गया है।
  - (ii) घरेलू उद्योग का निष्पादन मांग में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ था, जो विभिन्न अन्य कारकों जैसे कि आम चुनावों के कारण कम सार्वजनिक निवेश खर्च के कारण कमजोर क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्धता की कमी और ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मंदी आदि के कारण प्रभावित हुआ था।
  - (iii) भारत में घरेलू उत्पादक अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं (जो भारत में मांग से अधिक है)।
  - (iv) सेल ने घरेलू उद्योग के अन्य घटकों की तुलना में कर्मचारी लाभ व्यय की पर्याप्त राशि बहन की है।
- झ. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 24 सूचकांक तक गिरावट आई है।
- ञ. यह दावा करना कि याचिकाकर्ता की बिक्री में वृद्धि अल्पकालिक थी और पाटित आयातों के कारण घटी थी, गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता के अपने आंकड़े घरेलू बिक्री और मांग को समान स्तर पर रहने का संकेत देते हैं। घरेलू बिक्री में गिरावट को कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- ट. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी और घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत आधार वर्ष से बढ़ी और आयातों में आधार वर्ष से गिरावट आई। अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ घरेलू उद्योग का पहले ही जांच की अवधि (ए) के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में बाजार हिस्से का 95% हिस्सा है।
- ठ. घरेलू उद्योग को कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग एचआर इन कॉइल के लिए बिक्री मूल्य में 19% तक वृद्धि करने में सक्षम रहा है जबकि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (ए) के दौरान लागत में 15% तक वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान एचआर इन कॉइल के लिए पहुंच मूल्य में 37% तक वृद्धि हुई।
- ड. जबकि एचआर इन कॉइल के लिए घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री कीमत में 23 सूचकांक तक गिरावट आई और बिक्री लागत में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (ए) के दौरान 15 सूचकांक तक गिरावट आई, उसी समय, पहुंच मूल्य में 13 सूचकांक तक गिरावट आई।
- ढ. घरेलू उद्योग एचआर नॉट इन कॉइल के लिए अपनी बिक्री कीमत में 23% तक वृद्धि करने में सक्षम रहा है जबकि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (ए) के दौरान लागत में 16% तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, एचआर नॉट इन कॉइल की घरेलू बिक्री कीमत में बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में आधार वर्ष से जांच की अवधि (ए) में अधिक वृद्धि देखी गई।
- ण. बाजार रिपोर्ट दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान स्टील की कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी अंतर रहा है जिससे बिक्री कीमत प्रभावित हुई है।
- त. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। इसके अतिरिक्त, याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान अपने नकद लाभ को बढ़ाने में भी सक्षम रहा है।
- थ. आधार वर्ष से जांच की अवधि (ए) के दौरान घरेलू उद्योग के समग्र लाभ में 7% तक वृद्धि हुई है, और पूरी जांच अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य लाभप्रदता संकेतक, जैसे पीबीआईटी और नकद लाभ में भी जांच की अवधि के दौरान 7% और 53% तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का आरओसीई 3 वर्षों की अवधि अर्थात् आधार वर्ष से 2018-19 तक 116 प्रतिशत तक की समग्र वृद्धि दर्शाता है और आधार वर्ष से जांच की अवधि (ए) के दौरान 3% तक समग्र वृद्धि दर्शाता है।

**ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

106. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
107. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
108. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान क्षति हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क की समामि से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने की संभावना है। इसी प्रकार, यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क की समामि से घरेलू उद्योग को क्षति बार-बार होने की संभावना है।
109. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए आगे कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन या खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से भारी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार में विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
110. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि नियोजित पूंजी पर 22% आय स्वीकार्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में की गई सभी जांचों में प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी है।
111. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है जिसे वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण डेस्क सत्यापन/सुदूर परस्पर जांच के बाद सत्यापित और स्वीकार किया गया है।
112. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि जापान से आयातों और घरेलू उद्योग के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की संभावना न्यूनतम है क्योंकि घरेलू उद्योग जापानी मिलों द्वारा बेचे गए अत्यधिक विशिष्ट ग्रेडों से मेल नहीं खा सकता है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों निर्यातित पीसीएन और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीसीएन की जांच की है। सूचना की विस्तृत जांच से, प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग ने या तो सटीक मिलान वाले पीसीएन का निर्माण किया है या प्रत्येक पीसीएन के लिए निकट से मेल खाते पीसीएन का निर्माण किया है जिसके लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचना दी गई है।
113. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी को जांच की अवधि के पूरे अठारह महीनों के लिए भारित औसत कटौती मार्जिन का संचालन करना चाहिए जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाई गई मासिक कटौती का विरोध किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने पूरे 18 महीने लंबी जांच की अवधि के लिए भारित औसत आधार पर और जांच की अवधि से पूर्व के वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण किया है।
114. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सेल और जेएसडब्ल्यू ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सकारात्मक निष्पादन और बेहतर ईबीआईटीडीए मार्जिन को स्वीकार किया है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक बहु-

उत्पाद कंपनियां हैं जो संबद्ध सामानों के अलावा अन्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की घरेलू समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की है। इसलिए, कंपनियों का समग्र निष्पादन जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है, यह नहीं दर्शाता है कि क्या उसे समान वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में अपनी क्षमता में वास्तविक क्षति हो रही है।

115. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि तथाकथित पाटित आयातों को छोड़कर ऐसे विभिन्न कारक हैं जिनसे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है, यथा कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव/प्रभाव तथा परिणामस्वरूप मांग में गिरावट जिसे घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी जांच में इस बात की जांच की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति का कारण हैं और यह केवल एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों के बाद के पैराओं में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है।
116. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि भारत में घरेलू क्षमता भारत में मांग से अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता (घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की) पूरी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने के बावजूद, आयातों की मात्रा काफी रही है।
117. जहां तक कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाजार रिपोर्टों के संदर्भ का संबंध है, जो यह दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान स्टील की कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी अंतर आया है, जिसने बिक्री मूल्य को प्रभावित किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के अठारह महीनों के लिए बिक्री की औसत लागत की तुलना उसी अवधि के लिए औसत निवल बिक्री वसूली से की गई है और इसलिए, ऐसी कच्ची सामग्री की कीमतों में किसी अंतर का भी औसत निकाला जाएगा।
118. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कोविड-19 वैश्विक मैट्रिक्स को प्रभावित कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि वह भारत में उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बना सकता।
119. क्षति विश्लेषण के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के अन्य सभी अनुरोधों को निम्नलिखित पैराग्राफों में हल किया गया है।

### ज.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

120. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की कैप्टिव खपत और घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में ध्यान में रखा है।

विवरण	मूल्य	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल, 19 से सितं., 20)	जांच की अवधि (ए)
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,779,816	2,993,215	2,600,132	3,184,753	2,123,169
	सूचीबद्ध	100	108	94	115	76
अन्य देशों से आयात	मी. टन	428,750	218,164	381,755	242,129	161,419
	सूचीबद्ध	100	51	89	56	38
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. टन	15,225,634	16,699,221	17,745,040	22,849,840	15,233,227
	सूचीबद्ध	100	110	117	150	100
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	107	156	104
अन्य घरेलू	मी. टन	***	***	***	***	***

उत्पादकों की घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	100	133	119	152	101
अन्य भारतीय उत्पादकों की कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	109	158	105
मांग (कैप्टिव खपत सहित)	मी. टन	41,906,000	49,011,000	47,278,000	62,548,000	41,698,667
	सूचीबद्ध	100	117	113	149	100
मांग (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	मी. टन	29,999,223	35,280,695	34,476,098	43,826,600	29,217,734
	सूचीबद्ध	100	118	115	146	97
कुल घरेलू उत्पादन	मी. टन	41,825,000	49,237,000	50,349,000	71,571,000	47,714,000
खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात (कैप्टिव सहित)	%	7%	6%	5%	5%	5%
कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	7%	6%	5%	4%	4%
खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात (कैप्टिव को छोड़कर)	%	9%	8%	8%	7%	7%

121. प्राधिकारी यह पाते हैं कि 2016-17 में मांग 41.9 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2017-18 के दौरान 49.0 मिलियन मीट्रिक टन हो गई। यह 2018-19 के दौरान 47.3 मिलियन मीट्रिक टन और जांच की अवधि (ए) के दौरान 41.7 मिलियन मीट्रिक टन तक कम हो गई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान मांग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा

122. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (ए)
संबद्ध देश	मी. टन	2,779,816	2,993,215	2,600,132	3,184,754	2,123,169
	सूचीबद्ध	100	108	94	115	76
ब्राजील		191	-	-		-



चीन जन. गण.		850,785	705,576	420,396	669,411	446,274
इंडोनेशिया		38,464	92,693	98,657	167,633	111,755
जापान		659,786	595,062	441,931	431,765	287,844
कोरिया गणराज्य		1,086,611	1,541,231	1,605,592	1,915,943	1,277,296
रूस		143,980	58,654	33,555		-
अन्य देश	मी. टन	<b>428,750</b>	<b>218,164</b>	<b>381,755</b>	<b>242,129</b>	<b>161,419</b>
	सूचीबद्ध	100	51	89	56	38
कुल आयात	मी. टन	<b>3,208,566</b>	<b>3,211,379</b>	<b>2,981,886</b>	<b>3,426,883</b>	<b>2,284,588</b>
	सूचीबद्ध	100	100	93	107	71
कुल घरेलू उत्पादन	मी. टन	<b>41,825,000</b>	<b>49,237,000</b>	<b>50,349,000</b>	<b>71,571,000</b>	<b>47,714,000</b>
कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	87%	93%	87%	93%	93%
	सूचीबद्ध	100	108	101	107	107
कुल आयातों के संबंध में अन्य देशों से आयात	%	13%	7%	13%	7%	7%
	सूचीबद्ध	100	51	96	53	53
कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	7%	6%	5%	4%	4%
खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात (कैप्टिव सहित)	%	7%	6%	5%	5%	5%
खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात (कैप्टिव को छोड़कर)	%	9%	8%	8%	7%	7%

123. प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से आयात 2.1 मिलियन मी. टन से 3.0 मिलियन मी. टन की में अलग-अलग थे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 2016-17 के बाद ब्राजील और जांच की अवधि के दौरान रूस से कोई आयात नहीं हुआ था।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के कुल आयात में काफी हिस्सेदारी रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

125. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।

संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, क्षति रहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

#### क. कीमत कटौती

126. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों की कीमत से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कटौती प्रभाव निम्नानुसार निकलता है-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल, 19 से सितं., 20)	जांच की अवधि (ए)
पहुँच मूल्य	आईएनआर/मी. टन	32,603	39,224	48,661	45,497	45,497
	सूचीबद्ध	100	120	149	140	140
घरेलू बिक्री कीमतें	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	142	120	120
कीमत कटौती	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***
	% रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

127. यह दावा किया गया है कि समग्र रूप से संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। यह नोट किया जाता है कि संदर्भ कीमत के आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क ने आयातों की कीमतों को कम कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है।

#### ख. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

128. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	140	119
बिक्रियों की लागत	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	129	119
पहुँच मूल्य	आईएनआर/मी. टन	32,603	39,224	48,661	45,497
	सूचीबद्ध	100	120	149	140
कीमत ह्रास	आईएनआर/मी. टन		***	***	***
	सूचीबद्ध		***	***	***

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों में 2018-19 तक वृद्धि हुई जब आयात की कीमतें भी बढ़ रही थीं। इसके बाद, जब जांच की अवधि के दौरान आयातों की कीमतों में गिरावट आई, तो घरेलू उद्योग की कीमतों में भी गिरावट आई।
130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के कुछ संबंधित आयातकों ने पीयूसी को प्रयोक्ताओं को उस कीमत से कम पर बेचा है जिस पर उनका आयात किया गया था। कुछ उत्पादकों के संबंध में यह भी पाया गया कि उनकी संबंधित संस्थाओं और स्वतंत्र खरीदारों को निर्यात कीमत के बीच काफी अंतर था।
131. प्राधिकारी नोट करते हैं तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी जांच की अवधि के दौरान उसकी बिक्री लागत में कमी से अधिक थी, जो यह दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसकी कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास दोनों हुआ था।

### ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

132. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।
133. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

#### i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

134. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (ए)
संस्थापित क्षमता	मी. टन	28,540,000	28,638,630	29,540,000	44,310,000	29,540,000
	सूचीबद्ध	100	100	104	155	104
उत्पादन	मी. टन	24,311,195	25,643,998	26,791,249	37,322,672	24,881,782
	सूचीबद्ध	100	105	110	154	102
क्षमता उपयोग	%	85%	90%	91%	84%	84%
	सूचीबद्ध	100	106	107	99	99
घरेलू बिक्री	मी. टन	15,225,634	16,699,221	17,745,040	22,849,840	15,233,227
	सूचीबद्ध	100	110	117	150	100

135. प्राधिकारी पाते हैं कि –

- आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 2017-18 के दौरान और फिर 2018-19 के दौरान बढ़ी। बढ़ी हुई क्षमता के साथ भी, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्षमता उपयोग का प्रतिशत बढ़ा। तथापि, क्षमता उपयोग जांच की अवधि (ए) के दौरान 2016-17 में मौजूद स्तर से कम हो गया।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी 2018-19 तक इसी अनुपात में वृद्धि हुई। तथापि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री उसी स्तर तक कम हो गई जो आधार वर्ष में थी।

- (iii) जांच की अवधि के दौरान देखी गई मांग में कमी के परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग और बिक्री में कमी आई है।

### I. मांग में बाजार हिस्सा

136. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण		2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि (ए)
संबद्ध देशों से आयात	%	6.63%	6.11%	5.50%	5.09%	5.09%
	सूचीबद्ध	100	92	83	77	77
मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर)	%	9.26%	8.48%	7.54%	7.26%	7.26%
	सूचीबद्ध	100	92	81	78	78
अन्य देशों से आयात	%	1.02%	0.45%	0.81%	0.39%	0.39%
	सूचीबद्ध	100	44	79	38	38
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	%	36.33%	34.07%	37.53%	36.53%	36.53%
	सूचीबद्ध	100	94	103	101	101
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	94	105	105
अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	105	102	102
अन्य घरेलू उत्पादकों की कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	96	106	106

137. उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि:

- संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान कैप्टिव खपत को शामिल करके और छोड़कर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा एक सीमित रेंज में रहा है।
- पाटित आयातों का बाजार हिस्सा। तथापि, 2016-17 में 7% से मामूली रूप से 2018-19 में 5% तक कम होने के बाद, जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का बाजार हिस्सा समान रहा।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों का घरेलू बाजार में भारी मात्रा में आना जारी रहा।

### III. मालसूची

138. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (ए)
मालसूची	मी. टन	816,152	603,243	746,064	821,292
	सूचीबद्ध	100	74	91	101

उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची	सं.	12	9	10	12
	सूचीबद्ध	100	75	83	100
बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची	सं.	17	12	14	16
	सूचीबद्ध	100	71	82	94

139. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मालसूची में बहुत कम परिवर्तन हुआ है।

#### iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

140. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय नीचे दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (ए)
बिक्रियों की लागत - घरेलू	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	129	119
बिक्री कीमत - घरेलू	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	140	119
लाभ	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	192	332	115
पीबीआईटी - घरेलू बिक्रियां	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	143	198	86
नकद लाभ	आईएनआर/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	157	242	117
पीबीआईटी - घरेलू	करोड़ रु. में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	156	230	129
नकद लाभ	करोड़ रु. में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	172	282	176
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	221	81

141. प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, प्रति मीट्रिक टन लाभ 2016-17 के दौरान \*\*\* रुपये पीएमटी से बढ़कर 2018-19 के दौरान \*\*\* रुपये पीएमटी हो गया। तथापि, जांच की अवधि के दौरान लाभ घटकर \*\*\* रु. पीएमटी हो गया। पीबीआईटी और नकद लाभ के संबंध में यही प्रवृत्ति देखी गई है।

142. यह नोट किया जाता है कि 2016-17 के दौरान आरओसीई \*\*\*% था। यह 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः \*\*\*% और \*\*\*% तक बढ़ गया लेकिन जांच की अवधि के दौरान घटकर \*\*\*% हो गया।

#### v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

143. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	93,704	87,895	83,639	79,418
	सूचीबद्ध	100	94	89	85
मजदूरी	करोड़ रु. में	3,167	3,062	3,053	4,062
	सूचीबद्ध	100	97	96	128
	आईएनआर/मी. टन	2,080	1,834	1,720	1,778
	सूचीबद्ध	100	88	83	85
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	66,606	70,258	73,401	68,169
	सूचीबद्ध	100	105	110	102

144. यह देखा जाता है कि क्षति की पूरी अवधि में और जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार, क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति मी. टन मजदूरी में भी गिरावट आई। कुल मिलाकर उत्पादकता में सुधार हुआ परंतु 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई।

#### vi. वृद्धि

145. 2017-18 और 2018-19 के दौरान घरेलू उद्योग ने संबंधित पूर्ववर्ती वर्षों में वृद्धि दर्ज की, लेकिन उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (ए)	विवरण
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-	5%	4%	-7%
क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	-	6%	1%	-8%
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/वर्ष	-	10%	6%	-14%
प्रति यूनिट लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष	-	1423%	237%	-91%
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-	79%	108%	-60%
नियोजित पूंजी पर आय	वर्ष/वर्ष	-	67%	60%	-75%
मालसूचियां	वर्ष/वर्ष	-	-26%	24%	10%

#### vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

146. पाटन की मात्रा उस सीमा तक का सूचक है जहां तक भारत में आयात पाटित किये जा रहे हैं। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

#### viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

147. घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने में हाल ही में काफी निवेश किया गया था। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है।

#### ix. कम कीमत पर बिक्री की मात्रा/क्षति मार्जिन

148. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित करके निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए क्षति रहित कीमत की तुलना संबंध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है। प्राधिकारी ने पहले पीसीएन

स्तर पर पहुंच मूल्य और क्षति रहित कीमत की तुलना करके प्रत्येक पीसीएन के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। इसके बाद, समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। जहां कहीं भी घरेलू उद्योग द्वारा सटीक मिलान करते हुए पीसीएन की कोई बिक्री नहीं हुई थी, वहां संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना पीसीएन से काफी मिलती-जुलती क्षति रहित कीमत से की गई थी।

149. संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

### क्षति मार्जिन तालिका

क्रम सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक	उत्पाद	एनआईपी (अमे. डॉ./मी. टन)	पहुंच मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज %
1	चीन जन. गण.	सभी उत्पादक/निर्यातक	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
				***	***	***	***	नकारात्मक
				***	***	***	***	नकारात्मक
2	इंडोनेशिया	पीटी क्राकाटऊ पोसको,, इंडोनेशिया	एचआर इन कॉइल	***	***	उ. न.	उ. न.	उ. न.
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	उ. न.	उ. न.	उ. न.
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
3	जापान	जेएफई स्टील कारपोरेशन	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
		निप्पॉन स्टील कारपोरेशन	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	0-10
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
4	कोरिया गणराज्य	पोसको	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
		हुंडई स्टील कंपनी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक
		अन्य सभी	एचआर इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			एचआर नॉट इन कॉइल	***	***	***	***	नकारात्मक
			पीयूसी भारित औसत	***	***	***	***	नकारात्मक

**क्षति पर जांच**

150. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से गिरावट आई है लेकिन कैप्टिव खपत को छोड़कर मांग में महत्वपूर्ण बनी हुई है। जबकि कीमत में कटौती नकारात्मक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों का पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। यह नोट किया जाता है कि और भारत में उनके कुछ संबंधित आयातकों ने पीयूसी को उपयोगकर्ताओं को उस कीमत से कम पर बेचा है जिस पर उनका आयात किया गया था या उनकी संबंधित संस्थाओं और स्वतंत्र खरीदारों के लिए निर्यात मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर था। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में हास और हास दोनों ही हुए थे। जबकि जांच की अवधि के दौरान देखी गई मांग में कमी के कारण उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में कमी आई थी। घरेलू उद्योग के निष्पादन में कीमत हास और मंदी के कारण इसी अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की वृद्धि भी नकारात्मक हो गई है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है!

**अ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण**

151. धारा 9क(5) के तहत, प्राधिकारी को पाटन और क्षति की संभावना तथा शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने की आवश्यकता है, भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ हो या नहीं। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति सकती है:

**i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

152. यह देखा जाता है कि पाटित आयातों को छोड़कर अन्य देशों से आयात नगण्य हैं और क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान मांग के 0.39% से 1.02% के बीच थे और इसलिए, तीसरे देश के आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते।

**ii. मांग में संकुचन**

153. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी आई है। तथापि, जब मांग में संकुचन हुआ जिसने जांच की अवधि के पिछले छह महीनों के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री को प्रभावित किया, संबद्ध देशों से आयातों में भी समानुपातिक रूप से कमी आई और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयात जांच की अवधि के दौरान पूर्व वर्ष अर्थात् 2018-19 से तुलना करने पर समान रहे। इसलिए, मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

**iii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

154. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में किसी वास्तविक परिवर्तन (परिवर्तनों) के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसलिए, खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षति का कारण नहीं हैं।

**iv. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

**v. प्रौद्योगिकी में विकास**

156. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

**vi. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

157. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निर्यात इसके उत्पादन का छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।



**vii. अन्य उत्पादों का निष्पादन**

158. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और उन्हें क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**ट. क्षति के जारी रहने और कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण****घरेलू उद्योग की क्षति की संभावना**

159. प्राधिकारी पाते हैं कि यह निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच का जोर सतत पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने की अनुमति दी जाए, यहां तक कि वर्तमान पाटन अथवा क्षति नहीं है।

**ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

160. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के असमान, भारत केवल बड़ा निर्यातक लक्ष्य है जिसके पास अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कोई रक्षोपाय नहीं है। किसी सुरक्षा के अभाव में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के बाजारों में भारी मात्रा में आने की संभावना है।
- ख. ओईसीडी स्टील रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इस्पात क्षमता में 2018 से 2019 में 34.1 मी. टन तक वृद्धि हुई। 2022 के लिए अनुमान में 58-78 मी. टन की वृद्धि का अनुमान है जो कोरिया के लगभग समतुल्य है जिसकी चौथी सबसे बड़ी क्षमता है।
- ग. भारत में मांग बढ़ने की उम्मीद है तथा 2021 और 2022 में क्षमता में वृद्धि भारत की बढ़ी हुई मांग को पूरा करेगी।
- घ. संबद्ध देशों के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं से भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों के निर्यात हो सकते हैं।
- ङ. 2019 में अप्रयुक्त क्षमता दूसरी (यूरोपीय संघ), तीसरी (जापान) और चौथी (भारत) सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं की संयुक्त क्षमता के लगभग बराबर है। 2021 में निर्यात फिर से बढ़ने की उम्मीद है जब बाजार लॉकडाउन से पहले के स्तर पर काम करेंगे।
- च. संबद्ध देशों के खिलाफ तीसरे देशों द्वारा शुरू किए गए 28 व्यापार उपचार उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इस उपाय ने न केवल संबद्ध देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात बल्कि अन्य देशों को उनके निर्यात को भी प्रभावित किया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए धारा 232 उपायों का 'बाउंसिंग ऑफ' प्रभाव से अपने उद्योग की सुरक्षा के लिए उपायों की रक्षा करते हैं।

क्रम सं.	जिस देश पर लगाया गया है	प्रभावित देश	उपाय	प्रारंभिक अधिरोपण अथवा अंतिम विस्तार की तिथि	उत्पाद
1.	कनाडा	चीन	पाटनरोधी	13-फर.-1997 (पूर्व में विस्तारित 9-अग.-2018)	कुछ हॉट रोलड स्टील प्लेट (पूर्व में हॉट रोलड कार्बन स्टील प्लेट)
2.	कनाडा	चीन	पाटनरोधी	17-अग.-2001 (पूर्व में विस्तारित 12-अग.-2016)	कुछ हॉट रोलड स्टील शीट (पूर्व में हॉट रोलड कार्बन स्टील शीट)
3.	यूरोपीय संघ	चीन	पाटनरोधी	06-अप्रैल-2017	आयरन, नॉन-अलॉय अथवा अन्य अलॉय स्टील के कुछ हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद

4.	इंडोनेशिया	चीन	पाटनरोधी	15-अग.-2019	हॉट रोलड प्लेट
5.	थाईलैंड	चीन	पाटनरोधी	12-अग.-2011 (पूर्व में 23-जून-2017 को विस्तारित)	फ्लैट हॉट रोलड इन कॉइल्स और नॉट इन कॉइल्स
6.	थाईलैंड	चीन	पाटनरोधी	26-दिसं-2012 (पूर्व में 12-दिसं.- 2018 को विस्तारित)	फ्लैट हॉट रोलड स्टील एंडेड बोरोन इन कॉइल्स एंड नॉट इन कॉइल्स
7.	संयुक्त राज्य अमेरिका	चीन	पाटनरोधी	27-अग.-2019	कुछ हॉट रोलड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
8.	कनाडा	ब्राजील	पाटनरोधी	17-अग.-2001 (पूर्व में विस्तारित 12-अग.-2016)	कुछ हॉट रोलड स्टील शीट (पूर्व में हॉट रोलड कार्बन स्टील शीट)
9.	यूरोपीय संघ	ब्राजील	पाटनरोधी	6-अक्तूबर-2017	आयरन, नॉन-अलॉय अथवा अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद
10.	थाईलैंड	ब्राजील	पाटनरोधी	16-मई-2017	फ्लैट हॉट रोलड इन कॉइल्स एंड नॉट इन कॉइल्स
11.	संयुक्त राज्य अमेरिका	ब्राजील	सीवी	3-अक्तूबर-2016	फ्लैट हॉट रोलड स्टील प्रोडक्ट्स
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	ब्राजील	पाटनरोधी	3-अक्तूबर-2016	फ्लैट हॉट स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	जापान	पाटनरोधी	5-सितंबर-2019	हॉट रोलड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
14.	इंडोनेशिया	कोरिया	पाटनरोधी	7-फर.-2011	हॉट रोलड कॉइल
15.	थाईलैंड	कोरिया	पाटनरोधी	23-मई-2020	फ्लैट हॉट रोलड इन कॉइल्स एंड नॉट इन कॉइल्स
16.	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोरिया	सीवी	3-अक्तूबर-2016	हॉट रोलड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स
17.	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोरिया	पाटनरोधी	9-जुलाई-2019	हॉट रोलड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
18.	ब्राजील	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	19-जन.-2018	हॉट रोलड स्टील
19.	यूरोपीय संघ	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	6-अक्तू.-2017	आयरन, नॉन-अलॉय अथवा अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद
20.	इंडोनेशिया	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	2-अप्रैल-2019	हॉट रोलड कॉइल
21.	मैक्सिको	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	29-मार्च-2015	हॉट रोलड शीट
22.	थाईलैंड	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	23-मई-2020	फ्लैट हॉट रोलड इन कॉइल्स एंड नॉट इन कॉइल्स
23.	संयुक्त राज्य	रूसी फेडरेशन	पाटनरोधी	20-अक्तू.-2016	हॉट रोलड कार्बन

	अमेरिका				स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
24.	थाईलैंड	इंडोनेशिया	पाटनरोधी	21-मई-2015	फ्लैट हॉट रोलड इन कॉइल्स एंड नॉट इन कॉइल्स
25.	संयुक्त राज्य अमेरिका	इंडोनेशिया	पाटनरोधी	3-दिसं.-2001 (पूर्व में विस्तारित: 27- अग.-2019)	कुछ हॉट रोलड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
26.	संयुक्त राज्य अमेरिका	इंडोनेशिया	सीवी	27-अग.-2019	कुछ हॉट रोलड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स
27.	यूरोपीय संघ	सभी	एसजी	18-जुलाई-2018	ऑल स्टील प्रोडक्ट्स
28.	संयुक्त राज्य अमेरिका	सभी	एसजी	23-मार्च-2018	ऑल स्टील प्रोडक्ट्स

छ. उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ ने 18 जुलाई, 2018 को स्टील उत्पादों के आयात पर एक सुरक्षा उपाय लागू किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यूरोपीय संघ के उद्योग को उन देशों से बढ़े हुए आयात से बचाना था जो यूएस 232 उपाय के कारण अमेरिका को निर्यात नहीं कर सके।

ज. संबद्ध देशों में स्टील का उत्पादन 2017 से 2019 के बीच बढ़ा, जहां चीन में 14.5% और इंडोनेशिया में 23% तक वृद्धि हुई। संबद्ध देशों में मांग उनके पूरे उत्पादन को खपाने करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत निर्यात किया जाता है। यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो उच्च निर्यातोन्मुखता से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की अत्यधिक संभावना हो सकती है।

झ. 2019 में संबद्ध देशों से वैश्विक निर्यात में गिरावट आई है और इस प्रकार उनके पास संबद्ध सामानों की काफी मालसूची हो सकती है। शुल्कों के समाप्त होने पर इन्हें भारत में भेजा जा सकता है।

देश	2019	2018	कमी
चीन	63.8	68.8	5
जापान	33.1	35.8	2.7
रूस	29.5	33.3	3.8
कोरिया	29.9	30.1	0.2
ब्राजील	13.3	13.9	0.6
कुल	169.6	181.9	12.3

[स्रोत: डब्ल्यूएसए]

ञ. संबद्ध देशों द्वारा धारित क्षमताएं उनके संबंधित बाजारों में खपत से कहीं अधिक हैं। ऐसी स्थिति में जब अधिकांश प्रमुख इस्पात खपत वाले देशों ने अपने बाजार बंद कर दिए हैं, अतिरिक्त क्षमता वाले निर्यातोन्मुख देश खुले और अनुमानित बाजार की ओर देखेंगे।

	उत्पादन			खपत			आधिक्य उत्पादन		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
चीन जन. गण.	996.3	920	870.9	907.5	836.1	773.8	88.8	83.9	97.1
जापान	99.3	104.3	104.7	63.2	65.4	64.4	36.1	38.9	40.3
इंडोनेशिया	6.4	6.2	5.2	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
रूस	71.9	72.1	71.5	43.5	41.4	41.2	28.4	30.7	30.3

कोरिया गणराज्य	71.4	72.5	71	53.2	53.7	56.3	18.2	18.8	14.7
ब्राजील	32.2	35.4	34.5	20.6	21.2	19.6	11.6	14.2	14.9
<b>कुल</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>1088</b>	<b>1017.8</b>	<b>955.3</b>	<b>183.1</b>	<b>186.5</b>	<b>197.3</b>

[स्रोत: डब्ल्यूएसए]

ट. संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात की कीमत भारत को किए गए निर्यात से कम है। चूंकि संबद्ध देशों से भारत में कीमतें उनकी वैश्विक निर्यात कीमतों से अधिक हैं, अतः यह सिद्ध है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो संबद्ध देश संबद्ध सामानों के पाटन के लिए भारतीय घरेलू बाजार की ओर तेजी से रुख करेंगे क्योंकि वे अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

	भारत में एचआर कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)	विश्व में एचआर कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)	भारत में एचआर नॉट इन कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)	विश्व में एचआर नॉट इन कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)
ब्राजील	-	493	-	669
चीन	576	514	745	560
इंडोनेशिया	-	506	580	552
जापान	529	536	993	694
कोरिया	585	558	664	658
रूस	-	476	-	614

(स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप आंकड़े)

ठ. अप्रयुक्त क्षमता, ऐसी अप्रयुक्त क्षमताओं के शिखर पर क्षमता में वृद्धि, अधिशेष उत्पादन, प्रमुख इस्पात खपत वाले देशों में व्यापार बाधाएं, संचयी रूप से अचूक तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की और पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाने की स्थिति में वास्तविक क्षति बार-बार होने की स्पष्ट और आसन्न संभावना है।

ड. संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं:-

यूनिट: मिलियन मीट्रिक टन

		2017	2018	2019
चीन	क्षमता	1164	1128	1152
	उत्पादन	871	920	996
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>293</b>	<b>198</b>	<b>156</b>
जापान	क्षमता	130	130	130
	उत्पादन	105	104	99
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
कोरिया	क्षमता	82	82	82
	उत्पादन	71	72	71
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

इंडोनेशिया	क्षमता	11	11.5	12
	उत्पादन	5	6	6.5
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
रूस	क्षमता	86	86	87
	उत्पादन	71	72	72
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
ब्राजील	क्षमता	51	51	51
	उत्पादन	34	35	32
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
संबद्ध देश	क्षमता	1513	1477	1502
	उत्पादन	1157	1209	1276.5
	<b>अप्रयुक्त क्षमता</b>	<b>356</b>	<b>268</b>	<b>225.5</b>

[स्रोत: ओईसीडी और डब्ल्यूएसए]

इस तथ्य के बावजूद कि ओईसीडी लगातार देशों से अपनी इस्पात क्षमता कम करने का आग्रह कर रहा है, संबद्ध देशों में क्षमता में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों में अप्रयुक्त क्षमता भारत में मांग से कहीं अधिक है।

ढ. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमा शुल्क (प्रदर्श-27) द्वारा संबद्ध सामानों के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 12.5%/10% से घटाकर 7.5% कर दिया है।

ण. स्टील की कीमतें प्रकृति में चक्रीय हैं और पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक अस्थिर रही हैं। ये कीमतें महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अध्यधीन हैं:

क्रम सं.	उच्च	डॉलर/मी. टन	कम	डॉलर/मी. टन	माह में भिन्नता
1	मई-1995	475	फरवरी-1996	255	9
2	अप्रैल 1997	345	दिसंबर 1998	185	20
3	अप्रैल-2000	333	दिसंबर 2001	175	20
4	फरवरी 2003	353	जून-2003	250	4
5	सितम्बर 2004	625	जुलाई 2005	390	10
6	जून 2006	610	दिसंबर 2006	502	6
7	जून 2008	1113	मार्च -2009	380	9
8	अगस्त-2009	620	नवंबर-2009	496	3
9	अप्रैल-2010	718	जुलाई-2010	588	3
10	फरवरी-2011	772	दिसम्बर 2015	270	58
11	अप्रैल-2016	440	जून-2016	362	2
12	मार्च-2018	637	मई-2020	385	26
13	मई-2021	1015			

(स्रोत: डब्ल्यूएसडी)

त. जब भी स्टील की कीमतें बढ़ीं, वे फिर से तेजी से गिर गईं। वर्ल्ड स्टील डायनेमिक्स अनुमान यह बताते हैं कि स्टील की कीमतें फिर से कम हो जाएंगी:

हॉट रोल्ड बैंड (मी. टन)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	अप्रैल 2020	मई 2021	जून 2021	2021 (ति.-3)	2021 (ति.-4)	2022	2023 - 2030
विश्व निर्यात कीमत (एफओबी)	370	382	530	580	498	487	390	1070	1050	975	750	650	513

(स्रोत: डब्ल्यूएसडी)

थ. जांच की अवधि के बाद की सूचना कानूनी रूप से अनिवार्य कारक नहीं है जिसे प्रत्येक निर्णायक समीक्षा जांच में विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा (1) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के सीमलेस ट्यूब, पाइप और आयरन के खोखले प्रोफाइल - दिनांक 30 जुलाई 2021 के अंतिम जांच परिणाम, (2) चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस स्टेपल फाइबर - 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम, (3) चीन जन. गण. से फ्लैट-बेस्ड स्टील व्हील - 9 अगस्त, 2018 के अंतिम जांच परिणाम (4) चीन, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पाद - 20 जनवरी, 2021 के अंतिम जांच परिणाम (5) चीन जन. गण. से मिथाइल एसिटोसेटेट - 3 मई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम (6) चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया और थाईलैंड से थैलिक एनहाइड्राइड - दिनांक 19 मई, 2021 के अंतिम जांच परिणाम के संबंध में हाल ही में की गई निर्णायक समीक्षा में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए विचार नहीं किया गया था

### 1.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

161. संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत या क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है और इसलिए यह निराधार है। परिणामस्वरूप, जांच की शुरुआत (जो अप्रमाणित याचिका पर आधारित है) में औचित्य नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 द्वारा निर्धारित सीमा को पूरा करने में विफल रहता है।
- ख. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत मांग में वृद्धि और कीमतों में गिरावट के अनुमान अब कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण विश्वसनीय नहीं हैं।
- ग. जांच की अवधि के बाद के आंकड़े यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होंगे कि क्या घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के जांच परिणामों के अनुसार निरंतर क्षति हुई है। इसके अभाव में जांच को समाप्त करना चाहिए।
- घ. कोई काफी आयात नहीं हैं क्योंकि समग्र रूप से संबद्ध देशों से तथा जापान से भी आयातों में जांच की अवधि में कमी आई है।
- ङ. डीजीटीआर में कोविड-19 महामारी से प्रभावित 18 महीने की अवधि (मार्च 2020-सितंबर, 2021) शामिल नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- च. जापान के संबंध में अतिरिक्त क्षमता पर याचिकाकर्ता के दावे निराधार हैं।
- छ. भारत में मांग पर याचिकाकर्ता के दावे और क्षमता वृद्धि केवल बड़ी हुई मांग को पूरा करेगी, निराधार हैं: (1) कोविड-19 महामारी के लिए लेखांकन के बिना 2018/2019 में तैयार किए गए पूर्वानुमान और विश्वसनीय हैं, (2) याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि महामारी के कारण 2020 में मांग में कमी आई है और इसलिए वैश्विक क्षमता का उपयोग भारतीय बाजार को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता था, (3) जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई। याचिकाकर्ता 2021/2022 में मांग में वृद्धि दर्शाने के लिए पूर्वानुमान रिपोर्टों पर विश्वास नहीं कर सकता है।

- ज. प्रश्नावली के उत्तर यह दर्शाएंगे कि निर्यातकों के पास कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं।
- झ. याचिकाकर्ता द्वारा जिन ओईसीडी और डब्ल्यूएसए रिपोर्टों पर विश्वास किया गया है, उन्हें पक्षकारों के सामने प्रकट नहीं किया गया है, जो जापानी मिलों को इस खंड पर सार्थक टिप्पणी प्रदान करने के अवसर से वंचित करता है।
- ञ. यह मानते हुए (लेकिन स्वीकार नहीं) कि जापान में उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क अब संगत नहीं है (कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण) जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, जापान के उत्पादकों को पहले से ही भारत की ओर तथाकथित अप्रयुक्त क्षमताओं का निर्यात कर चुका है। तथापि, जापान से आयात में कमी आई।
- ट. जापानी उत्पादक केवल भारत को विशेष उत्पाद बेचते हैं, भारत में विशेष उत्पादों की मांग पहले से ही कम है और कोविड-19 महामारी के कारण मांग में संकुचन हुआ है। यदि विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ती है, तो भी जापानी उत्पादकों का निर्यात केवल विशिष्ट ग्रेड का होगा।
- ठ. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि उत्पादन और निर्यात में कमी आई है, जापानी मिलों के उत्पादन और मालसूची में भी गिरावट आई है। जापानी मिलों से सभी देशों को निर्यात स्थिर रहे। जापान में अप्रयुक्त क्षमताओं का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ड. जापान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका/यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपायों का जापानी मिलों की बिक्री और निर्यात के पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं है।
- ढ. कुछ जापानी मिलों द्वारा तीसरे देशों को बेचे गए ग्रेडों की काफी मात्रा, जहां व्यापार उपचार के उपाय लागू हैं, भारत को बेचे जाने वाले ग्रेडों के लिए प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इस प्रकार वहां भेजे जाने की संभावना नहीं है।
- ण. भारत-जापान सीईपीए के तहत बीसीडी में कमी के बावजूद निर्यात की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है, अथवा कीमत में कमी नहीं आई है।
- त. केवल निर्यातकों के पास अधिक क्षमता होने का अर्थ यह नहीं है कि इसे भारत की ओर भेजा जाना है, खासकर जब घरेलू उद्योग ने कोई ठोस साक्ष्य प्रदान न किया हो (एडीए का अनुच्छेद 3.2, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबर रसायन अर्थात् एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य, भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी)।
- थ. क्षति मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ प्राप्त कर रहा है और सभी आर्थिक मानदंडों में सुधार हुआ है। इस प्रकार, संबद्ध देशों की निर्यातोन्मुखता और अप्रयुक्त क्षमताओं की मौजूदगी के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क रद्द किया जाना चाहिए।
- द. घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित जेपीसी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मांग 40,478,000 मीट्रिक टन की संस्थापित क्षमता के मुकाबले 41,698,667 मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्टील की मांग में वृद्धि के संबंध में 13-14 प्रतिशत वर्ष के साथ पिछड़े एकीकृत और महत्वपूर्ण निर्यातक घरेलू उद्योग का अर्थ होगा कि कोविड-19 मंदी के बाद घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।
- ध. आधार वर्ष की तुलना में मांग के तुलनीय स्तर पर रहने के बावजूद संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में आधार वर्ष की तुलना में 24% तक गिरावट आई है। यह दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क ने आयातों के मात्रात्मक प्रभाव को कम करने में अपना प्रयोजन सिद्ध किया है।

## 1.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

162. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क के समाम होने की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

163. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि यह दावा किया है कि याचिका में क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है और इसलिए यह निराधार है और जांच शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने भी सूचना के उन्हीं स्रोतों जैसे वर्ल्ड स्टील डायनमिक्स और ओईसीडी रिपोर्टों पर विश्वास किया है।
164. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित मांग में वृद्धि और कीमतों में गिरावट के संबंध में अनुमान अब कोविड-19 के प्रभाव के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में दी गई सूचना में भी ऐतिहासिक आंकड़े निहित हैं, जो यह दर्शाते हैं कि स्टील की कीमतें प्रकृति में चक्रीय हैं और प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि स्टील की कीमतें समय-समय पर उतार-चढ़ाव के अधीन होती हैं।
165. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को कोविड-19 महामारी से प्रभावित 18 महीने की अवधि (अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2020) को शामिल नहीं करना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा की गई कई जांचों में अपनाई गई जांच की अवधि में उपर्युक्त अवधि को शामिल किया गया है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में जांच की लंबी अवधि उपयुक्त है क्योंकि 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित था। वर्तमान क्षति और तथाकथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए एक लंबी अवधि अधिक उपयुक्त होगी। उपर्युक्त को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 तक 18 महीने की जांच की अवधि (पीओआई) को उपयुक्त माना गया है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और जांच की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि शामिल होगी।
166. इस तर्क के संबंध में कि भारत-जापान सीईपीए के तहत बीसीडी में कमी के परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि पाटनरोधी शुल्क, शुल्क संदर्भ कीमत पर आधारित है, यह आयातों को घरेलू बाजार में बीसीडी में गिरावट के बावजूद ऐसी संदर्भ कीमत से कम कीमत पर आने से रोकता है।
167. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप मांग समान स्तर पर रहने के बावजूद आयात आधार वर्ष से कम हो गया है और घरेलू उद्योग को अब क्षति नहीं हो रही है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटित आयातों में फिर से वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की बार-बार संभावना होगी।
168. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 में उल्लिखित अपेक्षा और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इस तरह की संभावना विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II का खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन्हें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है जैसे:
- (i) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो कि पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाए।
  - (ii) किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटानयोग्य, या एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;
  - (iii) क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव है, और संभावित रूप से आयातों की और मांग बढ़ाएंगे; तथा



(iv) जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

**i. जारी और मौजूदा पाटन एवं क्षति**

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात, पाटनरोधी शुल्क विद्यमान होने के बावजूद पाटित कीमतों पर हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
170. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में गिरावट आई है।
171. पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा काफी रही है।

**ii. तीसरे देशों को निर्यात कीमतें**

172. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमतें भारत को किए जाने वाले निर्यातों की अपेक्षा काफी कम हैं।

	भारत में एचआर कॉइल्स का औसत निर्यात कीमत (2019)	विश्व में एचआर कॉइल्स का औसत निर्यात कीमत (2019)	भारत में एचआर नॉट इन कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)	भारत में एचआर नॉट इन कॉइल्स की औसत निर्यात कीमत (2019)
ब्राजील	-	493	-	669
चीन	576	514	745	560
इंडोनेशिया	-	506	580	552
जापान	529	536	993	694
कोरिया	585	558	664	658
रूस	-	476	-	614

(स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप)

173. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश जिनका भारत को कोई निर्यात नहीं था, तीसरे देशों को कम कीमतों पर निर्यात कर रहे थे। एचआर इन कॉइल्स के संबंध में, भारत को निर्यात नहीं करने वाले देशों के तीसरे देश की निर्यात कीमतें भारत को निर्यात करने वाले देशों के तीसरे देश की निर्यात कीमतों की तुलना में कम थीं। एचआर नॉट इन कॉइल्स के संबंध में भी, तीसरे देश के उन देशों की निर्यात कीमतें जिन्होंने भारत को निर्यात नहीं किया था, सामान्य रूप से कुछ संबद्ध देशों के तीसरे देश की निर्यात कीमतों से कम थीं।

**iii. संबद्ध देशों में मांग से अधिक उत्पादन**

174. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध देशों में देश के भीतर खपत की तुलना में अत्यधिक उत्पादन होता है।

	उत्पादन			खपत			आधिक्य उत्पादन		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
चीन जन. गण.	996.3	920	870.9	907.5	836.1	773.8	88.8	83.9	97.1
जापान	99.3	104.3	104.7	63.2	65.4	64.4	36.1	38.9	40.3
इंडोनेशिया	6.4	6.2	5.2	डीएनए	डीएनए	डीएनए	डीएनए	डीएनए	डीएनए
रूस	71.9	72.1	71.5	43.5	41.4	41.2	28.4	30.7	30.3
कोरिया गणराज्य	71.4	72.5	71	53.2	53.7	56.3	18.2	18.8	14.7
ब्राजील	32.2	35.4	34.5	20.6	21.2	19.6	11.6	14.2	14.9
<b>कुल</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>1088</b>	<b>1017.8</b>	<b>955.3</b>	<b>183.1</b>	<b>186.5</b>	<b>197.3</b>

(स्रोत: डब्ल्यूएसए)

175. चीन 2019 के दौरान चीन में मांग से अधिक 88.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है। जापान, रूस, कोरिया गणराज्य और ब्राजील वर्ष 2019 के दौरान क्रमशः 36.1 मिलियन मीट्रिक टन, 28.4 मिलियन मीट्रिक टन, 18.2 मिलियन मीट्रिक टन और 11.6 मिलियन मीट्रिक टन की मांग से अधिक उत्पादन करते हैं। यह प्रवृत्ति ऐतिहासिक है क्योंकि मांग से अधिक उत्पादन पिछले वर्षों के दौरान भी मौजूद था। इससे पता चलता है कि वे अत्यधिक निर्यात उन्मुख हैं।

#### iv. अप्रयुक्त क्षमताएं

176. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।

देशों	क्षमता			उत्पादन			अप्रयुक्त क्षमता		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
चीन जन. गण.	1152	1128	1164	996.3	920	870.9	156	198	293
जापान	130	130	130	99.3	104.3	104.7	31	26	25
इंडोनेशिया	12	11.5	11	6.4	6.2	5.2	5.5	5.5	6
रूस	87	86	86	71.9	72.1	71.5	15	14	15
कोरिया गणराज्य	82	82	82	71.4	72.5	71	11	10	11
ब्राजील	51	51	51	32.2	35.4	34.5	19	16	17
<b>कुल</b>	<b>1502</b>	<b>1477</b>	<b>1513</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>225.5</b>	<b>268</b>	<b>356</b>

(स्रोत: डब्ल्यूएसए और ओईसीडी)

177. पिछले वर्ष की तुलना में 2019 के दौरान संबद्ध देशों में क्षमता में वृद्धि हुई है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की दर से अधिक दर से बढ़ा है। संबद्ध देशों में अप्रयुक्त क्षमता 225.5 मिलियन मीट्रिक टन है जो भारत में मांग से कहीं अधिक है।

#### v. संबद्ध देशों से निर्यात में गिरावट

178. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2018 की तुलना में 2019 के दौरान संबद्ध देशों से निर्यात में गिरावट आई है।

#### vi. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपाय

179. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में भारत के अलावा अन्य देशों द्वारा संबद्ध देशों के विरुद्ध कई व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए गए हैं।

#### vii. मूल सीमा शुल्क में कमी

180. प्राधिकारी नोट करते हैं कि फरवरी, 2021 से संबद्ध सामानों के आयातों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। कोरिया गणराज्य और जापान से आयात भारत-कोरिया सीईपीए और भारत-जापान सीईपीए के कारण 0% मूल सीमा शुल्क के अध्वधीन हैं।

#### viii. स्टील की कीमतों की चक्रीय प्रकृति

181. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस्पात की कीमतें प्रकृति चक्रीय में हैं और इन वर्षों में अत्यधिक अस्थिर रही हैं। कीमतें महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अध्वधीन हैं, कुछ निश्चित अवधियों में कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद टूटी हैं। वर्तमान स्टील की कीमतें आपूर्ति की कमी और कच्ची सामग्री की अधिक कीमतों के कारण बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती हैं।

हॉट रोलड बैंड (एमटी)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Apr 2020	May 2021	June 2021	2021 (Q3)	2021 (Q4)	2022	2023 - 2030
विश्व निर्यात बाजार (एफओबी)	370	382	530	580	498	487	390	1070	1050	975	750	650	513

(स्रोत: डब्ल्यूएसए)

**ठ. पाटन और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष**

182. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य की जांच से प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्राजील और रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से पाटन जारी है और पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, ब्राजील और रूस को छोड़कर संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि के दौरान काफी रही है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच की अवधि के दौरान निरंतर वास्तविक क्षति हो रही है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमतें भारत में उनकी कीमतों से कम हैं। यद्यपि जांच की अवधि के दौरान रूस और ब्राजील से कोई आयात नहीं हुआ था, तथापि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि तीसरे देशों को उनकी निर्यात कीमत उन संबद्ध देशों के तीसरे देश की निर्यात कीमत से कम है, जिन्होंने भारत को निर्यात किया था। संबद्ध देशों के पास संबद्ध सामानों के अधिशेष उत्पादन के साथ-साथ अप्रयुक्त क्षमताएं भी हैं। इसके अतिरिक्त, कई तीसरे देशों ने संबद्ध देशों पर कई व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं जिन्होंने संबद्ध देशों के पास मौजूद अधिशेष उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमताओं की खपत के लिए अन्य निर्यात बाजारों को सीमित किया है। अन्य देशों द्वारा लगाए गए अधिशेष उत्पादन, अप्रयुक्त क्षमताओं और व्यापार उपचारात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए, जो उन बाजारों को सीमित करते हैं जहां संबद्ध देश निर्यात कर सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातकों द्वारा इन अधिशेष उत्पादन और अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग मौजूदा बड़े हुए स्तरों, जो पहले से ही काफी अधिक हैं, से बड़ी हुई मात्रा में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश अन्य देशों से अपने निर्यातों को, जो कम कीमतों पर किए जा रहे हैं, पाटन बंद होने की स्थिति में भारत को भेज सकते हैं। इस प्रकार, इन सभी मानदंडों से संकेत मिलता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, संबद्ध देशों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को पाटित उत्पादों के निर्यात को तेज करने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को पाटन जारी रहेगा और क्षति और भी अधिक होगी।

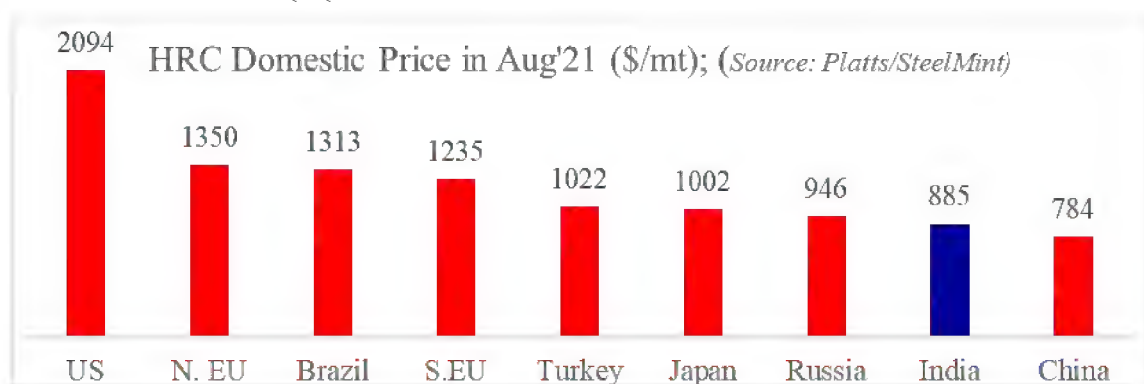
**ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध****ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

183. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- घरेलू उत्पादकों ने या तो उन ग्रेडों का उत्पादन किया है जिनके विरुद्ध हितबद्ध पक्षकारों ने उन्हें अलग किए जाने का दावा किया है या उनके पास ऑर्डर पर उनका निर्माण करने की क्षमता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा नहीं किया है कि ये ग्रेड नव विकसित हैं अथवा उस समय मौजूद नहीं थे जब मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण किया जा रहा था।
- उत्तरदाताओं के लिए यह दावा करना पर्याप्त नहीं है कि उन ग्रेडों की वास्तविक विशिष्टियां बताए बिना घरेलू उद्योग में क्षमता नहीं है। इसके बजाय, यह दावा करना प्रयोक्ता उद्योग के लिए है कि घरेलू उद्योग किसी उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। यह दर्शाया जाना है कि इसे घरेलू उद्योग से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और अस्वीकरण के साथ पूरा किया गया था। ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है।
- हुंडई ने कुछ ग्रेडों को आसानी से प्रतिस्थापनीय सूचीबद्ध किया है लेकिन उन ग्रेडों को अलग करने की मांग नहीं की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास उल्लिखित ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता है, और वास्तव में बिक्री बीजक के साक्ष्य के रूप में उन्हें उत्पादित और बेचा है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि घरेलू उद्योग किसी विशिष्ट ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर सकता।

- (iv) बीआईएस मानकों, एसआईएमएस, पीएलआई योजना और इस्पात पुनर्चक्रण नीति जैसी योजनाओं का लक्ष्य घरेलू उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, लेकिन यह पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों के विरुद्ध इसका बचाव नहीं कर सकता। चूंकि स्टील की कीमतें चक्रीय होती हैं, अतः जब स्टील की कीमतें कम होती हैं, तो निर्यातकों और उत्पादकों द्वारा पाटन की वर्तमान मात्रा पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में भी भारी कमी आएगी। इससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।
- (v) हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं स्वीकार किया है कि संदर्भ कीमत के आधार पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उन आयातों पर अनावश्यक दंड को रोकता है जो घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अधिक कीमत पर किए जा रहे हैं और इसलिए, घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं ने स्वीकार किया है कि वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं।
- (vi) ब्राजील और रूस के संबंध में, उत्पादकों और निर्यातकों के असहयोग से यह सिद्ध होता है कि पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात फिर से शुरू होने का आसन्न खतरा है।
- (vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि एनएससी की बिक्री एक असहयोगी संबद्ध कंपनी के माध्यम से होती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि ऐसी घरेलू बिक्री नगण्य है। यह अनुरोध किया जाता है कि एक संबद्ध कंपनी द्वारा असहयोग को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और संबद्ध विक्रेता कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के मद्देनजर एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जो कि व्यापक हो सकता है और उनके द्वारा पुनर्विक्रय किए गए लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेनों को शामिल कर सकता है और ऐसी संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए पुनर्विक्रय और अन्य खर्चों की लागत अधिक हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या सहयोगी उत्पादक द्वारा सूचित की गई लागत में संबद्ध विक्रेता कंपनियों द्वारा लगाई गई लागत उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुरूप बनाना आवश्यक है। चूंकि संबद्ध कंपनियों ने सहयोग नहीं किया है, अतः एनएससी के प्रत्युत्तर को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- (viii) एनएससी, जापान, जेएफई स्टील कॉरपोरेशन, पोसको कोरिया गणराज्य और पीटी क्राकाटाऊ पोसको, इंडोनेशिया की निर्यात कीमत निर्धारण के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया कि इन कंपनियों ने उन कुछ कंपनियों के माध्यम से कुछ मात्राओं में निर्यात किया है जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। तथापि, ऐसी कंपनियों से निर्यात को कम माना गया था। यह तथ्य कि कुछ निर्यातकों अथवा संबद्ध व्यापारिक कंपनियों ने भाग नहीं लिया है, उत्पादकों के उत्तरों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार है और कोई अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ix) संबद्ध देशों से कीमत कटौती का नकारात्मक होना यह नहीं दर्शाता कि आयातों का कीमत ह्रासकारी और न्यूनीकरण प्रभाव नहीं था। यह नोट करना संगत है कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों की सहायक कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद को हानि पर बेचा है। ऐसे कारक इस तथ्य के संकेतक हैं कि भारित औसत आयात कीमतें कीमत न्यूनीकरण और ह्रासमान प्रभावों की उचित तुलना नहीं करने देते क्योंकि आयात संबद्ध देशों में उत्पादकों की संबद्ध कंपनियों द्वारा स्वतंत्र खरीदारों को हानि पर बेचे जा रहे हैं।
- (x) यद्यपि औसत आयात कीमतों में कम अथवा नकारात्मक कीमत कटौती दिखाई दे सकती है, तथापि भारत में उत्पादकों और उनकी संबद्ध कंपनियों द्वारा इस तरह की परिपाटियों के परिणामस्वरूप कीमत प्रतिस्पर्धा का एक बहुत ही कम मार्जिन होता है जिससे उपर्युक्त मूल्यह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ता है। यह अनुरोध किया जाता है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन की जांच भी उसी परिप्रेक्ष्य में किए जाने की आवश्यकता है।
- (xi) यद्यपि अन्य देशों से आयात नगण्य थे, तथापि पाटन परिपाटियों के कारण संबद्ध देशों से आयात 7% पर काफी बने रहे। कुछ मामलों में पाटन मार्जिन 50% जितना अधिक था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि: (i) भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धी है और बहुत सस्ती दरों पर सामान बेच रहा है; (ii) यदि संबद्ध देशों से पाटन इतनी अधिक मात्रा में जारी नहीं रहता, तो संबद्ध देशों से कीमत का दबाव बहुत कम महसूस होता और घरेलू उद्योग पाटन की अनुचित प्रतिस्पर्धा के अभाव में संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली दरों की तुलना में बेहतर दरों पर आपूर्ति जारी रखने में सक्षम होता।

- (xii) कुछ पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि चूंकि क्षति मार्जिन नकारात्मक है, अतः पाटनरोधी शुल्क बंद किया जाना चाहिए। पूर्व विभिन्न जांचों से पता चलता है कि यदि पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है, तो नकारात्मक क्षति मार्जिन के बावजूद पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जाता है।
- (xiii) पाटनरोधी शुल्क जारी रखना जनहित में होगा क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं स्वीकार किया है कि संदर्भ कीमत के आधार पर लगाए गए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क आयातों पर अनावश्यक दंड को रोकते हैं जो कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से अधिक कीमत पर किए जा रहे हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं।
- (xiv) प्रयोक्ता उद्योग मात्रात्मक सूचना के माध्यम से, उनके प्रचालन अथवा बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने में विफल रहा है। अधिकतर मामलों में, प्रयोक्ताओं ने संदर्भ कीमत से अधिक सामानों का आयात किया है और इस प्रकार, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया है।
- (xv) पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि उसके पास सभी ग्रेडों की आपूर्ति करने की क्षमता है जिसके संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने उन्हें अलग करने का दावा किया है।
- (xvi) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में स्टील की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम रही हैं। अनुचित पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई कीमतें सभी स्रोतों में सबसे कम बनी रहेंगी।
- (xvii) इस्पात उद्योग राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% योगदान देता है और पर्याप्त प्रत्यक्ष (लगभग 5 लाख) और अप्रत्यक्ष रोजगार (लगभग 20 लाख) सृजित करता है। 2015 की गिरावट के कारण 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो गया था जिससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्रों, निवेशकों और अन्य हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- (xviii) निचले स्तर के उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा, उदाहरण के लिए, एचआर स्टील पर 20% पाटनरोधी शुल्क से किफायती आवास पर 0.17% प्रभाव पड़ेगा।
- (xix) प्राधिकारी ने संबंधित उत्पाद के लिए अनुमत क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कुछ समायोजन किए हैं। प्राधिकारी द्वारा किए गए समायोजन अत्यधिक हैं और मौजूदा नियमावली के अनुरूप नहीं हैं। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए स्तर तक क्षतिरहित कीमत में संशोधन करना चाहिए।
- (xx) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क और वैश्विक उछाल के बावजूद भारत में घरेलू स्टील की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्टील की कीमतों से कम रही हैं।



## ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

184. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) प्राधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने वास्तव में उन ग्रेडों का उत्पादन और बिक्री की है जिनके विरुद्ध एनएससी द्वारा उन्हें अलग किए जाने की मांग की गई।

- (ii) अलग करने के अनुरोध की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति घरेलू उद्योग के ग्रेडों और उत्पादक के ग्रेड के बीच पीसीएन-दर-पीसीएन तुलना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बल्कि, प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या संबद्ध ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में उत्पादित और बेचे गए थे।
- (iii) डीजीटीआर को जापानी मिलों द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रश्नावली के उत्तरों में संगत सूचना पर विचार करना चाहिए।
- (iv) डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़े जापानी मिलों को उनके अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
- (v) चूंकि डीजीटीआर ने प्रकटन विवरण में एचआर इन कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए अलग से पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है, अतः डीजीटीआर को घरेलू उद्योग की स्थिति और क्षति मूल्यांकन का एक अलग मूल्यांकन भी करना चाहिए।
- (vi) एसआईएमएस, बीआईएस मानकों, पीएलआई योजनाओं, इस्पात रिसाइकिलिंग नीति और घरेलू उद्योग के संरक्षण के उद्देश्य से अन्य नीतियों की मौजूदगी को डीजीटीआर के पाटन और वास्तविक क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के मूल्यांकन में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग को मौजूदा नीतियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह भारत में उन आयातकों/प्रयोक्ताओं को दंडित करने का औचित्य नहीं बनाता, जिन पर शुल्क लगाए जाने के कारण भार पड़ेगा।
- (vii) पूर्व जांच में डीजीटीआर ने औसत पाटन मार्जिन के लिए पीसीएन आधार पर डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को अलग किया है। वर्तमान जांच के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।
- (viii) डीजीटीआर ने अपने क्षति विश्लेषण में असंगत/चुनिंदा दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए, प्रकटन विवरण के पैरा 130 में, डीजीटीआर ने आधार वर्ष के साथ जांच की अवधि के आंकड़ों की तुलना करते हुए कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास का मूल्यांकन किया है। जबकि, पैरा 140 और 141 में, डीजीटीआर ने पूर्व (आधार वर्ष के बजाय) के साथ जांच की अवधि के आंकड़ों की तुलना करके घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का मूल्यांकन किया है। डीजीटीआर को एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- (ix) डीजीटीआर द्वारा अपने प्रकटन विवरण में माने गये आंकड़े याचिकाकर्ता द्वारा पहले दायर किए गए आंकड़ों से अलग हैं। तदनुसार, डीजीटीआर से अनुरोध किया जाता है कि वे तत्काल वे कारण देते हुए स्पष्टीकरण जारी करें कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े प्रकटन विवरण में विश्वास किए गए आंकड़ों से भिन्न क्यों हैं।
- (x) डीजीटीआर की यह टिप्पणी कि मांग में संकुचन घरेलू क्षति को क्षति का कारण नहीं हो सकता, विरोधाभासी है, जैसा कि डीजीटीआर ने पैरा 134(iii) में नोट किया है कि मांग में गिरावट के कारण बिक्री और क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है।
- (xi) कम मांग और उच्च वित्त लागत से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। इन्हें घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है।
- (xii) वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (जिसके सदस्य वैश्विक स्टील उत्पादन का लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं) के अनुसार, 2019 की तुलना में 2020 में भारत में स्टील की मांग में 14.1% तक कमी आई है।
- (xiii) स्टील की कीमतों की चक्रीय प्रकृति पर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- (xiv) वर्तमान मामले में आयात कीमतें संदर्भ कीमत से काफी अधिक हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कीमत में वृद्धि वाणिज्यिक आधारों पर आधारित है और संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के कारण कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ी हैं।
- (xv) जापान से भारत को निर्यात किए जाने वाले हॉट रोलड नॉट इन कॉइल की कीमतें अन्य देशों को बेचे जाने वाले हॉट रोलड नॉट इन कॉइल की तुलना में काफी अधिक हैं। डीजीटीआर के अनुसार, चूंकि भारत

में कीमतें अधिक हैं, अतः जापानी मिलों ने पहले से ही भारत में हॉट रोलड नॉट इन कॉइल्स की काफी मात्रा का निर्यात किया होता। यह विचार करने योग्य है कि ऐसा नहीं है क्योंकि आयात विभिन्न वाणिज्यिक आधारों के आधार पर किए जाते हैं।

- (xvi) डीजीटीआर ने अपने दावे के स्रोत को प्रकट नहीं किया है कि भारत में उत्पादन मांग से अधिक है। इसके अतिरिक्त, खपत से अधिक मात्रा में उत्पादन का होना यह सिद्ध नहीं करता कि संबद्ध देश निर्यातोन्मुख हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात में कमी आई है जबकि तीसरे देशों को निर्यात स्थिर रहा है, और अप्रयुक्त क्षमताओं का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- (xvii) डीजीटीआर ने इस टिप्पणी के लिए अपनी सूचना के स्रोत को प्रकट नहीं किया है कि संबद्ध देशों में क्षमता उपयोग भारत में मांग से कहीं अधिक है। यह मानते हुए कि अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिनका उपयोग भारत के लिए किया जा सकता है, जापान के उत्पादकों ने पहले ही भारत के प्रति ऐसा ही किया होता, जो वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता है।
- (xviii) जून, 2020 से अगस्त, 2021 के बीच, वित्त मंत्रालय ने "स्टील और अन्य धातुओं" की श्रेणी में आने वाले 6 में से 4 मामलों में शुल्क की सिफारिश न करना उचित समझा है, यहां तक कि यद्यपि डीजीटीआर ने शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
- (xix) उत्तरदाताओं को इसके साक्ष्य की कोई अगोपनीय प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है कि घरेलू उद्योग ईएन एस-355/आईएस ई-350 के अनुरूप एचआर प्लेटों का विनिर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने ईएन एस-355/आईएस ई-350 अनुरूप ग्रेड के विनिर्माण की अपनी क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत किया हो सकता है, तथापि पीटीकेपी द्वारा विनिर्मित प्लेटें भारतीय और यूरोपीय दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अनिवार्य मानकों से कहीं बेहतर हैं।
- (xx) यद्यपि आधार वर्ष से लाभ और आरओसीई में सुधार हुआ है, तथापि जांच की अवधि के दौरान उनमें कमी आई है। यह परिवर्तन मांग में कमी और कोविड-19 के प्रभावों के कारण हुआ है। जांच की अवधि में निर्धारित नकारात्मक वृद्धि भी उसी के कारण है।
- (xxi) इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि उत्तरदाताओं की अप्रयुक्त क्षमता भारत को भेजी जाएगी। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 में यह प्रावधान है कि यह केवल सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित है कि क्षति का निर्धारण किया जा सकता है। यह इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माना गया है, जिसमें यह माना गया था कि अधिशेष क्षमता की मौजूदगी को क्षति के स्पष्ट रूप से अनुमानित और आसन्न खतरे के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, अतिरिक्त क्षमताओं से कोई संभावना नहीं बनाई जा सकती।
- (xxii) जनहित के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि ईएन एस355/आईएस ई-350 के अनुरूप ग्रेड, पवनचक्की निर्माण प्रमुख नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हैं। घरेलू उद्योग से समतुल्य आपूर्ति के अभाव में प्रयोक्ता उद्योग को पाटनरोधी शुल्क का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

185 प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उन्हें पर्याप्त रूप से हल किया गया है। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में उठाए गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है:

- (i) जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों को कोई अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके कई संबद्ध/असंबद्ध व्यापारियों और निर्यातकों ने भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात भारत को कुल निर्यात के संदर्भ में बहुत कम हैं। उत्पादकों की निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए, प्राधिकारी ने उन उत्पादकों और सहयोगी व्यापारियों की श्रृंखला के लिए

वास्तविक निर्यात कीमत पर विचार किया है जिन्होंने जांच में विधिवत भाग लिया था और निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में उत्तर प्रस्तुत किए थे, और उन असहयोगी व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया था जिन्होंने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना दायर नहीं की थी। तदनुसार, भारत को सभी निर्यात चैनलों की भारित औसत निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

- (ii) एनएससी के इस तर्क के संबंध में कि एनएससी द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों की और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों की पीसीएन दर पीसीएन तुलना उत्पाद को अलग करने का निर्णय लेने के लिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह डीजीटीआर की परिपाटी के अनुरूप नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और निर्यातक द्वारा उत्पादित ग्रेडों की समान पीसीएन दर पीसीएन तुलना मूल जांच के दौरान की गई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह अनुरोध कि उसने सभी ग्रेडों की आपूर्ति की है, एनएससी को प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया है जिसके अनुसरण में एनएससी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से इसे सत्यापित करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि उन्होंने या तो कुछ ऐसे ग्रेड तैयार किए हैं जिन्हें अलग करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि यदि उसके लिए ऑर्डर प्राप्त होते हैं तो उसके पास उनका उत्पादन करने की क्षमता है। इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग किसी भी ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर सकता जिसके विरुद्ध उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उन्हें अलग किए जाने की मांग की गई है। उत्पादकों और निर्यातकों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि जिन ग्रेडों के लिए अलग किए जाने की मांग की गई है, वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आने वाले किसी अन्य ग्रेड द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। इसलिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उसे अलग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) इस तर्क के संबंध में कि इस साक्ष्य की कोई अगोपनीय प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है कि घरेलू उद्योग ईएन एस-355/आईएस ई-350 के अनुरूप एचआर प्लेट का विनिर्माण करता आ रहा है, प्राधिकारी ने गोपनीय आधार पर दायर बिक्री संबंधी सूचना का सत्यापन किया है, और प्रकटन विवरण में ये तथ्य प्रकट किये हैं।
- (iv) इस दावे के संबंध में कि डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़े जापानी मिलों को उनके अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने उन सभी पक्षकारों को डीजीसीआईएंडएस आंकड़े प्राप्त करने के लिए उन सभी पक्षकारों को प्राधिकार प्रदान किया है जिन्होंने व्यापार सूचना संख्या 07/2018 के अनुसार उचित प्रपत्र में अनुरोध किया है।
- (v) इस तर्क के संबंध में कि पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन एचआर इन कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के लिए अलग-अलग किया गया है और इसलिए, घरेलू उद्योग के आधार का एक अलग मूल्यांकन और इसके संबंध में क्षति मूल्यांकन भी अलग से किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचआर इन कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल के संबंध में अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत अथवा पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसी तुलना करने का यह अर्थ नहीं है कि संपूर्ण क्षति विश्लेषण अलग से किए जाने की आवश्यकता है। यह भी नोट किया जाता है कि सभी आवेदक घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं जिसमें एचआर इन कॉइल और एचआर नॉट इन कॉइल दोनों शामिल हैं और इसके अतिरिक्त, मूल जांच में भी, ऐसी कोई अलग क्षति जांच नहीं की गई थी।
- (vi) इस तर्क के संबंध में कि एसआईएमएस, बीआईएस मानकों, पीएलआई योजनाओं, इस्पात रिसाइकिलिंग नीति और घरेलू उद्योग के संरक्षण के उद्देश्य से अन्य नीतियों की मौजूदगी को पाटन और वास्तविक क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के मूल्यांकन में ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को मौजूदा नीतियों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, जिसके लिए उन आयातकों/प्रयोक्ताओं को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है, जिन पर शुल्क जारी रखने से भार पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते



हैं कि घरेलू उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी है जो इस तथ्य से सिद्ध है कि पाटन संबद्ध देशों से जारी रहने के बावजूद और पाटन मार्जिन काफी होने पर भी, घरेलू उद्योग पाटन आयातों से कम कीमतों पर संबद्ध सामानों की आपूर्ति करने में सक्षम रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि स्टील की कीमतें ऐतिहासिक रूप से समय-समय पर उछाल और गिरावट के साथ प्रकृति में चक्रीय रही हैं, अतः निरंतर पाटन का इतना अधिक मार्जिन पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कारण बनेगा जब स्टील की कीमतें फिर से गिरेंगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं और आयातकों ने संबद्ध देशों से वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क की संदर्भ कीमत से अधिक पर आयात किया है और इसलिए इससे उन्हें संबद्ध सामानों की खरीद में कोई बाधा नहीं आई है।

- (vii) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विवरणों की तुलना में क्षति विश्लेषण जारी रहने की संभावना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और घरेलू इस्पात उद्योग के पक्ष में विभिन्न प्रवृत्तियों और सरकारी कार्यक्रमों/पहलों पर विचार नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सभी सूचनाओं की जांच उस सीमा तक की है जहां तक पाटन और क्षति दोनों के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच के लिए संगत मानी गई है।
- (viii) इस तर्क के संबंध में कि पूर्व जांचों में, डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को औसत पाटन मार्जिन के लिए पीसीएन आधार पर अलग किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधिकारिक डीजीसीआईएस आंकड़ों को पीसीएन के संदर्भ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में दिया गया विवरण काफी संख्या में आयात लेनदेनों को मिलाने के लिए पीसीएन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त नहीं था।
- (ix) इस तर्क के संबंध में कि क्षति विश्लेषण में असंगत दृष्टिकोण लागू किया गया है क्योंकि कीमत न्यूनीकरण और ह्रास की तुलना आधार वर्ष से की गई है, जबकि लाभप्रदता की तुलना पूर्व वर्ष से की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने कीमत प्रभाव का और पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव का वस्तुपरक रूप से विश्लेषण किया है। जांच के दौरान यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की कीमतों में 2018-19 तक वृद्धि हुई जब आयात की कीमतें भी बढ़ रही थीं। इसके बाद, जब जांच की अवधि के दौरान आयातों की कीमतों में गिरावट आई, तो घरेलू उद्योग की कीमतों में भी गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी जांच की अवधि के दौरान उसकी बिक्री लागत में कमी से अधिक थी, यह दर्शाता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसकी कीमतों में न्यूनीकरण और ह्रास दोनों हुए थे। लाभ के संबंध में, यह नोट किया गया था कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, प्रति मीट्रिक टन लाभ में 2018-19 तक काफी वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि के दौरान लाभ में तेजी से गिरावट आई। पीबीआईटी और नकद लाभ के संबंध में एक समान प्रवृत्ति देखी जाती है।
- (x) इस तर्क के संबंध में कि प्रकटन विवरण में माने गये आंकड़े याचिकाकर्ता द्वारा दायर आंकड़ों से अलग हैं, यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त आंकड़ों को प्राधिकारी द्वारा किए गए सूचना के सत्यापन के बाद संशोधित किया गया है।
- (xi) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि प्रकटन विवरण के कारणात्मक संपर्क विश्लेषण में प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता, प्राधिकारी की इस टिप्पणी की विरोधाभासी है कि बिक्री और क्षमता उपयोग मांग में गिरावट के कारण प्रभावित हुए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग आधार वर्ष अर्थात् 2016-17 के समान स्तर पर रही। तथापि, 2018-19 से जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में कमी आई और यह आधार वर्ष के समान स्तर पर थी, घरेलू उद्योग ने आयातों की कीमत में गिरावट के कारण आधार वर्ष की तुलना में नियोजित पूंजी पर कम आय अर्जित की।
- (xii) इस तर्क के संबंध में कि कम मांग और उच्च वित्त लागतों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के संबंध में दी गई सूचना का सत्यापन किया है और यह नोट किया है कि वित्त लागत वास्तव में आधार वर्ष की तुलना में

जांच की अवधि के दौरान कम हुई है और इसलिए, घरेलू उद्योग की कम लाभप्रदता का एक कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि मांग आधार वर्ष के समान स्तर पर है, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उच्चतर सीमा तक गिरावट आई है।

- (xiii) इस दावे के संबंध में कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, 2019 की तुलना में 2020 में भारत में स्टील की मांग में 14.1% की कमी आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े यह भी सिद्ध करते हैं कि 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में कमी आई है और आधार वर्ष के समान स्तर तक कम हो गयी।
- (xiv) इस तर्क के संबंध में कि इस्पात की कीमतों की चक्रीय प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटन जारी है, तथापि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों से कम कीमत वाले पाटित आयात घरेलू बाजार में आने से रुके हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। तथापि, यद्यपि वर्तमान स्टील की कीमतें अधिक हैं और पाटित आयात वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क की संदर्भ कीमत से अधिक पर भारत में आ रहे हैं, तथापि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में इस्पात की कीमतों में फिर से गिरावट आने पर ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
- (xv) इस तर्क के संबंध में कि आयात कीमतें संदर्भ कीमतों से काफी अधिक हैं जो दर्शाता है कि कीमत वृद्धि वाणिज्यिक आधारों पर आधारित है और संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के कारण कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन काफी मात्रा में जारी है और इसलिए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या निरंतर पाटन से वास्तविक क्षति हुई है और क्या यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं तो वास्तविक क्षति बार-बार होने की संभावना है।
- (xvi) इस तर्क के संबंध में कि जापान से भारत को निर्यात किए गए हॉट रोलड नॉट इन कॉइल की कीमतें अन्य देशों को बेची गई कॉइल्स की तुलना में काफी अधिक हैं और इस तरह, जापानी मिलों ने पहले से ही भारत को हॉट रोलड नॉट इन कॉइल की काफी मात्रा का निर्यात किया होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आयात विभिन्न वाणिज्यिक आधारों पर किए जाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क से संबद्ध देशों से कम कीमत वाले पाटित आयात देश में आने से रुके हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्कों ने संबद्ध देशों को भारत में आयात बढ़ाने के लिए अपनी अप्रयुक्त क्षमताओं को लगाने से रोका है।
- (xvii) इस तर्क के संबंध में कि भारत में उत्पादन मांग से अधिक होने के दावे के स्रोत को प्रकट नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का कुल उत्पादन संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है और उपर्युक्त आंकड़े प्राधिकारी के पास दायर अगोपनीय अनुरोधों में निहित थे जिन्हें जांच प्रक्रिया के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।
- (xviii) इस दावे के संबंध में कि इस टिप्पणी के लिए सूचना के स्रोत को प्रकट नहीं किया गया है कि संबद्ध देशों में क्षमता भारत में मांग से कहीं अधिक है, यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त आंकड़े प्राधिकारी के पास दायर अगोपनीय अनुरोधों में निहित डब्ल्यूएसए और ओईसीडी रिपोर्टों से लिये गये हैं जो जांच प्रक्रिया के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे।
- (xix) इस तर्क के संबंध में कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि उत्तरदाताओं की अप्रयुक्त क्षमता भारत को भेजी जाएगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, तीसरे देशों द्वारा संबद्ध देशों पर कई व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए गए हैं। इससे संबद्ध देशों में अप्रयुक्त क्षमताओं की एक अधिक मात्रा हो गई है और किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि तीसरे देशों के अलावा अन्य निर्यात बाजार भी हैं जिन्होंने संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है।
- (xx) इस तर्क के संबंध में कि ईएन एस355/आईएस ई-350 के अनुरूप ग्रेड पवनचक्की निर्माण और प्रमुख नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हैं और घरेलू उद्योग से समतुल्य आपूर्ति के अभाव में प्रयोक्ता

उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का अतिरिक्त भार पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी प्रयोक्ता द्वारा कोई सूचना दायर नहीं की गई है कि संबद्ध देशों से उपर्युक्त ग्रेडों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में प्रयोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की है।

(xxi) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत निकालने में प्राधिकारी द्वारा किए गए समायोजन अत्यधिक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित किया गया है और इसलिए क्षतिरहित कीमत में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

#### ब. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

186. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क जारी रखना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित है।
187. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारणों, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनशीलता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने के प्रभाव, आयातों के स्रोत (चाहे संबद्ध आपूर्तिकर्ताओं अथवा असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से हों), उनके प्रचालनों के लिए लाभप्रदता विवरण आदि के संबंध में भी सूचना मांगी।
188. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:
  - (i) पोस्को-महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड।
  - (ii) हुंडई स्टील पाइप इंडिया प्रा. लिमिटेड
  - (iii) हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
  - (iv) निप्पाॉन स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  - (v) राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
189. इन प्रयोक्ताओं ने मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया और अनुरोध किए, जिन्हें ध्यान में रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन प्रयोक्ताओं ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है और प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रस्तुत की है, वे विदेशी निर्यातकों से संबद्ध हैं और या तो अपने संबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहे हैं अथवा अपने संबद्ध पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं। इन हितबद्ध पक्षकारों ने मात्रात्मक सूचना के साथ यह नहीं दर्शाया है कि संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन प्रयोक्ताओं अथवा जनता पर कोई काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हितबद्ध पक्षकारों ने मात्रात्मक सूचना के साथ यह भी नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारत में उनके प्रचालनों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
190. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयात संदर्भ कीमत से अधिक कीमत पर हुए हैं और प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का कोई भार नहीं पड़ा है और इसलिए, प्रयोक्ताओं पर संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को मापना संभव नहीं है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोधों से नोट करते हैं कि काल्पनिक रूप से, विचाराधीन उत्पाद पर 20% की दर से पाटनरोधी शुल्क मानते हुए, यह देखा जा सकता है कि प्रभाव नगण्य होगा अर्थात् 2 लाख रुपये के वहनीय कुल मूल्य के 0.17% से कम होगा।

191. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद सहित स्टील की कीमतें वैश्विक स्टील कीमतों से कम रही हैं, भले ही हाल ही में वैश्विक स्टील की कीमतों में समग्र वृद्धि हुई हो। इससे पता चलता है कि भारत में घरेलू उद्योग को लागू पाटनरोधी शुल्क अथवा वैश्विक कीमतों में हाल की वृद्धि से अनुचित लाभ नहीं हुआ है और उत्पाद के आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी और हाल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि होने के कारण पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।
192. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संबद्ध सामानों की आपूर्ति कर रहा है, यह इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि पूरी क्षति विश्लेषण अवधि में संबद्ध देशों से कीमत कटौती नकारात्मक रही है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू बिक्री कीमत जांच की अवधि सहित पूरी क्षति विश्लेषण अवधि में संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से कम रही है जब संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन बहुत अधिक था।
193. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाओं का कम उपयोग किया गया है। भारत में घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं।
194. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
195. डंपिंग रोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो सामान्य रूप से है। देश हित। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और इस प्रकार, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा, यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी जहां उपयोगकर्ता इसे संबद्ध देशों से प्राप्त करना चुनते हैं।
196. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय इस्पात उद्योग भारतीय जीडीपी में इसके योगदान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन और परिवहन सेवाओं, बंदरगाह सुविधाओं आदि जैसी लिंकड डाउनस्ट्रीम सेवाओं के लिए इसके समर्थन को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। शुल्क की निरंतरता सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी। अनुचित व्यापार प्रथाओं और वैश्विक इस्पात कीमतों की चक्रीय प्रकृति से घरेलू उद्योग के लिए शुद्ध जो निकट भविष्य में घटने का अनुमान है।
197. अतः, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में होगा।

## ण. निष्कर्ष

198. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
  - क. आवेदक घरेलू उत्पादक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं और घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
  - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
  - ग. आवेदन पत्र में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने के उद्देश्य से सभी संगत सूचनाएं निहित हैं और आवेदन पत्र में वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
  - घ. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 तक 18 महीने की लंबी अवधि को जांच की अवधि के रूप में माना ताकि यह घरेलू उद्योग को वर्तमान और संभावित पाटन एवं क्षति के बारे में पर्याप्त अपेक्षित सूचना प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में एक लंबी जांच की अवधि को उपयुक्त माना गया था क्योंकि 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित था। वर्तमान क्षति और तथाकथित पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक लंबी अवधि अधिक उपयुक्त होगी।

ड. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, ब्राजील और रूस के मामले को छोड़कर संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन काफी है। चीन, जापान, कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों का पाटन जारी है।

च. चूंकि ब्राजील और रूस से कोई आयात नहीं हुए थे, अतः जांच की अवधि के लिए कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य यह दर्शाते हैं कि ब्राजील और रूस से तीसरे देशों को निर्यात कीमतें उन संबद्ध देशों की निर्यात कीमतों से भी कम थीं, जिन्होंने भारत को निर्यात किया है। अतः, यदि शुल्क वापस ले लिए जाते हैं तो ब्राजील और रूस से पाटन के बार-बार होने की संभावना है।

छ. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित के मद्देनजर वास्तविक क्षति हुई है:

- (i) संबद्ध देशों से पाटन आयातों की मात्रा काफी रही है।
- (ii) यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री दोनों में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के साथ-साथ मांग में कमी के कारण गिरावट आई जो आधार वर्ष के समान स्तर तक नीचे आ गई, तथापि आयातों की कीमतों में गिरावट से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास हुआ जिससे नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष की तुलना में कम स्तर तक काफी गिरावट आई है।

ज. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित कारणों से क्षति के जारी रहने और उसके बार-बार होने की संभावना है:

- (i) तीसरे देशों के लिए संबद्ध देशों की कीमतें भारत में उनकी कीमतों से कम हैं जो यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है तो ऐसे निर्यातों को भारत में भेजा जा सकता है;
- (ii) संबद्ध देशों के पास संबद्ध देशों में मांग की तुलना में काफी अप्रयुक्त क्षमताएं और अतिरिक्त उत्पादन है;
- (iii) संबद्ध देशों से निर्यातों को तीसरे देशों से बड़ी संख्या में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ता है जो मौजूदा अधिशेष उत्पादन का निर्यात करने तथा उनकी अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उनकी संभावना को सीमित करते हैं।
- (iv) अप्रयुक्त क्षमताओं और अधिशेष उत्पादन को मौजूदा शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत को निर्यात करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है
- (v) संबद्ध वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। फरवरी 2021।
- (vi) वैश्विक इस्पात कीमतों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति दर्शाती है कि इस्पात की कीमतें प्रकृति में चक्रीय हैं और वैश्विक इस्पात कीमतों में गिरावट होने पर कम कीमत पर आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

झ. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में एकाधिकार या अल्पाधिकार की स्थिति पैदा नहीं होगी।

199. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है और आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी उपाय जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

## त. सिफारिशें

200. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के सभी पहलुओं और पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क तथा पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की

संभावना की निर्णायक समीक्षा शुरू करने और निर्णायक समीक्षा करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना आवश्यक है।

201. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण, कोरिया गणराज्य और जापान के उत्पादकों/निर्यातकों ने मूल जांच में भाग लिया था और अन्य देशों से कोई प्रतिभागिता नहीं थी। तथापि, चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है, परन्तु इंडोनेशिया के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया है। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार शुल्क तालिका को नए सिरे से निर्धारित करना उपयुक्त मानते हैं।
202. प्राधिकारी इस संबंध में केंद्र सरकार जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं। पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित सामानों के पहुंच मूल्य और नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बीच अंतर के रूप में सिफारिश की जाती है, बशर्ते कि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाये गये मूल्य से कम हो। यदि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है, तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर के अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा।

### शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	संबद्ध सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7208, 7211, 7225 और 7226	मिमी तक 2100 25 की चौड़ाई और मिमी तक की मोटाई की कॉइलों में अलॉय अथवा नॉनअलॉय स्टील - के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हुंडई स्टील कंपनी	478	मी. टन	अमे. डॉ.
2.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	पोसको	489	मी. टन	अमे. डॉ.
3.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई अन्य	489	मी. टन	अमे. डॉ.
4.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अधीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
5.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	जेएफई स्टील कारपोरेशन	489	मी. टन	अमे. डॉ.

6.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	निप्पॉन स्टील कारपोरेशन	489	मी. टन	अमे. डॉ.
7.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	क्रम सं. 6 और 7 को छोड़कर कोई अन्य	489	मी. टन	अमे. डॉ.
8.	-वही-	-वही-	पाटनरोध्री शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
9.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
10.	-वही-	-वही-	पाटनरोध्री शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
11.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
12.	-वही-	-वही-	पाटनरोध्री शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
13.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
14.	-वही-	-वही-	पाटनरोध्री शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
15.	-वही-	-वही-	ब्राजील	ब्राजील सहित कोई भी देश	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.
16.	-वही-	-वही-	पाटनरोध्री शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	ब्राजील	कोई भी	489	मी. टन	अमे. डॉ.

क्रम सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	संबद्ध सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7208, 7211, 7225 और 7226	मिमी तक की 4950 150 चौड़ाई और मिमी तक की मोटाई के 10 कॉइलरहित -अलॉय अथवा नॉन अलॉय स्टील के हॉट फ्लैट उत्पाद रोल्ड सामान्य रूप से) शीट्स और प्लेटों के (रूप में जाने जाते हैं)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हुंडई स्टील कंपनी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
2.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	पोसको	561	मी. टन	अमे. डॉ.
3.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई अन्य	561	मी. टन	अमे. डॉ.
4.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
5.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	जेएफई स्टील कारपोरेशन	561	मी. टन	अमे. डॉ.
6.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	निप्पॉन स्टील कारपोरेशन	561	मी. टन	अमे. डॉ.
7.	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	क्रम सं. 6 और 7 को छोड़कर कोई अन्य	561	मी. टन	अमे. डॉ.
8.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
9.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
10.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के	चीन जन. गण.	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.



			अलावा कोई भी देश					
11.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
12.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
13.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पीटी क्राकाटाऊ पोसको	561	मी. टन	अमे. डॉ.
14.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	क्रम सं. 13 को छोड़कर कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
15.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
16.	-वही-	-वही-	ब्राजील	ब्राजील सहित कोई भी देश	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.
17.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन आने वाले देशों के अलावा कोई भी देश	ब्राजील	कोई भी	561	मी. टन	अमे. डॉ.

203. उपर्युक्त शुल्क तालिका में कॉलम संख्या 3 में सामानों के विवरण में निम्नलिखित के आयात शामिल नहीं हैं:

क. स्टेनलेस स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद।

ख. स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड होते हैं।

ग. स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद अन्यथा प्लेटेड अथवा जिंक से कोटेड।

घ. क्लैडेड स्टील।

#### य. आगे की प्रक्रिया

204. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**NOTIFICATION**  
**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 14th September, 2021

**Case No. (SSR) 05/2021**

**Subject : Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of “Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel” from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia.**

**F. No. 7/5/2021-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. The Authority initiated the original investigation concerning imports of ‘Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel’ originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia vide Notification No. 14/9/2016-DGAD dated 11<sup>th</sup> April 2016. The Designated Authority recommended provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 1<sup>st</sup> August 2016, which was imposed vide Notification No. 44/2016- Customs (ADD), dated 8th August 2016. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/9/2016-DGAD dated 10<sup>th</sup> April 2017 recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty (ADD) on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia. Definitive anti-dumping duties were imposed vide Notification No. 17/2017-Customs (ADD) dated 11<sup>th</sup> May, 2017 (as amended by Corrigendum dated 16<sup>th</sup> May 2017).
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

*“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”*

3. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And whereas, in terms of above provisions, Indian Steel Association (hereinafter also referred to as the “Applicant” or “Petitioner”) on behalf of Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants” or “Applicant companies” or “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty (ADD) imposed on imports of ‘Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel’ (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia (“subject countries”). The Applicants provided the prescribed information in the Application.

5. The Applicant sought continuation of the Anti-dumping duty (ADD) against imports of "Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel" from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent continuation of material injury to the Domestic Industry as well as a likelihood of recurrence of material injury.
6. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification no.7/5/2021-DGTR dated 31<sup>st</sup> March, 2021 to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
7. Pending conclusion of the investigation, the anti-dumping duties were extended up to and inclusive of 15<sup>th</sup> December 2021 vide Notification No. 36/2021-Customs (ADD) dated 29<sup>th</sup> June, 2021.
8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No.14/9/2016-DGAD dated 10<sup>th</sup> April 2017 which had recommended the imposition of ADD on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

## **B. PROCEDURE**

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The Authority vide Notification no.7/5/2021-DGTR dated 31<sup>st</sup> March, 2021 issued a public notice in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning anti-dumping duty imposed on imports of subject goods from subject countries.
  - ii. In accordance with rule 6(2) of the AD Rules, the Authority forwarded a copy of the initiation notification dated 31<sup>st</sup> March, 2021, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
  - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
  - v. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 3<sup>rd</sup> May, 2021, the time was extended up to 20<sup>th</sup> May, 2021. Vide communication dated 17<sup>th</sup> May, 2021, the time was further extended up to 3<sup>rd</sup> June, 2021.
  - vi. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - i. Rizhao Steel Holding Group Co Ltd
    - ii. Baotou Iron and Steel Group Jiangsu Shagang Group Company Limited
    - iii. Angang Steel Company
    - iv. Nanjing Iron and Steel
    - v. Wuhan Iron and Steel
    - vi. Zhangjiagang Hongchang Steel Plate Co. Ltd

- vii. Jiangsu Shagang International Trade Co
  - viii. Nanjing Iron and Steel Group International Trade Co. Ltd.
  - ix. Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co. Ltd
  - x. Wuyang Iron & Steel Co. Ltd
  - xi. Nippon Sumitomo
  - xii. JFE Steel Corporation
  - xiii. Mitsui & Co. Ltd.
  - xiv. Sumitomo Corporation
  - xv. Kanematsu Corporation Ltd.
  - xvi. Toyota Tshusho Corporation
  - xvii. Metal One Corporation
  - xviii. POSCO
  - xix. Dongkuk Steel Mill Col ltd
  - xx. Samwoo Co. Ltd.
  - xxi. P & A corporation
  - xxii. GS Global Corp
  - xxiii. POSCO Daewoo Corporation
  - xxiv. Severstal
  - xxv. EVRAZ
  - xxvi. Arcelor Mittal
  - xxvii. PT Krakatau POSCO, Indonesia
- vii. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
- a) POSCO, Korea RP
  - b) PT Krakatau POSCO
  - c) Taechang Steel Co., Ltd.
  - d) Winsteel Co., Ltd.
  - e) PT. POSCO Indonesia Inti, Indonesia-Exporter
  - f) PT. POSCO International Indonesia,
  - g) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Indonesia-Exporter
  - h) Hyosung TNC Corporation
  - i) Hyosung Japan Co., Ltd
  - j) POSCO Asia Company Limited
  - k) POSCO International Corp
  - l) Samsung C&T Corporation
  - m) GS Global Corp
  - n) GS Global Singapore Pte. Ltd
  - o) Nippon Steel Corporation
  - p) JFE Steel Corporation
  - q) Kobe Steel Ltd

- r) Honda Trading Corporation
- s) JFE Shoji Corporation
- t) Kanematsu Corporation
- u) Marubeni-Itochu Steel Inc.
- v) Metal One Corporation
- w) Mitsui & Co., Ltd.
- x) Nippon Steel Trading Corporation
- y) Hitachi Zosen Corporation
- z) IHI Corporation
- aa) Nissan Trading Co., Ltd.
- bb) Ohmi Industries, Ltd.
- cc) Sato Shoji Corporation
- dd) Sumitomo Corporation
- ee) Sumitomo Corporation Global Metals Co. Ltd
- ff) Toyota Tsusho Corporation
- gg) Tetsusho Kayaba Corporation
- hh) Hyundai Steel Company
- ii) Hyundai Corporation
- jj) Samsung C&T Corporation
- kk) SK Networks Co. Ltd
- ll) GS Global Corporation
- mm) Hanwa Co., Ltd.

viii. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

- i. Arcelor Neel Tailored Blanks Private Limited
- ii. Bharat Heavy Electricals Limited
- iii. Bhilai Engineering Corporation Ltd.
- iv. C.R.I. Pumps Private Limited
- v. DENIS PLAST LIMITED
- vi. Fine Forge Limited
- vii. Flakt (India) Limited
- viii. Gamesa Wind Turbines Pvt. Ltd
- ix. Hindustan Construction Co. Ltd
- x. Kalpataru Power Transmission Ltd.
- xi. Larsen & Toubro Ltd
- xii. Llyods Steel Industries Ltd
- xiii. Maruti Suzuki India Ltd
- xiv. POSCO Electrical Steel India Pvt. Ltd.
- xv. Superior Steel Industries
- xvi. Tranter India Private Ltd

- xvii. TRF Limited
- xviii. Sungreen Ventilation Systems (P) Limited
- xix. Metal Shine Roofing
- xx. Oriental Metal India Pvt. Ltd .
- xxi. M.K.K Metal Sections Pvt. Ltd
- xxii. Whirlpool of India Ltd.
- xxiii. Hyundai Steel India Limited
- xxiv. Highly Electrical Appliances India Pvt. Ltd.
- xxv. Ferrum Extreme Engineering Pvt. Ltd
- xxvi. Rajasthan Prime Steel Processing Center Pvt. Ltd.
- xxvii. Hyundai Motors India Ltd
- xxviii. Mobis India Limited
- xxix. TI Metal Forming
- xxx. Myuong Shin India Automotove Private Ltd.
- xxxi. KwangJin India Autosystems Pvt. Ltd
- xxxii. Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd.
- xxxiii. Welspun Corp Limited
- xxxiv. The Bombay Iron Merchants' Association
- xxxv. Federation of Association of Maharashtra (FAM)
- xxxvi. All India Induction Furnaces Association
- xxxvii. ASSOCHAM
- xxxviii. Confederation of Indian Industry
- xxxix. Indian Chamber of Commerce
  - xl. Auto Component Manufacturers Association (ACMA)
  - xli. Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
  - xlii. Indian Construction Equipment Manufacturers Association (ICEMA)
  - xliii. Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association (IEEMA)
  - xliv. Process Plant and Machinery Association of India (PPMAI)
  - xl. Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India (CORSMA)
- ix. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:
  - a) POSCO-India Pune Processing Centre Pvt Ltd
  - b) POSCO-India Processing Centre Pvt Ltd
  - c) POSCO-Maharashtra Steel Private Limited
  - d) Honda Trading Corporation India Pvt Ltd
  - e) Rajasthan Prime steel Processing Center Pvt Ltd
  - f) JFE Shoji India Private Limited
  - g) Marubeni-Itochu Steel India Private Limited
  - h) Metal One Corporation India Pvt. Ltd.
  - i) Nippon Steel Pipe India Private Ltd.

- j) TT Steel Service India Pvt. Ltd.
  - k) Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association (CEAMA)
  - l) POS Hyundai Steel Mfg. (I) Pvt
  - m) Hyundai Steel Anantapur Private Limited
  - n) Hyundai Steel India Pvt. Ltd
  - o) Hyundai Motor India Limited
  - p) Hyundai Steel Pipe India Pvt. Ltd
  - q) Steel Users Federation of India (SUFI)
  - r) Society of Indian Automobile Manufacturers, (SIAM)
  - s) Theis Precision Steel India Private Limited
  - t) SKODA AUTO Volkswagen India Pvt. Ltd.
  - u) Ratnamani Metals & Tubes Ltd.
  - v) Maruti Suzuki India Limited
  - w) Ysi Automotive Pvt. Ltd.
  - x) Hwashin AutoIndia Pvt. Ltd.
  - y) Renault Nissan Auto India Pvy. Ltd.
  - z) Indian Pipe Manufacturers Association
  - aa) The Japan Iron and Steel Federation
  - bb) Myoung Shin India Automotive Pvt. Ltd.
  - cc) PHA India Pvt. Ltd.
- x. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2019 to 30th September 2020 (18 months). The injury examination period has been considered as the period from April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019, and POI.
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis.
- xii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 2<sup>nd</sup> August, 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- xiii. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- xiv. Further information was sought from the Applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xv. The non-injurious price (hereinafter referred to as "NIP") based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xvi. Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/dimensions, the Authority after taking into account views of interested parties, and in line with approach made in the original investigations, finalized Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN-to-PCN comparison for computing the dumping margin, and injury margin. Accordingly, the Authority has made PCN to PCN comparison for the purpose of computing dumping margins, and injury margins in the present review investigation.
- xvii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would form the basis of the final findings was issued to the interested parties on 03.09.2021 and the interested parties were allowed time upto 09.09.2021 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings' notification.
- xviii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this Final Findings.
- xix. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- xx. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this Final Findings on the basis of the facts available.
- xxii. '\*\*\*' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= 73.17.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

10. The Product Under Consideration is "Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel" which was defined in the original investigation was as follows:

*"Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm and Hot-rolled flat products of 10 alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm".*

*The PUC covers products which are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or nonprime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge or "milled" edge or "sheared" edge or "laser-cut" edge or "gas-cut" edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit, normalized or un-normalized, ultrasonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be "as-rolled" or "thermo-mechanically rolled" or "thermo-mechanically controlled rolled" or "controlled rolled" or "normalized rolled" or "normalized" or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. The PUC*



*covers Hot Rolled flat sheets and plates of alloy or non-alloy steel, whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process. The PUC includes sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut sheared from hot rolled coils. The following are not included in the scope of the product under consideration:*

- 1. Hot-rolled flat products of stainless steel.*
  - 2. Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc.*
  - 3. Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc.*
  - 4. Cladded steel. ”*
11. Being a sunset review, the Authority adopted the abovementioned scope of the PUC at the time of initiation of the investigation.
  12. The Authority notes that the Domestic Industry did not propose any PCN methodology in the sunset review petition. However, it was noted that in the original investigation, PCN methodology was proposed by the domestic industry, and the Authority determined Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to-PCN comparison for computing the dumping margin. Therefore, the Authority proposed to adopt the same PCNs described in the original investigation for the present sunset review, and informed the interested parties to offer their comments on the PCN methodology by 14<sup>th</sup> of April.
  13. Based on the comments received from interested parties, the Authority has adopted the following Product Control Number (PCN) for the PUC for fair comparison and requested the interested parties to file questionnaire response:

PCN for Hot Rolled Flat Steel Products				
S. No.	Attributes	No. of Digits	Description	Code
1	Product Form	1	Coil	C
			Cut to length-Slit, Sheet and Plates	L
			Plate Mill Plate	P
2	Quality	4	Cold rolling/Galvanizing Quality	Q01Q
			Pipe and Tube Quality	Q02Q
			High tensile including HSLA	Q03Q
			High Strength Structural Steel(YS 350 Mpa & above)	Q04Q
			Structural Steel (YS below 350Mpa)	Q05Q
			Chequered Quality	Q06Q
			Drawing/forming/flanging quality Steel	Q07Q
			API grade X52 and above quality Steel	Q08Q
			API grade below X52 quality steel	Q09Q
			Quenched/Tempered Quality	Q10Q
			Corrosion Resistant Steel Quality	Q11Q
			Boiler/Pressure Vessel Quality	Q12Q
			Ship Building Quality	Q13Q
			LPG Cylinder Quality	Q14Q
			Medium/High Carbon Steel Quality	Q15Q
			Silicon Electrical Steel	Q16Q
			Other Qualities not covered above	Q17Q

3	<b>Thickness</b>	1	Upto 1.6 mm	T
			More than 1.6 mm upto 2mm	U
			More than 2 mm upto 10 mm	V
			More than 10 mm upto 25 mm	W
			More than 25 mm upto 40 mm	X
			More than 40 mm upto 100 mm	Y
			More than 100 mm upto 150 mm	Z
4	<b>Width</b>	1	Upto 600mm	1
			More than 600mm upto 1500mm	2
			More than 1500mm upto 2500mm	3
			More than 2500mm upto 3000mm	4
			More than 3000mm upto 4950mm	5
5	<b>Longitudinal Edges</b>	2	As rolled	EB
			Sheared/Trimmed/Milled/Gas-Cut etc.	ED
6	<b>Surface Treatment/Surface Preparation</b>	1	Pickled	H
			Sand blasted/shot blasted	I
			Painted	J
			No surface treatment/no surface preparation	K
7	<b>Heat Treatment</b>	1	Un-Normalized	8
			Normalizing	9
Example: A plate mill plate of chequered quality, 80 mm thick having width 750 mm with sheared edges in pickled form having unnormalized heat treatment Product PCN will be (1 Idigit): PQ06QY2EDH8				

14. Interested parties i.e. cooperating producers and exporters and the domestic industry provided information based on the said PCN structure prescribed by the authority.
15. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive, oil and gas line pipes/exploration, cold-rolling, pipe and tube manufacturing, infrastructure and construction, general engineering & fabrication, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, capital goods including plant and process equipment for cement, fertilizer, refineries etc.
16. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7208, 7211, 7225 and 7226. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The Designated Authority analyzed the transaction-wise DGCIS import data to arrive at the import statistics for the PUC by removing the items that are not part of the product scope.
17. While PCN wise breakdown of data of individual companies was available from the interested parties, the official DGCIS statistics could not be converted in terms of PCN as the description given in the DGCIS data was not sufficient enough to determine the PCN for an overwhelmingly large number of import transactions.

### **C.1. Submissions of the domestic industry**

18. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:
  - a. The product manufactured by domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.

- b. Consumers use the product manufactured by the domestic industry and the producers in the subject countries interchangeably.
- c. In a sunset review, the scope of the product under consideration shall remain the same as determined in the original investigation.
- d. The grades produced by PTKP and NSC are produced by the Domestic Industry also. The evidence in this regard has been submitted separately.
- e. The domestic industry has supplied grades viz. EN S-355/IS E-350 in the domestic market. Specifically, \*\*\*, has been supplying the above said grades during the entire injury analysis period and the evidence in this regard has been submitted separately.
- f. Nippon Steel Corporation (“NSC”) has alleged that certain grades produced by it are not sold by Domestic Industry as they are not listed in their brochure. Furthermore, NSC has not given sufficient technical parameters of the various grades to allow for comparison with grades produced by Domestic Industry. Exhibit does not clearly highlight technical differences between product type sought to be excluded and like article produced by domestic industry. Also, quality is not a criterion for exclusion of any product type in an anti-dumping investigation. The domestic industry supplies all grades of steel for all thicknesses which fall under scope of PUC and same can be verified.
- g. In *Anti-dumping investigation concerning imports of Aluminium foil 80 microns and below originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Indonesia* (F.No. 06/21/2020-DGTR), *Nylon Multi Filament Yarn originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand* (F.No. 6/11/2019-DGTR) and sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of ‘Fluor elastomer’ (FKM) originating in or exported from China PR (F. No. 7/03/2020-DGTR), the Authority held that quality or minor variations in specifications were not relevant criterion for exclusion of a product under consideration. The Hon’ble CESTAT in *Dsm Idemitsu Limited vs Designated Authority* also held that difference in quality is not a relevant parameter to ascertain ‘likeness’ which was relied upon by Authority in *Anti-dumping investigation concerning imports of “Black Toner in powder form” originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan* to hold that difference in quality is not a criterion.

## C.2. Submissions of other interested parties

19. The following submissions were made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration:
  - i. AMNS is not to be regarded as part of the Domestic industry (DI) in the present investigation and the grades of PUC exclusively manufactured by them are to be excluded from the scope of the PUC.
  - ii. Likeness of products should be assessed by taking into account end uses, consumer preferences, product properties, nature and quality amongst others as stated by the WTO Appellate Body in *Japan – Alcoholic Beverages*, *Canada- Periodicals*, and by WTO Panel in *Indonesia – Autos* and 1970 Report of the Working Party on Border Tax Adjustment)
  - iii. Nippon Steel Corporation (“NSC”) produces various grades of the PUC which are not produced by the DI or commercially or technically substitutable with the grades produced by the DI. That grade of NSC must be excluded from the scope of PUC. Prior AD practice, the DGTR SOP and the Authorities findings confirm the same.
  - iv. There are several findings made by the authority where the DGTR excluded certain grades from the scope of the investigation as the DI had not rebutted the claim of the exporter that they could not produce the said grades.
  - v. Grades of NSC are distinct with distinct properties which are not produced by the DI or cannot be commercially substitutable with the grades produced by the DI. Same can be inferred from product brochures of the DI and publicly available information.

- vi. AMNS cannot be included in the DI and consequently any grades of PUC manufactured exclusively by them to the exclusion of JSW and SAIL must be excluded from the scope of the PUC.
- vii. There are various product grades manufactured and exported by PTKP to India which the DI does not produce or sell any alternate that may be commercially or technically substitutable. The same has been observed by the authority in many of its findings. These cannot be included in the scope of the PUC.
- viii. The likeness of the imported products by taking into account the end uses; consumer preferences; product properties, nature and quality, amongst others, and accordingly exclude the grades that are not manufactured by the DI.
- ix. Specialty Grade of dual spec HR plates conforming to EN S-355 /IS E-350 must be excluded from the scope of this investigation, as the DI does not manufacture products of comparable quality. Specialty grade plates exported to India by PTKP are produced wholly depending on Indian consumers preferences and requirements. HR Plates manufactured by the respondent are far higher in their technical superiority than what is prescribed in European and Indian Standards (EN/IS Specification) which merely indicates threshold requirements. These specifications and test results are described in every Mill Test certificate provided to Indian Consumers who placed requests according to different end uses. Specialty grades which are dual certified in EN/IS a with special characteristics are not like articles compared to general hot-rolled coils in the Indian market.

### **C.3. Examination by the Authority**

- 20. Since the present investigation is a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Nevertheless, the Authority has examined the claims made by certain interested parties seeking exclusion of certain grades from the scope of the PUC.
- 21. PT. Krakatau-POSCO, Indonesia has sought exclusion of HR Steel not in coil EN S-355 /IS E-350 grades as the domestic industry does not have the capability to produce the same and are far higher in their technical superiority than what is prescribed in European and Indian Standards (EN/IS Specification). Nippon Steel Corporation has sought an exclusion of various grades produced by it as the same cannot be produced by the DI and is not commercially substitutable with the grades produced by the DI. From the information submitted by the domestic industry, the Authority finds that the domestic industry is producing grades EN S-355/IS E 350. Therefore, the Authority finds no reason to exclude these two grades.
- 22. It has been submitted by producer and exporter from Japan i.e. M.s NSC, that the domestic industry does not produce those grades covered in the product scope; ii) the domestic industry does manufacture certain grades but the quality is not suitable; and iii) for certain grades, the domestic industry does not have customer's approval. The domestic industry has filed a detailed response addressing the claims of these interested parties.
- 23. To examine the PUC exclusion related issues in an objective manner, the Authority examined the PCNs exported by NSC and those manufactured by the domestic industry during the POI. From the detailed examination of the information, the Authority found that the domestic industry either manufactured exactly matching PCN or a closely resembling PCN for each PCN manufactured by NSC. In view of this, the Authority proposes that no exclusions are warranted from the product scope.
- 24. The Authority verified that the domestic industry is manufacturing all grades for which it got orders, and has also supplied them to the users in India. No evidence has been furnished by any interested party which establishes that they tried procuring any particular grade from the Domestic Industry against which exclusion has been sought by the producers and exporters in the subject countries but the Domestic Industry was unable to supply the same.
- 25. In so far as concerns regarding quality are concerned, the Authority notes that difference in quality is not a relevant parameter for exclusion of an article in an anti-dumping investigation as held in a number of investigations including (a) Anti-dumping investigation concerning imports of

“Black Toner in powder form” originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan (F. NO. 6/6/2020-DGTR) and (b) Anti-dumping investigation on the import of Nylon Multi Filament Yarn originating in or exported from China PR, Korea RP, Taiwan and Thailand (F.No. 6/11/2019-DGTR). The Authority also notes that the aspect of quality not being a factor for exclusion of a product from the scope of ‘like article’ has been held by the Hon’ble CESTAT in DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority in which it was held that *“The plea of the appellants’ counsel is not convincing since he did not adduce any evidence technical literature with reference to process of manufacture to show that product manufactured by the domestic manufacturers was different from the goods exported into India. He failed to substantiate that they are not similar and interchangeable except stating that they were of different grades. Difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing ‘that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles’. We do not find any valid reason to disturb the findings given by the Designated Authority on this issue”*

26. Therefore, the Authority finds that no case has been made out by any of the interested parties for grant of any exclusion from the scope of the product under investigation. Accordingly, the Authority confirms the scope of the product under consideration as defined in the final findings of the original investigation, and also as mentioned in the subject review investigation which is reproduced below:

*“Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm and Hot-rolled flat products of 10 alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm”.*

*The PUC covers products which are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or nonprime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge or “milled” edge or “sheared” edge or “laser-cut” edge or “gas-cut” edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit, normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be “as-rolled” or “thermo-mechanically rolled” or “thermo-mechanically controlled rolled” or “controlled rolled” or “normalized rolled” or “normalized” or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. The PUC covers Hot Rolled flat sheets and plates of alloy or non-alloy steel, whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process. The PUC includes sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils.*

*The following are not included in the scope of the product under consideration:*

- 1. Hot-rolled flat products of stainless steel.*
- 2. Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc.*
- 3. Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc.*
- 4. Cladded steel.”*

27. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject countries in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially

substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

## **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

### **D.1. Submissions by the domestic industry**

28. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
  - a) The Applicant Indian Steel Association on behalf of Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited and Arcelor Mittal Nippon Steel India Limited constitute major proportion of total Indian production for the subject goods in India.
  - b) JSW had imported miniscule quantity of the PUC – [\*\*\*] MT i.e. \*\*\*% of JSW's total production of the PUC.
  - c) AMNS, which became an entity related to Arcelor Mittal and Nippon Steel with effect from 16th December 2019 had imported a very small quantity of PUC. Such small quantities do not change the characteristics of the two entities from being a domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. There is nothing to suggest that AMNS has changed its policy from that of a domestic producer of the subject goods to that of an importer/trader. AMNS has not contributed to dumping from its related entity - Nippon Steel. Imports made by AMNS were negligible in quantity as it is less than (i) [\*\*\*%] of its own production, (ii) [1%] of total imports into India, (iii) [\*\*\*%] of total production of domestic industry, and (iv) [\*\*\*%] of total Indian production. Focus and area of operation of AMNS continues to be manufacture of the subject goods and not indulge in trading of subject goods.
  - d) AMNS, is related to Arcelor Mittal and Nippon Steel with effect from 16<sup>th</sup> December 2019. M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan ("NSSMC") has no direct shareholding in AMNS but is a minority stakeholder in an intermediate holding company separated by several intervening independent corporate enterprises. AMNS is a wholly owned subsidiary of ArcelorMittal India Pvt. Ltd., a company incorporated under the laws of India. ArcelorMittal India Pvt. Ltd. itself is a wholly owned subsidiary of Oakey Holdings BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands. NSSMC holds minority stake of 40% in the parent company of Oakey Holdings BV i.e. AMNS Luxembourg Holding, in which the majority stake is held by AM Belval & Differdange, Luxembourg. AMNS is an independent, professionally managed company and does not reflect the individual interests of its shareholders. As a domestic producer, the very fact that it has come together with other domestic producers to seek the present sunset review evidences that it is not acting in a manner different from other domestic producers.
  - e) AMNS has not imported any product from NSSMC during the PUC. AMNS does not have any contracts with NSSMC or its subsidiaries/affiliates for procurement or sale of any products. AMNS's procurement, production and sales policy does not display any discordant behaviour on account of NSSMC holding shares in an intermediate holding company."
  - f) The word 'may' in Rule 2(b) confers a discretion to include a domestic producer within the ambit of domestic industry notwithstanding its relation to producer or exporter of the subject goods in subject countries if focus of domestic producer has continued to remain on domestic production.
  - g) Nothing to suggest that AMNS has changed its policy from domestic producer to that of importer/trader. Furthermore, neither has AMNS contributed to dumping of the subject goods from its related entity - Nippon Steel in any manner as the imports made by it were not from it but from Korea.
  - h) There is nothing to suggest that AMNS has changed its policy from that of a domestic producer of the subject goods to that of an importer/trader. AMNS has not contributed to dumping from its related entity - Nippon Steel. Imports made by AMNS were negligible in quantity as it is less than (i) 0.2% of its own production, (ii) 1% of total imports into India,

(iii) 0.1% of total production of domestic industry, and (iv) 0.02% of total Indian production. Focus and area of operation of AMNS continues to be manufacture of the subject goods and not indulge in trading of subject goods.

- i) As per test in final findings dated 10 April 2012 in *Anti-dumping investigation concerning imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia*, there is nothing on record that imports made by AMNS provoked or contributed to fall in prices or that it was shielded from effect of dumping or where they benefited unduly from them. Imports made by AMNS were negligible and could not have provoked or contributed to a fall in prices on the market or shield AMNS from their effects, or benefit AMNS unduly. The relationship with Nippon Steel has in no way affected the principal activity of AMNS which is producing the subject goods in India and AMNS has not reduced its own production activity or turned to trading. Neither has the relationship with Nippon Steel led to any imports by AMNS from it. Nippon steel by virtue of its 40% shareholding in Oakey Holdings BV cannot influence AMNS to change its business and resort to trading of the subject goods. Therefore, AMNS shall not be excluded from the scope of the domestic industry.
- j) Even if AMNS were to be excluded, the remaining domestic producers viz. JSW Limited and SAIL would constitute 35-45% of the production of the subject goods in India which is more than the threshold of 25% mentioned in Rule 5(3)(a) and a major proportion under Rule 2(b) which need not be more than 50%. WTO Panel report in *WT/DS440/R - China - Anti-Dumping And Countervailing Duties On Certain Automobiles From The United States* and *Lubrizol (India) Pvt. Ltd. v. Designated Authority* relied upon where it was held that it was not necessary to account for more than 50% domestic production to constitute a major proportion within meaning of Rule 2(b) of the AD Rules 1995. Share in total production by JSW Steel Ltd and SAIL is sufficiently important, serious and significant to constitute a major proportion of total domestic production and be considered as Domestic Industry.
- k) Furthermore, with supporters of the present application viz. Tata Steel Ltd. and Tata Steel BSL Ltd., the support towards the application has been made by applicant who constitute more than 50% of the domestic production.

#### **D.2. Submissions by other interested parties**

29. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing.

- i. AMNS is an importer of the PUC themselves and are also related to the producer of the PUC, i.e., Nippon Steel from Japan which is one of the subject countries. AMNS imported \*\*\* MT of PUC which is not a small number and must have been sold to user industry and not just for testing/sampling purpose.
- ii. AMNS is a 60:40 joint venture between ArcelorMittal and Nippon Steel Corporation. Nippon Steel Corporation that holds a 40% stake in AMNS is based in Japan which is a subject country and a known exporter of the PUC to India. In the final findings Anti-dumping investigation concerning imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia, it was held that the investigating authority can exclude a related producer where the related parties (a) provoked or contributed to a fall in prices on the market (b) are shielded from the effects, or (c) where they benefited unduly from them.
- iii. Nippon Steel Corporation by virtue of 40% shareholding can block any special resolution and thus has significant powers with respect to the overall operation of AMNS. AMNS became a subsidiary of Nippon Steel from December 2019 which is part of the POI. Thus, AMNS which had not imported PUC during the injury period prior to POI, imported during the POI. This indicates that the approach of AMNS is no longer DI but also an importer. It is requested that the Authority to seek disclosure of information from DI regarding nature of transactions between AMNS and Nippon Steel Corporation Japan. Share of the DI will drop below 50% given the exclusion of AMNS from the scope of the DI and the remaining producers would not satisfy the 'major proportion' requirement.

- iv. Support from Tata and Tata BSL is liable to be rejected as both these companies have not provided information to register their support under Trade Notice No. 13/2018. Rejection of Tata, Tata BSL and AMNS would result in the share of producers declining below 50%. As the current application would not be supported by producers constituting 50% of the total production of the DI, supporting producers and other domestic producers, the SSR is to be terminated.
- v. The Petitioner relies upon the report of the Joint Plant committee of the ministry of steel to a certain share of participating companies in the total production of DI but did not provide a non-confidential version of this claiming business sensitive information. Given that this data is publicly available, the DI should be directed to furnish the same to the respondent to enable the respondent to be afforded an opportunity of a fair rebuttal of the same.
- vi. As per the petition, imports made by JSW and AMNS is less than 1% in total imports into India, total production of concerned producer and total Indian production. DGTR must verify these claims. DGTR should examine if the imports made by AMNS and JSW are de minimis when compared to imports from subject countries as a whole and each subject country. If these imports are more than de minimis, they cannot be the constituents of the Domestic Industry and, cannot attribute injury, if any, on account of their own imports to other imports from subject countries.

### **D.3. Examination by the Authority**

30. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

31. The Application has been filed by the Indian Steel Association on behalf of Steel Authority of India Limited, JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited and supported by Tata and Tata BSL. The Authority notes that the Applicant account for 58% of the total Indian production during the period of investigation. The Authority notes that the production of petitioners along with supporters’ accounts for 79% of the total Indian production.
32. At the time of initiation, the Authority noted the following with respect to imports made by JSW Steel Ltd and ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd as well as the latter’s relationship with Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan:

*“Of the three applicant producers, JSW Steel Ltd and ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd have imported small quantities of the subject goods from the subject countries. As the volumes imported by them are small and their focus and area of operation continue to be manufacture of domestic like articles and not indulge in trading of subject goods, the Authority considers it appropriate to treat them as part of the domestic industry*

*Essar Steel India Ltd. was admitted to corporate insolvency resolution process by way of an Order dated 02.08.2017 passed by the National Company Law Tribunal, Ahmedabad. Pursuant to the procedure established by the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, ArcelorMittal India Pvt. Ltd. became the successful resolution applicant and with effect from 16.12.2019 took over the entire shareholding of the company. Pursuant to issuance of a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies, the name of Essar Steel India Ltd. was changed to ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd. with effect from 08.01.2020. The Company is incorporated in India under the Companies Act, 1956. It is a domestic producer of Hot Rolled Products (both in coil and not-in coil) and Cold Rolled Products and has significant production capacities in India and is in the process of further expansion. M.s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan has no direct shareholding in ArcelorMittal Nippon Steel India Limited but is a minority stakeholder in an intermediate holding company separated by several intervening independent corporate enterprises. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has not imported the subject goods from Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan during the POL ArcelorMittal*



*Nippon Steel India Limited is an independent, professionally managed company and does not reflect the individual interests of its shareholders. As a domestic producer, the very fact that it has come together with other domestic producers to seek the present sunset review evidences that it is not acting in a manner different from other domestic producers. "*

33. A number of interested parties have objected to the inclusion of AMNS within the scope of the domestic industry on the ground that imports made by it are substantial and that its relationship with M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan also disentitles it from being considered as such.
34. To determine whether AMNS is liable to be included within the scope of the domestic industry as it has imported the product under consideration, the Authority examined the imports made by AMNS and found them to be negligible as they account for less than (i) \*\*\*% of the production of AMNS, (ii) 1% of total imports into India, (iii) \*\*\*% of total production of the domestic industry, (iv) \*\*\*% of the total Indian demand. On examination, the Authority finds that such low imports— (a) did not contribute to a fall in prices in the market; (b) did not shield the domestic industry from the effects of dumped imports, or (c) did not confer any undue benefits to the domestic industry. The Authority further notes that the imports made by JSW are also negligible being only \*\*\*% of the total production of JSW.
35. Regarding the relationship of AMNS to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan, the Authority had already noted at the time of initiation of the investigation that M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan has no direct shareholding in ArcelorMittal Nippon Steel India Limited but is a minority stakeholder in an intermediate holding company separated by several intervening independent corporate enterprises. On the basis of information on record, the Authority has also noted that ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has not imported the subject goods from Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan during the POI. No additional facts have been brought to the notice of the Authority which suggest that the relationship to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan has led AMNS to behave differently than a domestic producer of the like article or change its core activity which is production of the domestic like product.
36. Therefore, the Authority has considered both AMNS and JSW as part of the domestic industry and no case has been made out for excluding either of them from the scope of the domestic industry.
37. The Authority also notes that the supporters have filed information in the relevant formats and the same was made available in the public file as well as circulated to the interested parties by the domestic industry.
38. The Authority notes that the applicant on their own and also including the supporters, account for a major proportion of the total domestic production.
39. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submissions by the domestic industry**

40. The following submissions have been made with regard to confidentiality:
  - i. DI has circulated all documents filed by it during the course of the investigation with the interested parties including addendum 2. Vide email dated 28th July 2021 non-confidential versions of the submissions were shared with all interested parties mentioned in the notice of oral hearing dated 14th of July 2021. It has been clearly mentioned that the NCV of Addendum 2 has already been incorporated into the relevant parts of the non-confidential version of the Petition circulated with the interested parties.
  - ii. Non-confidential versions of the application and all other documents filed by the Petitioner were made available to the Authority and the interested parties could have accessed the same at any point of time from the public file maintained by the DGTR. Therefore, the grievance of the Respondents is non-est.

- iii. Supporters to the Application have filed non-confidential versions of their responses.
- iv. The responding exporters have resorted to excessive confidentiality claims which have completely prevented the Petitioners from offering their comments.
- v. Injury statements filed by the domestic industry are invariably either on actual basis or on indexed basis. The comparison of the non-confidential version of the injury parameters by the domestic industry and by the responding producers and exporters will clearly show that the extent of confidentiality claimed by the responding exporters is far higher.
- vi. The domestic industry has provided indexed figures of the parameters showing the trend of injury parameters.
- vii. The exporter has claimed information like product list, channel of distribution, production process, production flowchart, name of raw material, information regarding exports to India, sales of goods of the company, sales price structure, statement showing installed capacity, information related to cost of production, information related to subsidiary, information with regard to exports to third countries etc. Non-confidential version of the questionnaire response is grossly inadequate. The interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose under the Rules. Even information that is publicly available has not been disclosed in the non-confidential version
- viii. The petitioners have filed non-confidential version of the information as per Trade Notice No 10/2018 dated 7th September, 2018

### **E.2. Submissions by other interested parties**

41. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
- i. As may be seen from the final findings of anti-dumping investigation against import of Plain Medium Density Fiber Board originating in or exported from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Ukraine, it is the practice of the DA to disclose the volume of imports of the PUC of the DI to the opposite interested parties. It should be provided with the import data of the PUC imported by AMNS and JSW along with the country from where such imports have taken place, so that it can provide a meaningful response and adequately defend its interest.
  - ii. The Petition does not comply with the requirements of the Trade Notice No. 10/2018 and a number of figures have been provided as a trend instead of actuals.
  - iii. On account of excessive claim of confidentiality by the DI pertaining to the economic and injury indicators, the respondent has been precluded from providing an effective rebuttal to the claims of the DI resulting in violation of the due process rights and principles of natural justice.
  - iv. Domestic Industry has not circulated non-confidential version of Addendum 2 to the Petition. Non-confidential version of questionnaire filed by supporters has not been shared.

### **E.3. Examination by the Authority**

42. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the party's providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

43. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
44. The Authority also notes that the applicant has circulated the non-confidential versions of the petition along with Addendum 2 as well as questionnaire responses filed by the supporters to the petition.
45. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by the domestic industry**

46. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
  - a. No request was made in the application for adopting a PCN methodology for facilitating a fair comparison. Subsequent to the initiation of the investigation, Authority proposed a PCN methodology, obtained comments from interested parties and after considering those comments, finalized the PCN structure and directed the interested parties to provide relevant information in accordance with the PCN structure finalized by the authority. Pursuant to the said directions, domestic industry filed PCN-wise information in the relevant formats.
  - b. Regarding not furnishing minutes of meeting and other documents mentioned in DGTR vide F. No. 14/44/2016-DGAD, it is not clear whether instruction circulated by the are still in operation since the same are not to be found on the website of the DGTR which contains all trade notices and office memorandums which are required to be observed by interested parties. Same must be deemed to have been replaced by instructions issued by DGTR vide Trade Notice No.02/2018 which provides for format for Petition by Domestic Industry and states that *it will supersede all previous instructions or Trade Notices, if any, issued by the Directorate with regard to the petition to be submitted by the Petitioner Domestic Industry*". Therefore, question of following instruction circulated vide F. No. 14/44/2016-DGAD does not arise.
  - c. In so far as DGCIS data is concerned, the product description given in the said data is not sufficient enough to group the same according to the PCN structure. Due to lack of relevant information, imports, in its entirety, could not be classified in terms of the PCN structure. However, PCN wise imports in respect of exports made by the cooperating producers is available the exporters' questionnaire responses filed by them.
  - d. None of the policies listed by the interested parties as beneficial to the Domestic Industry are even remotely helpful in arresting the injurious effect of dumped imports from subject countries.
  - e. Production-Linked incentive scheme for 'speciality steel' is to promote manufacturing of specialty steel grades within the country. The PLI incentive is expected to boost the domestic production of specialty steel. This scheme was not operational during the POI and is expected to be operational from 2022-23.

- f. Import of subject goods from Japan and South Korea enjoy zero-tariff. Because of preferential import tariff on subject goods, domestic industry is faced with inverted duty structure because import of raw material such as coking coal is subject to 2.5% import duty. India has also reduced MFN import tariff on steel to 7.5% from 12.5% from February 2021

### **F.2. Submissions by other interested parties**

47. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a) Imposition of anti-dumping duty (if any) should be made on a reference price basis. This prevents unnecessary penalization on imports which are being made at a price higher than the NIP of the DI and hence, are not harming the DI. An imposition of anti-dumping duty on a reference price basis, adopted in the original investigation, would ensure that the product grade which is imported at par or above the reference price would not attract any anti-dumping duty.
- b) Public interest must be examined comprehensively and completely, and Government of India must not impose anti-dumping measures even if it is determined that the imports have caused the injury.
- c) The DGTR has not provided transaction-wise import data in the same form and manner in which it was taken on record.
- d) The determination of all factors should be made separately for HR in coil and HR not in coil because the original investigation determined dumping and injury margins separately for the same.
- e) The present Petition is not a duly substantiated Petition as it does not provide relevant PCN-wise information. By providing average margin calculations, the methodology utilized in the original investigation has been deviated from without providing any justifiable reasons in the Petition. Therefore, the present initiation on the basis of said Petition should not have taken place. Consequently, the present initiation is bad in law.
- f) DGTR should take into account not only the views from Japanese steel mills but also other stakeholders including user industries and companies in India so that public interests as a whole can be duly reflected.
- g) The domestic industry is now profitable and have increased opportunities to sell within India and the outlook also looks better. The recent trends and strategies in the Indian steel industry such as BIS standards, SIMS, PLI scheme, steel recycling policy indicate that there is no threat of recurrence of injury to the domestic industry if anti-dumping duties are revoked.

### **F.3. Examination by the Authority**

48. The Authority has considered the views of the interested parties at the appropriate places in this Final Findings. In this regard, the Authority notes the following:

- i. As regards the submission that the authority shall recommend duty on a reference price basis, the Authority would take an appropriate decision while arriving at the final findings.
- ii. As regards public interest, the same has been examined in a separate section of this Final Findings.
- iii. As regards, provision of transaction-wise import data to the interested parties, the Authority refers to Trade Notice No.07/2018 and in terms of the same, wherever an interested party has made a request for procurement of import statistics, the Authority has granted approval for the same.
- iv. The product under consideration is 'Hot rolled flat products of alloy and non-alloy steel'. The said product is grouped under two broad categories namely 'in coils' and 'not in coils'. There is no requirement that an injury analysis shall be made for every category of the product separately. In this regard, the Authority notes that 'in-coil' products may be cut and slit into 'not-in coil' products depending upon the requirement. The applicant makes 'in-coil' and 'not-in-coil' products using the same base facilities. Therefore, it is appropriate to determine injury for the 'Hot-rolled flat products of alloy and non-alloy steel' together. The Authority

further notes that no such separate injury examination for HR 'in coil' and 'not in coil' was performed during the original investigation and therefore, the question of segregating such injury analysis does not arise during the sunset review. However, similar to that of the original investigation, Authority has applied a PCN based comparison for the purposes of effecting fair comparison of both injury margin and dumping margin which ensures an apple-to-apple comparison for the cooperating producers and exporters from the subject countries.

- v. With regard to comments made by the other interested parties about the existence of BIS standards, SIMS, PLI scheme, steel recycling policy, the Authority notes that the purpose of the present sunset review is to examine whether discontinuation of duties would lead to a continuation of dumping and material injury to the domestic industry or a recurrence of the same which has to be examined only with reference to impact of dumped imports on the performance of the domestic industry, while ensuring that injury caused by other factors are not attributed to dumping.
- vi. The Authority also notes that the average dumping margin calculations of imports instead of PCN wise information were accepted since while PCN wise breakdown of data of individual companies has been made available by the cooperating producers and exporters, the official DGCIS statistics could not be converted in terms of PCN as the description given in the DGCIS data was not sufficient enough to determine the PCN for an overwhelmingly large number of import transactions.

## **G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

### **G.1. Submissions of the domestic industry**

49. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to the normal value, export price and dumping margin:

- i. Normal value has been constructed for all the subject countries by taking (1) International prices of raw materials (coal and iron ore) i.e. global weighted average import price of these materials into the concerned subject country from 'Trade map' database. (2) Other manufacturing costs have been considered based on the experience of the domestic industry after adjusting labor costs in India to duly reflect the costs prevailing in the subject country based on differences in cost of living between India and the concerned subject country. (3) SGA costs and Finance costs have been considered based on the experience of the domestic industry, (4) A profit margin of 5% has been considered for working out the normal value. Addendum 1 to the Petition filed on 28 March 2021 made it clear that the normal value was calculated in the said manner.
- ii. The petitioner has arrived at export price at ex-factory level. From CIF export price, adjustments have been made regarding (1) Ocean Freight (2) Inland Freight (3) Ocean Insurance (4) Commission (5) Bank Charges (6) Port & Handling Expenses (7) Non-Refundable VAT (In respect of China PR) to arrive at ex-factory export price.
- iii. Interested parties have not indicated why, in the absence of information of price of subject goods in subject countries or any other manner in which the price for these countries could be determined, Normal Value could not have been constructed in the manner done by the Petitioner. In the absence of information which can controvert the normal value calculated by the petitioner, the same shall rightly be considered reliable. Respondents have not been able to controvert the veracity of the adjustments adopted by the petitioner. Therefore, the objection raised with respect thereto are without any merit.
- iv. Dumping margin determined for the subject countries is significant and is a clear indicator of the fact that if anti-dumping duties are revoked, there is every likelihood of continuation of dumping of subject goods into India from the subject countries and continuation or recurrence of injury to the domestic industry.
- v. JFE Steel has not claimed deductions towards Bank charges package charges, and deduction for commissions.

- vi. Nippon Steel has not claimed deductions towards Bank charges package charges and clarified whether any related firm exports PUC to India.
- vii. Honda has domestic sales in Japan and this has to be considered while determining the normal value. It has also not claimed deductions towards bank charges and packages charges
- viii. JFE Shoji has not claimed deductions towards bank and packaging charges.
- ix. Kobe Steel Ltd have not provided any document or submission other than the authorization in Appendix B. Thus, they should be declared as non-cooperative
- x. Even though Hitachi Zosen Corporation has been listed as an interested party, no information has been provided pertaining to this trader. Therefore, they may be declared as non-cooperative

### **G.2. Submissions of other interested parties**

50. The following submissions have been made by other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:
- a) The initiation notification states that the Petitioner has constructed normal for subject countries (which includes Japan) based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs based on experience of the domestic industry after making adjustment to duly reflect labor cost prevailing in the concerned subject country, and (c) a reasonable profit.
  - b) As per the initiation, the Authority has considered a different basis for arriving at normal value than that provided in the Petition. Accordingly, it is evident that the initiation is not based on evidence in the application / Petition. The initiation is therefore in violation of Rule 5 of AD Rules and is bad in law.
  - c) The petitioner has not justified the following as well: any effort to obtain information regarding documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in Brazil, Indonesia, Japan, Korea RP, and Russia, how normal value constructed based on the international price of raw material specifically reflect the cost of production in Japan, how the petitioner's experience is comparable to that of producers in Japan for considered conversion costs, SGA costs and finance costs, based on the experience of the domestic industry.
  - d) No evidence on record as to how Malaysia is an appropriate third country for considering the export price from Japan to an appropriate third country.
  - e) At Page 17 of the Petition various adjustments have been made to the export price, but no justifiable evidence has been provided to support the same.
  - f) It is unlikely that a fair comparison which is unbiased, objective, and even-handed has been made between the normal value and the export price so as to calculate proper dumping margin. Consequently, the alleged dumping margin in the Petition is not based on objective, verifiable, and credible information and therefore, do not constitute evidence of dumping under Rule 5 (2) of the AD Rules and Article 5 (2) of the AD Agreement.

### **G.3. Examination by the Authority**

51. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, where meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*
  - ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);*

(b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

52. At the time of initiation, the Authority determined the normal value by taking the facts which were considered sufficient to initiate the investigation, However, after initiation the determination of normal value has been made after taking into account the responses received from the interested parties.

53. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

#### Korea RP

- i. POSCO
- ii. Hyundai Steel Company
- iii. GS GLOBAL CORPORATION
- iv. HYOSUNG TNC CORPORATION
- v. HYOSUNG JAPAN CO., LTD
- vi. POSCO ASIA COMPANY LIMITED
- vii. POSCO INTERNATIONAL CORP.
- viii. SAMSUNG C&T CORPORATION
- ix. GS GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD
- x. Hyundai Corporation
- xi. SK Networks Co., Ltd.

#### Japan

- i. Nippon Steel Corporation
- ii. JFE Steel Corporation
- iii. Mitsui & Co., Ltd.
- iv. JFE Shoji Corporation
- v. Mitsui & Co., Ltd.
- vi. Honda Trading Corporation
- vii. Honda Trading Corporation
- viii. KANEMATSU CORPORATION
- ix. Marubeni-Itochu Steel Inc.
- x. Metal One Corporation
- xi. NIPPON STEEL TRADING CORPORATION

- xii. NISSAN TRADING CO., LTD.
- xiii. Ohmi Industries, Ltd.
- xiv. Sato Shoji Corporation
- xv. Sumitomo Corporation
- xvi. Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd
- xvii. Toyota Tsusho Corporation
- xviii. Tetsusho Kayaba Corporation

#### Indonesia

- i. PT KRAKATAU-POSCO
- ii. HYOSUNG TNC CORPORATION
- iii. GS GLOBAL CORPORATION
- iv. HYOSUNG JAPAN CO., LTD, JAPAN
- v. POSCO ASIA COMPANY LIMITED
- vi. POSCO INTERNATIONAL CORP.
- vii. SAMSUNG C&T CORPORATION

- 54. None of the producers/exporters of subject goods from Russia, Brazil and China have filed exporter's questionnaire response.
- 55. The Authority devised Product Control Numbers (PCNs) in the present sunset review in order to make a PCN-to-PCN comparison. The Authority has first determined dumping margin for each PCN by comparing the export price and normal value at PCN level. Thereafter, weighted average dumping margin for the PUC as a whole has been determined. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of exactly matching PCN, normal value was constructed either based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits, or based on domestic selling price of closely resembling PCN.
- 56. The Authority has made appropriate adjustments to the export price in those cases where it was noted that the related or unrelated trader involved in the export chain to India or the related importer in India were incurring losses on the sales of PUC.
- 57. Keeping in view the submissions of interested parties, the normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries has been determined as follows.

### G.4. Determination of normal value

#### China PR

#### Market Economy claims for Chinese producers

- 58. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*



*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

59. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since producers/ exporters from China PR have not submitted response to MET/supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.

60. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as are enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR based on (a) international prices of raw materials, (b) consumption norms and conversion costs, SGA and finance costs on the basis of the experience of the domestic industry, and (c) a reasonable profit. The Normal Value so constructed is shown in the Dumping Margin Table below.

#### **G.5. Determination of Export Price**

61. As none of the producers/exporters from China PR has filed questionnaire response, export price from China PR has been determined considering volume and value of imports for the period of investigation as per DGCI&S published data. Further, it is noted that sufficient details are not available in DGCI&S import data to arrive at PCN wise export price. Therefore, the Authority has considered single weighted average export price for determination of dumping margin in case of China PR. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, bank charges and non-refundable VAT. The export price at ex-factory level has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table.

**Japan****(i) JFE Steel Corporation (“JFE”)****Normal Value**

62. It is noted that during the POI, JFE, a producer and exporter of subject good has sold the subject goods in the domestic market to related and unrelated parties. Therefore, the Authority has determined the normal value based upon the total domestic sales.
63. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. All determinations have been made on the basis of PCN as specified by the Authority earlier in the investigations.
64. All profit-making transactions are more than 80%, then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value, and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales or sufficiency test was not met for a particular PCN, normal value was either constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits or based on domestic selling price of closely resembling PCN.
65. JFE has claimed adjustments on account of inland freight, inland insurance, storage cost and credit cost. The Authority has accepted the adjustments after verifications through remote cross check. Accordingly, the weighted average normal value at ex-factory level for JFE has been determined for HR coils and HR not in coils and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**Export Price**

66. JFE filed a questionnaire response along with its related/unrelated trading companies, Mitsui & Co., Ltd, Ohmi Industries Ltd., Toyota Tsusho Corporation, JFE Shoji Corporation, Sato Shoji Corporation, Honda Trading Corporation, Metal One Corporation, and Marubeni-Itochu Steel Inc who exported the subject goods to India manufactured by JFE. Further, JFE has also exported some quantities through other traders (who are traders of JFE's aforementioned traders) who have not filed their questionnaire response with the Designated Authority.
67. However, it is also noted by the authority that the exports to India made through non-cooperative unrelated parties are insignificant in terms of total exports to India.
68. For working out export price of the producer M/s JFE, the Authority has considered the actual export price for chain comprising JFE and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of JFE who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for JFE has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.
69. JFE has claimed adjustments on account of inland freight, inland insurance, storage cost and credit cost and the same have been allowed. Accordingly, the export price has been determined for JFE at ex-factory level for HR Coils and HR not in Coils and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**Nippon Steel Corporation (“NSC”)****Normal Value**

70. It is noted that during the POI, NSC has sold the subject goods in the domestic market to related and unrelated companies. The Authority notes that one related entity i.e., Nippon Steel Trading Corporation has filed its response. It is also noted by the Authority that the domestic sales made to non-cooperative related parties are insignificant in terms of total domestic sales. Therefore, the Authority has determined the normal value based upon the total domestic sales.

71. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods in India. All determinations have been made on the basis of PCN as specified by the Authority earlier in the investigations.
72. If profit making transactions are more than 80%, then the Authority has considered all the transactions in the domestic market and in cases where profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales or sufficiency test was not met for a particular PCN, normal value was either constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits or based on domestic selling price of closely resembling PCN.
73. NSC has claimed adjustments on account of rebate, warranty, credit note, inland freight, inland insurance, storage cost and credit cost. The Authority has accepted all the adjustments. Accordingly, the normal value at ex-factory level for NSC for HR coils and HR not in coils and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

#### **Export Price**

74. NSC filed a questionnaire response along with its related/unrelated trading companies, Nippon Steel Trading Corporation, Kanematsu Corporation, Metal one Corporation, Hanwa Co., Ltd, Marubeni-Itochu Steel Inc, Toyota Tsusho Corporation, Honda Trading Corporation, Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd and Mitsui & Co., Ltd who have exported the subject goods to India. Further, NSC has also exported some quantities through other traders (who are traders of NSC's aforementioned traders) who have not filed their questionnaire response with the Designated Authority.
75. However, it is also noted by the authority that the exports to India made through non-cooperative unrelated parties are insignificant in terms of total exports to India. The export sales of NSSMC through its unrelated/related trading companies are on FOB basis. The export sales of NSSMC through its unrelated/related trading companies are on FOB basis.
76. The export sales of NSC through its unrelated/related trading companies are on FOB basis. NSC has claimed adjustments on account of inland freight, inland insurance, storage cost and credit cost and the same have been allowed. Accordingly, the weighted average export price has been determined for NSC at ex-factory level for HR Coils and for HR not in Coils and the same is shown in the Dumping Margin Table.

#### **Normal Value and Export price for non-cooperating producers and exporters from Japan**

77. The Authority notes that no other producer/exporter from Japan has responded to the Authority in the present investigation. The Authority also notes that M/s. Kobe Steel Ltd participated in the original investigation and the Authority had determined normal value for the said company based on the information furnished by them. However, in this sunset review, Kobe Steel Ltd did not cooperate and accordingly, the Authority did not determine an individual normal value for the said entity.
78. In view of noncooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers on price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.
79. With regard to export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined for all non-cooperating producers and exporters is mentioned in the dumping margin table.

#### **Korea RP**

#### **POSCO, Korea RP**

#### **Normal Value**

80. POSCO is a listed company (joint-stock Corporation) in Korea RP. During the POI, POSCO has sold subject goods to related and unrelated parties. To determine the normal value, the Authority

conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions for particular PCN are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions for particular PCN are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales or sufficiency test was not met for a particular PCN, normal value was either constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits or based on domestic selling price of closely resembling PCN.

81. POSCO has claimed adjustments on account of inland freight, warehousing expenses, credit cost and packing cost and the same have been allowed by the authority. Accordingly, weighted average normal value at ex-factory level for POSCO has been determined for HR Coils and HR not in Coils and the same is shown in the dumping margin table below.

#### **Export Price for POSCO, Korea RP**

82. POSCO has filed questionnaire response along with its related/unrelated trading companies namely, POSCO International Corp., Korea RP, POSCO Asia Company Limited, Hongkong, GS Global Corp., Korea RP, GS Global Singapore Pte. Ltd., Singapore, Samsung C&T Corporation, Korea RP, Hyosung TNC Corporation, Korea RP, Hyosung Japan Co., Ltd, Japan, who have exported the subject goods to India manufactured by POSCO. POSCO has exported PUC using direct/indirect channel.
83. POSCO has also made direct/indirect exports to related processors/importers of POSCO in India during the POI namely POSCO India PC, POSCO IPPC and POSCO Maharashtra. All these related parties have also filed importers/end-user questionnaire responses.
84. Further, POSCO has also exported some quantities through other traders who have not filed their questionnaire response with the Designated Authority. However, it is also noted by the authority that exports to India made through noncooperating unrelated parties are very insignificant in terms of total exports to India. For working out export price of the producer M/s POSCO, the Authority has considered the actual export price for chain comprising POSCO and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of POSCO who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for POSCO has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.
85. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO subsidiaries in India that, some of them are in losses during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. POSCO through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price, suitable adjustment has been made from POSCO's landed price and net export price. Further adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, credit costs and packing costs. The weighted average export price has been determined for POSCO at ex-factory level for HR Coils and for HR not in Coils and the same is shown in the dumping margin table below.

#### **M/s Hyundai Steel Company, Korea RP, and its participating related and unrelated importers/end-users**

##### **Normal Value**

86. It is noted that during the POI, Hyundai Steel Company, Korea RP, has sold the subject goods in the domestic market to related and unrelated parties. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the

normal value. With regard to Hyundai Steel Company, Korea RP, since in oct test the profit-making sales are less than 80%, the Authority has considered only profit-making domestic sales to determine the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales or sufficiency test was not met for a particular PCN, normal value was either constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits or based on domestic selling price of closely resembling PCN.

87. Hyundai Steel Company, Korea RP, has claimed adjustment on account of inland transportation, ocean freight and credit expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

#### **Export Price**

88. Hyundai Steel Company, who is a producer and exporter of the subject goods in Korea RP, has filed questionnaire response. During the POI, Hyundai Steel Company, exported the subject goods to India indirectly through three unrelated/related traders namely GS Global Corporation, Korea RP, Hyundai Corporation, Korea RP, Samsung C&T Corporation, Korea RP, and SK Networks Co., Ltd., Korea RP. It was observed by the authority that there was significant variation between the export sales price to its related company and the export sales price to unrelated customers in India for the same PCN/Grade. Hyundai Steel, Korea RP, was unable to provide any valid reasons for such a significant variation in export sales price between related and unrelated parties for the same PCN/grade. Therefore, authority has only considered the export sales to unrelated parties for determination of export price. Hyundai Steel Company, has claimed adjustment on account of ocean freight, inland transportation, port and other related expenses and credit cost. The weighted average export price has been determined at ex-factory level for HR Coils and for HR not in Coils and the same is shown in the dumping margin table below.

#### **Normal Value and Export price for non-cooperating producers and exporters from Korea RP**

89. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation.
90. In view of noncooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers on price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.
91. With regard to export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined for all non-cooperating producers and exporters is mentioned in the dumping margin table.

#### **Indonesia**

##### **PT Krakatau POSCO, Indonesia**

#### **Normal Value**

92. It is noted that M/s PT Krakatau POSCO is a Joint Venture Company in Indonesia. During the POI, PT Krakatau POSCO has sold \*\*\* MT of subject goods having invoice value \*\*\*USD to related and unrelated parties. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions for particular PCN are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions for particular PCN are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales or sufficiency test was not met for a particular PCN, normal value was either constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits or based on domestic selling price of closely resembling PCN.

93. PT Krakatau POSCO has claimed adjustments on account of inland freight, credit cost and the same have been allowed by the authority. Accordingly, weighted average normal value at ex-factory level for PT Krakatau POSCO has been determined for HR not in Coils and the same is shown in the dumping margin table below.

#### **Export Price**

94. PT Krakatau POSCO has filed questionnaire response along with its related/unrelated trading companies namely, POSCO International Corp., Korea RP, POSCO Asia Company Limited, Hongkong, GS Global Corp., Korea RP, Hyosung TNC Corporation, Korea RP, Hyosung Japan Co., Ltd, Japan, who have exported the subject goods to India manufactured by PT Krakatau POSCO. PT Krakatau POSCO has exported \*\*\* MT of PUC using direct/indirect channel.
95. PT Krakatau POSCO has also made direct/indirect exports to related importers of POSCO in India during the POI namely POSCO India PC and POSCO IPPC. All these related parties have also filed importers questionnaire responses.
96. Further, PT Krakatau POSCO has also exported some quantities through other traders who have not filed their questionnaire response with the Designated Authority. However, it is also noted by the authority that exports to India made through noncooperating unrelated parties are very insignificant in terms of total exports to India. For working out export price of the producer, the Authority has considered the actual export price for chain comprising PT Krakatau POSCO and cooperating traders who have duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders of PT Krakatau POSCO who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, the export price for PT Krakatau POSCO has been determined based on the weighted average export price of all exports' channels to India.
97. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO subsidiaries in India that, one of them is in losses during the sale of the subject goods imported from PT Krakatau POSCO through different trading channels as mentioned above. . As their sales price of subject goods are lower than their purchase price, suitable adjustment has been made from PT Krakatau POSCO's landed price and net export price. Further adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, credit costs, port and other related expenses. The weighted average export price has been determined for PT Krakatau POSCO at ex-factory level for HR not in Coils and the same is shown in the dumping margin table below.

#### **Normal Value and Export price for non-cooperating producers and exporters from Indonesia**

98. The Authority notes that no other producer/exporter from Indonesia has responded to the Authority in the present investigation.
99. In view of noncooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers on price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.
100. With regard to export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined for all non-cooperating producers and exporters from Indonesia is mentioned in the dumping margin table.

#### **Brazil**

##### **Normal value, Export price and Dumping margin**

101. It is noted that there were no imports of either HR in coil or HR not in coil from Brazil during the POI. Therefore, no dumping margin could be determined for Brazil.

#### **Russia**

##### **Normal value, Export price and Dumping margin**

102. It is noted that there were no imports of either HR in coil or HR not in coil from Russia during the POI. Therefore, no dumping margin could be determined for Russia.

**G.6. Determination of dumping margin**

103. Considering the normal value and export price for subject goods for the subject countries which had exports to India during the POI, the weighted average dumping margins for the said subject countries have been determined. The dumping margin determined as above is mentioned in the dumping margin table below.

S No	Country	Producer /Exporter	Product	Normal Value (USD/MT)	NEP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM %	Range %
1	China PR	All Producers /Exporters	HR in Coil	***	***	***	***	30-40
			HR not in Coil	***	***	***	***	20-30
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	25-35
2	Indonesia	PT Krakatau POSCO, Indonesia	HR in Coil	-	-	NA	NA	NA
			HR not in Coil	***	***	***	***	10-20
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	10-20
		All Others	HR in Coil	-	-	NA	NA	NA
			HR not in Coil	***	***	***	***	40-50
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	40-50
3	Japan	JFE Steel Corporation	HR in Coil	***	***	***	***	0-10
			HR not in Coil	***	***	***	***	10-20
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	10-20
		Nippon Steel Corporation	HR in Coil	***	***	***	***	20-30
			HR not in Coil	***	***	***	***	20-30
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	20-30
		All Others	HR in Coil	***	***	***	***	40-50
			HR not in Coil	***	***	***	***	10-20
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	40-50
4	Korea RP	POSCO	HR in Coil	***	***	***	***	0-10
			HR not in Coil	***	***	***	***	0-10
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	0-10
		Hyundai Steel Company	HR in Coil	***	***	***	***	0-10
			HR not in Coil	***	***	***	***	30-40
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	10-20
		All Others	HR in Coil	***	***	***	***	35-40
			HR not in Coil	***	***	***	***	40-50
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	40-50

**H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1. Submissions of the domestic industry**

104. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. Despite the imposition of antidumping duties, imports of subject goods from the subject countries have been stable and any decline from April 2020 to September 2020 is attributed to the decrease in demand owing to the Covid-19 pandemic. This decline will bounce back once the situation improves.

- ii. Actual and potential effect on sales- Dumped imports from the subject countries brought down the short-lived growth in sales that arose due to ADD being imposed.
- iii. The domestic industry has faced significant price suppression and depression during the POI(A) despite the existence of ADD. Removal of existing duties would only aggravate the said situation.
- iv. The negative price undercutting is negative due to the existence of reference price based anti-dumping duty imposed on the subject goods imported from the subject countries. In any case, a comparison of the weighted average import price with the domestic selling price covering the entire POI masks the actual price undercutting in view of (a) significant monthly variation in prices of both imports and the domestic industry; and (b) significant variation in the product-mix i.e. product under consideration contains multiple product types under several tariff headings and prices vary as per product types and the composition of imports and domestic sales in terms of volumes of different types affect the weighted average prices used for comparison. The exporters from the subject countries are known to indulge in over-invoicing as noted by the authority in the case of Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP.
- v. The demand for subject goods has remained stable except for a decline during the proposed POI which may be attributable to Covid-19 pandemic. Imports from other countries has declined during the POI.
- vi. Sales, Capacity, Production and Capacity Utilization- Between the base year and the POI, capacity utilization grew by 26%, while the total production and domestic sales of domestic industry decreased by 7% and 14% respectively. Capacity utilization has also considerably decreased. During the proposed POI, the profitability, cash profits as well as return on capital employed witnessed a significant decline. The domestic industry witnessed decline in the number of employees during the proposed POI. The inventory levels for the subject goods produced by the DI increased in the POI and continue to be significant. Removal of ADD would prejudice ability to raise capital investment for further growth.
- vii. Despite imposition of ADD, the domestic industry continues to suffer material injury and there is likelihood of injury in the imminent future to the domestic industry is due to dumped imports.
- viii. The export performance of the Domestic Industry in no way has affected its financial and economic situation as injury information has been segregated. There has been no change in either the technology or the production process, to be a cause of injury to the domestic industry. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry. The only cause of injury is the dumped imports from subject countries. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Changes in the pattern of consumption have not caused claimed injury to the domestic industry.

## **H.2. Submissions of other interested parties**

105. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Scope for competition between imports from Japan and Domestic Industry’s products are minimal because the Domestic industry cannot match the highly specialized grades sold by Japanese Mills.
- ii. Imports from the subject countries have significantly decreased by 56 index points in the POI(A) compared to the base year.
- iii. Petitioner cannot attribute decline in volume due to Covid-19 decline in demand and continued presence of dumped imports from the subject countries.
- iv. There is no price suppression / depression from subject countries as the selling price is in tandem with the cost of sales of the DI throughout the injury period.



- v. The price undercutting for all subject countries in the POI is negative. Petitioners arguments to oppose the use of weighted average of entire 18 months is to be rejected because:
  - i. there is a significant difference between the reference price and the landed price of Japanese Mills, which clearly demonstrates that the price increase is based on commercial considerations and not artificially inflated due to reference price based anti-dumping duty
  - ii. Monthly price variation in import prices cannot be the basis to oppose as subject goods comprise of multiple product types whose prices vary significantly. Monthly product mix may vary and consequently the price may also vary each month.
  - iii. The issue of over-invoicing, if any, is one that is appropriately assessed and dealt with by customs authorities (which is the appropriate forum), and not the DGTR and anyways lacks supporting evidence.
- vi. Installed capacity, production, sales value, sales realization, inventories and PBIT and cash profits have improved in the POI compared to the base year despite the Covid-19 pandemic. Therefore, an adjustment for the pandemic could mean that the DI must be performing much better.
- vii. DI specifically SAIL and JSW have acknowledged positive performance in their annual reports. Absence of injury to DI, as SAIL's annual reports indicates improved EBITDA margin. JSW Steel also reports improved EBITDA margin and marginal decline in FY 2019-20 can be attributed to extended monsoon, slowdown in automotive industry and covid-19 pandemic.
- viii. There are various factors other than alleged dumped imports that have impacted the performance of Domestic Industry:
  - i. The adverse effect / impact of COVID-19 on the Domestic Industry and steel industry has been recognized in the annual reports of the Domestic Industry as well as in the public domain.
  - ii. The performance of the Domestic Industry was impacted due to decline in the demand which in turn was on account of various other factors such as weaker activity caused by lower public investment spend on account of general elections, lack of credit availability across the economy and slowdown in automotive and consumer durables etc.
  - iii. The domestic producers in India are increasing their capacities (which is in excess of the demand in India).
  - iv. SAIL has incurred a substantial amount of the employee benefit expenses in comparison to other constituents of the Domestic Industry.
- ix. The volume of imports of the PUC from subject countries has declined by 24 indexed during the POI as compared to base year.
- x. Claim that the growth of sales of the petitioner was short lived and declined due to dumped imports is incorrect as petitioner's own data indicates domestic sales and demand have remained on the same level. Decline in domestic sales can be attributed to the Covid-19 pandemic.
- xi. Market share of the DI and captive consumption of the DI increased from the base year and the imports declined from the base year. The DI along with the other domestic producers already accounts for 95% of the market share of the domestic demand of the PUC during the POI(A).
- xii. DI has not suffered any price suppression or depression DI has been able to increase selling price for HR in coil by 19% while costs increased by 15% during the POI(A) as compared to the base year. Landed value for HR in coil increased by 37% during the same period.
- xiii. While domestic selling price of DI for HR in Coil declined by 23 indexed points and cost of sales declined by 15 indexed points during POI(A) as compared to previous year, at the same time, the landed value declined by 13 indexed points.

- xiv. DI has been able to increase its selling price for HR not in Coil by 23% while the costs increased by 16% during POI(A) as compared to base year. Thus, the domestic selling price of HR not in Coil witnessed a higher increase in POI(A) from base year as compared to the increase in cost of sales.
- xv. Market report indicates that there has been significant variation in raw material prices of steel during POI which has impacted the selling price.
- xvi. DI does not appear to be suffering from price underselling due to alleged dumped imports of PUC from subject countries during the POI. Moreover, as per the data provided in the petition, the DI has also been able to increase its cash profits during this period.
- xvii. The overall profit of the DI has increased by 7% during the POI(A) from the base year, and it has increased significantly throughout the investigation period. Moreover, the other profitability indicators, such as PBIT and Cash Profits have also increased by 7% and 53% during the investigation period. ROCE of the DI shows an overall increase by 116% in a span of 3 years, i.e., from the base year to 2018-19, and an increase of 3% during the POI(A) from the base year.

### **H.3. Examination by the Authority**

106. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
107. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."
108. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to continuation of material injury to the domestic industry. Similarly, if the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic industry.
109. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.
110. As regards the submission of the interested parties that 22% returns on capital employed is not acceptable for calculation of NIP, the Authority notes that this is the consistent practice of the Authority in all previous investigations conducted.
111. The Authority has examined the information furnished by the domestic Industry which has been verified and accepted after desk verification/remote cross check due to the present COVID-19 situation.

112. As regards the submission of the interested parties that scope for competition between imports from Japan and the domestic industry's products are minimal because the domestic industry cannot match the highly specialized grades sold by the Japanese Mills, the Authority examined the PCNs exported by the interested parties and those manufactured by the domestic industry during the POI. From the detailed examination of the information, the Authority found that the domestic industry either manufactured exactly matching PCN or a closely resembling PCN for each PCN for which information has been provided by the interested parties.
113. The interested parties have claimed that the Authority must conduct a weighted average undercutting margin for the entire eighteen months of the POI as opposed to the monthly undercutting suggested by the Petitioners. The Authority notes that it has conducted the price undercutting analysis on a weighted average basis for the entire 18 months-long POI and on an annual basis for the years prior to the POI.
114. As regards the contention that SAIL and JSW have acknowledged positive performance in their Annual Reports and improved EBITDA margin, it is noted that the applicant domestic producers are multi-product companies which manufacture other articles in addition to the subject goods. The Authority has examined the performance of the domestic industry with regard to the domestic like article to the PUC. Therefore, overall performance of the companies as reflected in their Annual Reports is not indicative of whether it is suffering from material injury in its capacity as domestic industry of the like article.
115. Some of the interested parties have claimed that various factors other than alleged dumped imports that have impacted the performance of domestic industry such as adverse effect / impact of COVID-19 which has been recognized in the Annual Reports of the domestic industry as well as the consequent decline in demand. In this regard, the Authority notes that the present anti-dumping investigation entails an examination of whether dumped imports are a cause of material injury to the domestic industry and that they need not be the only cause. Therefore, the Authority has examined whether dumped imports have impacted the performance of the domestic industry in the subsequent paras.
116. Some of the interested parties have claimed that the domestic capacity in India is in excess of the demand in India. The Authority notes that despite capacities (of the domestic industry and other producers) being sufficient to cater to the entire domestic demand, the volume of imports have remained significant.
117. As regards the reference to market reports by certain interested parties which indicate that there has been significant variation in raw material prices of steel during the POI which has impacted the selling price, the Authority notes that the average cost of sales for eighteen months of the POI has been compared with the average net sales realization for the same period and therefore, any variations in such raw material prices will also be averaged out.
118. As regards the argument that Covid-19 is impacting the global matrix, it is noted that the same cannot justify dumping of the product in India.
119. All other submissions of all interested parties with regard to injury analysis have been addressed in the following paragraphs.

### **H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry**

#### **a. Assessment of demand/apparent consumption**

120. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of captive consumption and domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	Value	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr 19 to Sep 20)	POI (A)
Imports from subject countries	MT	2,779,816	2,993,215	2,600,132	3,184,753	2,123,169
	Indexed	100	108	94	115	76
Imports from other countries	MT	428,750	218,164	381,755	242,129	161,419
	Indexed	100	51	89	56	38
Domestic Sales of DI	MT	15,225,634	16,699,221	17,745,040	22,849,840	15,233,227
	Indexed	100	110	117	150	100
Captive Consumption of DI	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	106	107	156	104
Domestic Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	133	119	152	101
Captive Consumption of other domestic producers	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	128	109	158	105
<b>Demand (including captive consumption)</b>	MT	<b>41,906,000</b>	<b>49,011,000</b>	<b>47,278,000</b>	<b>62,548,000</b>	<b>41,698,667</b>
	Indexed	100	117	113	149	100
<b>Demand (excluding captive consumption)</b>	MT	<b>29,999,223</b>	<b>35,280,695</b>	<b>34,476,098</b>	<b>43,826,600</b>	<b>29,217,734</b>
	Indexed	100	118	115	146	97
<b>Total Domestic Production</b>	MT	<b>41,825,000</b>	<b>49,237,000</b>	<b>50,349,000</b>	<b>71,571,000</b>	<b>47,714,000</b>
Imports from subject countries in relation to <b>Consumption (including captive)</b>	%	7%	6%	5%	5%	5%
Imports from subject countries in relation to <b>total Domestic production</b>	%	7%	6%	5%	4%	4%
Imports from subject countries in relation to <b>Consumption (excluding captive)</b>	%	9%	8%	8%	7%	7%

121. The Authority finds that the demand increased from 41.9 Mn MT in 2016-17 to 49.0 Mn MT during 2017-18. It declined to 47.3 Mn MT during 2018-19 and further to 41.7 Mn MT during POI (A). There is no significant change in the demand between the base year and the POI of the injury analysis period.

**b. Import Volumes from subject countries.**

122. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (A)
Subject Countries	MT	2,779,816	2,993,215	2,600,132	3,184,754	2,123,169
	Indexed	100	108	94	115	76
Brazil		191	-	-		-
China PR		850,785	705,576	420,396	669,411	446,274
Indonesia		38,464	92,693	98,657	167,633	111,755
Japan		659,786	595,062	441,931	431,765	287,844
Korea RP		1,086,611	1,541,231	1,605,592	1,915,943	1,277,296
Russia		143,980	58,654	33,555		-
Other Countries	MT	428,750	218,164	381,755	242,129	161,419
	Indexed	100	51	89	56	38
Total Imports	MT	3,208,566	3,211,379	2,981,886	3,426,883	2,284,588
	Indexed	100	100	93	107	71
Total Domestic Production	MT	41,825,000	49,237,000	50,349,000	71,571,000	47,714,000
Imports from Subject Countries in relation to total imports	%	87%	93%	87%	93%	93%
	indexed	100	108	101	107	107
Imports from Other Countries in relation to total imports	%	13%	7%	13%	7%	7%
	indexed	100	51	96	53	53
Imports from subject countries in relation to total Domestic production	%	7%	6%	5%	4%	4%
Imports from subject countries in relation to Consumption (including captive)	%	7%	6%	5%	5%	5%
Imports from subject countries in relation to Consumption (excluding captive)	%	9%	8%	8%	7%	7%

123. The Authority finds that imports from the subject countries varied within a range of 2.1 Mn MT to 3.0 Mn MT. The Authority also notes that there were no imports from Brazil after 2016-17 and Russia during the POI.

124. The Authority notes that imports from the subject countries has commanded a significant share in the total import of the subject goods during the entire injury analysis period. The Authority further notes that the share of imports from the subject countries in total imports has increased during the POI.

### **H.3.2. Price effect of the dumped imports**

125. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

#### **i. Price undercutting**

126. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the price from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr 19 to Sep 20)	POI (A)
Landed Value	INR/MT	32,603	39,224	48,661	45,497	45,497
	Indexed	100	120	149	140	140
Domestic Selling Prices	INR/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	120	142	120	120
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***
	% Range	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative

127. It has been claimed that the imports from subject countries as a whole are entering at prices above the domestic selling prices of the domestic industry resulting in negative price undercutting. It is noted that the anti-dumping duty imposed on the basis of reference price has prevented the prices of the imports from entering the domestic market at low prices.

#### **A.1 b. Price suppression and depression**

128. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling Price	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	120	140	119

Cost of sales	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	115	129	119
Landed Value	INR/MT	32,603	39,224	48,661	45,497
	Indexed	100	120	149	140
Price Suppression	INR/MT		***	***	***
	Indexed		(100)	(160)	208

129. The Authority notes that the prices of the domestic industry increased till 2018-19 when prices of imports were also increasing. Thereafter, when prices of imports declined during the period of investigation, the prices of the domestic industry also declined.

130. The Authority notes that some of the related importers of the producers and exporters in the subject countries have resold the PUC to users below the prices at which they were imported. It was also found with respect to certain producers that there was a significant variation between the export price to their related entities and independent buyers.

131. The Authority further notes that the decrease in selling price of the domestic industry was more than the decrease in its cost of sales during the POI, indicating that its prices were both suppressed and depressed during the POI as compared to previous year.

### H.3.3. Economic parameters of the domestic industry

132. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below.

133. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

#### A.2 i. Production, capacity, capacity utilization and sales

134. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Installed Capacity	MT	28,540,000	28,638,630	29,540,000	44,310,000	29,540,000
	Indexed	100	100	104	155	104
Production	MT	24,311,195	25,643,998	26,791,249	37,322,672	24,881,782
	Indexed	100	105	110	154	102
Capacity Utilization	%	85%	90%	91%	84%	84%
	Indexed	100	106	107	99	99
Domestic Sales	MT	15,225,634	16,699,221	17,745,040	22,849,840	15,233,227
	Indexed	100	110	117	150	100

135. The Authority finds that -

- i. Compared to the base year 2016-17, installed capacity of the domestic industry increased during 2017-18 and again during 2018-19. Even with increased capacity, percentage of capacity utilization increased during 2017-18 and 2018-19. However, capacity utilization declined during the POI (A) to a level lower than that existed in 2016-17.
- ii. Production and sales of the domestic industry also increased commensurately till 2018-19. During the POI however, the production and domestic sales of the domestic industry reduced to the same levels as that of the base year.
- iii. Capacity utilization and sales reduced as a result of reduction in demand witnessed during the POI compared to 2018-19.

**i. Market Share in demand**

136. Market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars		2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI(A)
Market share of subject countries in demand (including captive)	%	6.63%	6.10%	5.49%	5.09%	5.09%
	Indexed	100	92	83	77	77
Market share of subject countries in demand (excluding captive)	%	9.26%	8.48%	7.54%	7.26%	7.26%
	Indexed	100	92	81	78	78
Imports from other countries	%	1.02%	0.45%	0.81%	0.39%	0.39%
	Indexed	100	44	79	38	38
Domestic Sales of DI	%	36.33%	34.07%	37.53%	36.53%	36.53%
	Indexed	100	94	103	101	101
Captive Consumption of DI	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	90	94	105	105
Domestic Sales of other domestic producers	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	114	105	102	102
Captive Consumption of other domestic producers	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	109	96	106	106

137. It is seen from the above table that

- i. The market share of domestic industry, both including and excluding captive consumption remained within a narrow range during the entire injury analysis period.
- ii. Market share of dumped imports. However, after reducing marginally from 7% in 2016-17 to 5% in 2018-19, the market share of dumped imports remained the same during the POI.
- iii. The Authority notes that dumped imports continued to enter the domestic market in significant volumes.

**iii. Inventories**

138. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:



Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
Inventory	MT	816,152	603,243	746,064	821,292
	Indexed	100	74	91	101
Inventory as No. of days of Production	No	12	9	10	12
	Indexed	100	75	83	100
Inventory as No. of days of Sales	No	17	12	14	16
	Indexed	100	71	82	94

139. It is noted that there is little change in inventory of subject goods during the injury period.

#### iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

140. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the period is given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (A)
Cost of Sales - Domestic	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	115	129	119
Selling Price- Domestic	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	120	140	119
Profit	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	192	332	115
PBIT - Domestic Sales	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	143	198	86
Cash Profit	INR/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	157	242	117
PBIT - Domestic	Rs. in Crores	7,495	11,720	17,259	9,666
	Indexed	100	156	230	129
Cash Profit	Rs. in Crores	***	***	***	***
	Indexed	100	172	282	176
Return on capital employed	%	***	***	***	***
	Indexed	100	154	221	81

141. The Authority finds that after imposition of ADD, profit per MT increased from Rs. \*\*\* PMT during 2016-17 to Rs. \*\*\* PMT during 2018-19. However, profits declined to Rs. \*\*\* PMT during POI. A similar trend is seen in respect of PBIT and cash profit.

142. It is noted that ROCE was \*\*\*% during 2016-17. It increased to \*\*\*% and \*\*\*% during 2017-18 and 2018-19 respectively but declined to \*\*\*% during the POI.

#### v. Employment, wages and productivity

143. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No of Employees	Nos	93,704	87,895	83,639	79,418
	Indexed	100	94	89	85
Wages	Rs. in Crores	3,167	3,062	3,053	4,062
	Indexed	100	97	96	128
	INR/MT	2,080	1,834	1,720	1,778
	Indexed	100	88	83	85
Productivity per Day	MT/Day	66,606	70,258	73,401	68,169
	Indexed	100	105	110	102

144. It is seen that the number of employees has decreased throughout the injury period and in the period of investigation. Similarly, wages per MT also declined during the injury analysis period. Productivity improved overall but declined in the POI compared to 2018-19.

#### vi. Growth

145. The domestic industry record growth during 2017-18 and 2018-19 over the respective preceding years, but recorded a negative growth during the POI, in terms of, production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment as shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI(A)
Production	Y/Y	-	5%	4%	-7%
Capacity Utilisation	Y/Y	-	6%	1%	-8%
Domestic Sales	Y/Y	-	10%	6%	-14%
Profit/Loss Per unit	Y/Y	-	1423%	237%	-91%
Cash Profit	Y/Y	-	79%	108%	-60%
Return on Capital Employed	Y/Y	-	67%	60%	-75%
Inventories	Y/Y	-	-26%	24%	10%

#### vii. Magnitude of dumping margin

146. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive in the period of investigation.

#### viii. Ability to raise capital investment

147. Significant investment was recently made in increasing the capacity of the Domestic Industry to produce the PUC. However, the profitability of the domestic industry has significantly declined in the POI.

#### ix. Magnitude of price underselling/injury margin

148. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin. The Authority has first determined injury margin for each PCN by comparing the landed value and NIP at PCN level. Thereafter, weighted average injury margin for the PUC as a whole has been determined. Wherever there were no sales of exactly matching PCN by domestic industry, comparison of landed value of imports from subject country was made with NIP of closely resembling PCN.

149. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

Injury Margin Table

S No	Country	Producer/Exporter	Product	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Range %
1	China PR	All Producers/Exporters	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
2	Indonesia	PT Krakatau POSCO, Indonesia	HR in Coil	-	-	NA	NA	NA
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
		All Others	HR in Coil	-	-	NA	NA	NA
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
3	Japan	JFE Steel Corporation	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
		Nippon Steel Corporation	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
		All Others	HR in Coil	***	***	***	***	0-10
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
4	Korea RP	POSCO	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
		Hyundai Steel Company	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative
		All Others	HR in Coil	***	***	***	***	Negative
			HR not in Coil	***	***	***	***	Negative
			PUC W. Avg.	***	***	***	***	Negative

## B I. EXAMINATION ON INJURY

150. The examination of the imports of the subject goods from the subject countries and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries have declined in absolute terms but continue to remain significant in the demand excluding captive consumption. While price undercutting is negative, the Authority notes that the dumping margin of the producers and exporters in the subject countries is significant. It is noted that and some of their related importers in India have resold the PUC to users below the prices at which they were imported or there was a significant variation in export price to their related entities and independent buyers. The prices of the Domestic Industry were both suppressed and depressed during the POI. While there was a reduction in production, sales and capacity utilization due to a reduction in demand witnessed during the POI, the performance of the domestic industry significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed during the same period due to price suppression and depression. Growth of the

Domestic Industry has also become negative. In view of the foregoing, the Authority concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

### **C J.CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

151. Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the PUC during the review investigation period or not. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

#### **i. Volume and prices of imports from third countries**

152. It is seen that imports from other countries other than dumped imports are negligible and ranged between 0.39% to 1.02% of demand during the injury analysis period and therefore, third country imports could not have been a cause of injury to the domestic industry.

#### **ii. Contraction in Demand**

153. It is seen that the demand for the product under consideration decreased during the period of investigation. However, while demand contracted which impacted sales of the domestic industry during the last six months of the period of investigation, imports from the subject countries also reduced commensurately and as a consequence, the market share of the domestic industry and imports remained the same during the period of investigation when compared to the preceding year i.e. 2018-19. Therefore, contraction in demand cannot be considered as a reason for injury to the domestic industry.

#### **iii. Changes in Pattern of consumption**

154. No evidence has been brought by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption of the product under consideration. Therefore, possible changes in the pattern of consumption are not the cause of injury considered by the Authority.

#### **iv. Conditions of competition and trade restrictive practices**

155. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for injury suffered by the Authority.

#### **v. Developments in technology**

156. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

#### **vi. Export Performance of the Domestic industry**

157. Exports made by the domestic industry constitutes small portion of its production. The Authority has considered data for domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

#### **vii. Performance of other products**

158. The domestic industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

### **D K. ANALYSIS OF CONTINUATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**

#### **Likelihood of Injury to the domestic industry**

159. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of the investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD were to be allowed to expire, even if there is no current dumping or injury.

#### **I.1. Submissions by the domestic industry**

160. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood:

- i. Unlike EU and the USA, India is the only large exporting destination which does not have a safeguard measure imposed for the protection of its domestic industry. The absence of any protection is likely to cause subject goods from subject countries to flood the markets.

- ii. As per the OECD steel report, global steel capacity increased by 34.1mmt.in 2019 from 2018. Projection for 2022 estimates an increase of another 58-78 mmt which is almost equivalent to that of Korea which has the fourth largest capacity.
- iii. Demand is expected to rise in India and the increase in capacity in 2021 and 2022 will cater to the increased demand of India.
- iv. Free trade agreements with the subject countries may result in export of the subject goods to the Indian market.
- v. The unutilized capacity in 2019 is almost equal to the combined capacity of the second (EU), third (Japan) and fourth (India) largest steel producing economies. Exports in 2021 are expected to rise again when the markets will function at the level before the lockdown.
- vi. There are 28 trade remedy measures initiated by third countries against the subject countries. Additionally, the USA has imposed 25% additional duty under Section 232 of the US Trade Expansion Act 1962. This measure not only affected exports from the subject countries to USA but also their exports to other countries as they safeguard measures to protect their industry from the 'bouncing off' effect of Section 232 measures imposed by US.

Sl. No.	Imposing Country	Country Affected	Measure	Date of initial Imposition or last extension	Product
1.	Canada	China	AD	13-Feb-1997 (Last extended 9-Aug-2018)	Certain hot-rolled steel plate (previously hot-rolled carbon steel plate)
2.	Canada	China	AD	17-Aug-2001 (Last extended 12-Aug-2016)	Certain hot-rolled steel sheet (previously hot-rolled carbon steel sheet)
3.	European Union	China	AD	06-Apr-2017	Certain hot-rolled flat products of iron, non- alloy or other alloy steel
4.	Indonesia	China	AD	15-Aug-2019	Hot Rolled Plate
5.	Thailand	China	AD	12-Aug-2011 (Last extended on 23-Jun-2017)	Flat Hot Rolled in Coils and not in Coils
6.	Thailand	China	AD	26-Dec-2012 (Last extended on 12-Dec-2018)	Flat Hot Rolled Steel added Boron in Coils and not in Coils
7.	United States of America	China	AD	27-Aug-2019	Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
8.	Canada	Brazil	AD	17-Aug-2001 (Last extended 12-Aug-2016)	Certain hot-rolled steel sheet (previously hot-rolled carbon steel sheet)
9.	European Union	Brazil	AD	6-Oct-2017	Hot-rolled flat products of iron, non- alloy or other alloy steel
10.	Thailand	Brazil	AD	16-May-2017	Flat hot rolled in coils and not in coils
11.	United States of America	Brazil	CV	3-Oct-2016	Hot rolled flat steel products
12.	United States of America	Brazil	AD	3-Oct-2016	Hot-rolled steel flat products

13.	United States of America	Japan	AD	5-Sept-2019	Hot-rolled steel flat products
14.	Indonesia	Korea	AD	7-Feb-2011	Hot Rolled Coil
15.	Thailand	Korea	AD	23-May-2020	Flat Hot Rolled in Coils and not in Coils
16.	United States of America	Korea	CV	3-Oct-2016	Hot rolled flat steel products
17.	United States of America	Korea	AD	9-July-2019	Hot-rolled steel flat products
18.	Brazil	Russian Federation	AD	19-Jan-2018	Hot rolled steel
19.	European Union	Russian Federation	AD	6-Oct-2017	Hot-rolled flat products of iron, non- alloy or other alloy steel
20.	Indonesia	Russian Federation	AD	2-Apr-2019	Hot Rolled Coil
21.	Mexico	Russian Federation	AD	29-Mar-2015	Hot-rolled sheet
22.	Thailand	Russian Federation	AD	23-May-2020	Flat Hot Rolled in Coils and not in Coils
23.	United States of America	Russian Federation	AD	20-Oct-2016	Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
24.	Thailand	Indonesia	AD	21-May-2015	Flat Hot Rolled in Coils and not in Coils
25.	United States of America	Indonesia	AD	3-Dec-2001 (Last extended: 27- Aug- 2019)	Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
26.	United States of America	Indonesia	CV	27-Aug-2019	Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
27.	European Union	All	SG	18-Jul-2018	All Steel Products
28.	United States of America	All	SG	23-Mar-2018	All Steel Products

- vii. For instance, European Union imposed a safeguard measure on 18 July 2018 on imports of steel products with the sole objective of protecting EU industry from increased imports from countries that could not export to US due to US 232 measure.
- viii. The steel production in the subject countries increased between 2017 to 2019, where China's increased by 14.5% and Indonesia by 23%. The demand in the subject countries are not sufficient to absorb their entire production and a significant percentage of production is exported. High export orientation can lead to high likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the duties were to cease.
- ix. Global exports from the subject countries have declined in 2019 and thus they may be holding significant inventories of the subject goods. These could be released in India when the duties cease.

Country	2019	2018	Reduction
China	63.8	68.8	5
Japan	33.1	35.8	2.7
Russia	29.5	33.3	3.8
Korea	29.9	30.1	0.2
Brazil	13.3	13.9	0.6
<b>Total</b>	<b>169.6</b>	<b>181.9</b>	<b>12.3</b>

[Source: WSA]

- x. The capacities held by subject countries far outstrip the consumption in their respective markets. In a situation when most of the major steel consuming countries have closed their markets, export oriented countries with excess capacities will look to open and predictable markets.

	Production			Consumption			Excess Production		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
China PR	996.3	920	870.9	907.5	836.1	773.8	88.8	83.9	97.1
Japan	99.3	104.3	104.7	63.2	65.4	64.4	36.1	38.9	40.3
Indonesia	6.4	6.2	5.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Russia	71.9	72.1	71.5	43.5	41.4	41.2	28.4	30.7	30.3
Korea RP	71.4	72.5	71	53.2	53.7	56.3	18.2	18.8	14.7
Brazil	32.2	35.4	34.5	20.6	21.2	19.6	11.6	14.2	14.9
<b>Total</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>1088</b>	<b>1017.8</b>	<b>955.3</b>	<b>183.1</b>	<b>186.5</b>	<b>197.3</b>

[Source : WSA ]

- xi. The exports from subject countries to third countries are priced lower than the exports to India. Since the prices from the subject countries to India are higher than their global export prices, it is evident that if the existing antidumping duties are removed, the subject countries will increasingly turn to the Indian domestic market to dump the subject goods because they would be able to fetch higher prices.

	HR Coils Avg Export Price to India (2019)	HR Coils Avg Export Price to World (2019)	HR not in Coils Avg Export Price to India (2019)	HR not in Coils Avg Export Price to World (2019)
<b>Brazil</b>	-	493	-	669
<b>China</b>	576	514	745	560
<b>Indonesia</b>	-	506	580	552
<b>Japan</b>	529	536	993	694
<b>Korea</b>	585	558	664	658
<b>Russia</b>	-	476	-	614

(Source: ITC Trade map Data)

- xii. The unutilized capacity, additions to capacity on top of such unutilized capacities, surplus production, trade barriers in major steel consuming countries, cumulatively point towards the unmistakable factum that there is a clear and imminent likelihood of increase in dumped imports to India and recurrence of material injury in the event that anti-dumping duties are removed.

xiii. The producers/exporters in subject countries have significant unutilized capacities:-

**D.1 Unit: Million metric tonnes**

**D.2**

		2017	2018	2019
<b>China</b>	Capacity	1164	1128	1152
	Production	871	920	996
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>293</b>	<b>198</b>	<b>156</b>
<b>Japan</b>	Capacity	130	130	130
	Production	105	104	99
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
<b>Korea</b>	Capacity	82	82	82
	Production	71	72	71
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Indonesia</b>	Capacity	11	11.5	12
	Production	5	6	6.5
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
<b>Russia</b>	Capacity	86	86	87
	Production	71	72	72
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>Brazil</b>	Capacity	51	51	51
	Production	34	35	32
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
<b>Subject Countries</b>	Capacity	1513	1477	1502
	Production	1157	1209	1276.5
	<b>Unutilized Capacity</b>	<b>356</b>	<b>268</b>	<b>225.5</b>

[Source: OECD and WSA]

Capacity in the subject countries have increased despite the fact that OECD is constantly urging countries to reduce their steel capacities. The unutilized capacity in the subject countries is far higher than the demand in India

xiv. The Ministry of Finance vide Notification No.2/2021-Customs (Exhibit-27), has reduced the basic customs duties on imports of the subject goods from 12.5%/10% to 7.5%.

xv. Steel prices are cyclical in nature and has remained extremely volatile over the years. The prices are subject to significant variations:

S. No.	High	\$/MT	Low	\$/MT	Difference in Months
1	May-1995	475	Feb-1996	255	9
2	Apr-1997	345	Dec-1998	185	20
3	Apr-2000	333	Dec 2001	175	20



4	Feb-2003	353	Jun-2003	250	4
5	Sep-2004	625	Jul-2005	390	10
6	Jun-2006	610	Dec-2006	502	6
7	Jun-2008	1113	Mar-2009	380	9
8	Aug-2009	620	Nov-2009	496	3
9	Apr-2010	718	Jul-2010	588	3
10	Feb-2011	772	Dec-2015	270	58
11	Apr-2016	440	Jun-2016	362	2
12	Mar-2018	637	May-2020	385	26
13	May-2021	1015			

(Source: WSD)

- xvi. Whenever steel prices increased, they fell sharply again. The World Steel Dynamics projections predict that steel prices will reduce again:

Hot Rolled Band (mt)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Apr 2020	May 2021	June 2021	2021 (Q3)	2021 (Q4)	2022	2023 - 2030
World Export Market (FOB)	370	382	530	580	498	487	390	1070	1050	975	750	650	513

(Source: WSD)

- xvii. Post-POI information is not a legally mandated factor to be considered in each and every sunset review investigation. In sunset reviews recently concluded by the Authority regarding (1) *Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profile of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel* originating in or exported from China PR-reg - Final findings dated 30<sup>th</sup> July 2021, (2) *Viscose Staple Fibre* originating in or exported from China PR and Indonesia - Final findings dated 31<sup>st</sup> July 2021, (3) *Flat-based Steel Wheels* from China PR – Final Findings on 9<sup>th</sup> August 2018, (4) *Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel* from China, Korea RP, EU, Taiwan, Thailand & USA– Final Findings dated 20<sup>th</sup> January 2021(5) *Methyl Acetoacetate* from China PR – Final Findings dated 3<sup>rd</sup> May 2021(6) *Phthalic Anhydride* from China PR, Indonesia, Korea and Thailand – Final Findings dated 19<sup>th</sup> May 2021, post-POI data was not considered for determining likelihood of dumping and injury

## I.2. Submissions by other interested parties

161. The following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood:

- Petition lacks reliable evidence regarding normal value and export price or likelihood of recurrence of injury and is therefore, unsubstantiated. Consequently, the initiation (which is based on unsubstantiated Petition) lacks merit and fails to meet the threshold set forth by Rule 23 of the AD Rules.
- Projections regarding increase in demand and slump in prices cited by Petitioner are no longer reliable due to the impact of Covid-19 pandemic.
- Post-POI data would be required to determine whether DI suffered from continued injury as per the Authorities findings in Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Filament Yarn originating in or exported from China PR. Lack of it should lead to termination of the investigation.

- iv. No significant imports as the imports from subject countries as a whole as well as Japan have decreased in the POI.
- v. DGTR should not include the 18-month period (March 2020-September 2021) affected by Covid-19 pandemic. Any injury to the Domestic Industry due to the COVID-19 pandemic should not be attributed to the subject imports.
- vi. Petitioner's claims on excess capacity from with respect to Japan are unsubstantiated.
- vii. Averments of petitioner on demand in India and capacity increase will only cater to increased demand are baseless: (1) Forecasts prepared in 2018/2019 without accounting for the Covid-19 pandemic and hence unreliable, (2) Petitioner admits that demand decreased in 2020 due to the pandemic and hence the global capacity could not have been used to cater to the Indian market, (3) Demand declined in the POI. Petitioner cannot rely on the forecast reports to show increases in demand in 2021/2022.
- viii. Questionnaire responses will indicate that there are no excess capacities with the Exporters.
- ix. The OECD and WSA reports relied upon by the Petitioner has not be disclosed to the parties, which deprives the Japanese Mills an opportunity to provide meaningful comments on this section.
- x. Assuming (but not conceding) that there are unutilized capacities with the producers in Japan and reference price based anti-dumping duty is no longer relevant (on account of movement of raw material prices) as claimed by the Petitioner, the producers from Japan would have already exported the alleged unutilized capacities towards India. However, imports from Japan decreased.
- xi. Japanese producers sell specialized products only to India, the demand for specialized products is already low in India and that there has been a contraction in demand on account of the COVID-19 pandemic. Even if the demand for PUC increases, the Japanese producers' exports will be of specialized grades only.
- xii. Information provided by the petitioner shows production and exports decreased, production and inventories of the Japanese Mills also declined. Exports from Japanese Mills to all countries remained stable. No evidence of unutilized capacities in Japan.
- xiii. Trade remedial measures imposed by USA/EU against Japan do not have effect on the pattern of the sales and exports of the Japanese Mills.
- xiv. Significant volumes of grades sold by some of the Japanese Mills to the third countries where trade remedy measures are in place are not substitutable to the grades sold to India and thus unlikely to be diverted.
- xv. Volume of exports have not increased, or price not decreased despite the reduction in BCD under the India-Japan CEPA.
- xvi. Merely having an excess capacity with the exporters does not in itself imply that it is meant to be diverted to India especially when the DI has not provided any cogent evidence (Article 3.2 of the ADA, Final findings in a sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Rubber Chemicals, namely, MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT, originating in or exported from China PR and imports of PX-13 (6PPD) originating in or exported from China PR and Korea RP, Indian Spinners Association v. DA)
- xvii. The injury parameters show that the DI is enjoying substantial profits and has improved on all the economic parameters. Thus, petitioner's argument regarding Export Orientation of Subject Countries and presence of Unutilized Capacities must be rejected.
- xviii. Present demand as per the JPC data cited by the DI is 41,698,667 MT<sup>61</sup> against an installed capacity of 40,478,000 MT. A 13-14% year on growth in steel demand for FY2021-22 along with backward integrated and significant exporting DI would mean imports are necessary to cater to domestic demand after Covid-19 slowdown.

- xix. Imports of the PUC from the subject countries have declined by 24% when compared to the base year despite the demand remaining at comparable levels to the base year. This indicates ADD has served its purpose in reducing volume impact of imports.

### **I.3. Examination by the Authority**

162. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
163. Some of the interested parties have claimed that the petition lacks reliable evidence regarding likelihood of recurrence of injury and is therefore, unsubstantiated and could not have formed the basis of initiation of the investigation. In this regard, the authority notes that the interested parties have also relied upon the same sources of information such as world steel dynamics report and the OECD reports.
164. Some of the interested parties have the contended that the projections regarding increase in demand and slump in prices cited by petitioner are no longer reliable due to the impact of Covid- 19. In this regard, the Authority notes that information on record also contains historical data which demonstrates that steel prices are cyclical in nature and the Authority further notes that the interested parties have also not denied that the prices of steel are subject to peaks and troughs from time to time.
165. As regards the contention that the Authority should not include the 18-month period (April 2019 to September, 2020) affected by Covid-19 pandemic, it is noted that the POI adopted in a number of investigations conducted by the Authority have included the said period. A longer period of investigation is appropriate in the present sunset review since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. In view of the above, period of investigation (POI) of 18 months from 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2020 is considered appropriate. The injury investigation period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the period of investigation i.e., 1<sup>st</sup> April 2019 to 30<sup>th</sup> September 2020.
166. As regards the contention that volume of imports have not increased as a result of reduction of BCD under the India-Japan CEPA, the Authority notes that as the anti-dumping duty is based on a reference price, it prevents imports from entering the domestic market at prices below such reference price notwithstanding reduction in BCD.
167. Some of the interested parties have claimed that imports have reduced from the base year despite demand remaining at similar levels as a result of the anti-dumping duties and the domestic industry is no longer suffering from injury. In this regard, the Authority has examined whether cessation of anti-dumping duties will again lead to an increase in dumped imports and recurrence of material injury to the domestic industry as a consequence.
168. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. It is noted that the present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.

**i. Continued & existing dumping and injury**

169. The Authority notes that the imports of product under consideration in the current period of investigation, are at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. Further, dumping margin is positive from the subject countries.

170. It is also noted that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, domestic sales, inventories, profits, cash profits and return on capital employed.

171. The volume of dumped imports has remained significant during the period of investigation despite the existence of anti-dumping duties.

**ii. Export prices to third countries**

172. The Authority notes on the basis of information on record that exports from subject countries to third countries are largely priced lower than the exports to India.

	HR Coils Avg Export Price to India (2019)	HR Coils Avg Export Price to World (2019)	HR not in Coils Avg Export Price to India (2019)	HR not in Coils Avg Export Price to World (2019)
<b>Brazil</b>	-	493	-	669
<b>China</b>	576	514	745	560
<b>Indonesia</b>	-	506	580	552
<b>Japan</b>	529	536	993	694
<b>Korea</b>	585	558	664	658
<b>Russia</b>	-	476	-	614

(Source: ITC Trade Map)

173. The Authority notes that the subject countries which did not have any exports to India were exporting to third countries at lower prices. In respect of HR in coils, third country export prices of countries that did not export to India were lower compared to the third country export prices of countries that had exported to India. In respect of HR not in coils also, third country export prices of countries that did not export to India were generally lower than the third country export prices of some of subject countries.

**iii. Production in excess of demand in the subject countries**

174. As per the information on record, the subject countries have significant excess production than consumption within the country.

	Production			Consumption			Excess Production		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
China PR	996.3	920	870.9	907.5	836.1	773.8	88.8	83.9	97.1
Japan	99.3	104.3	104.7	63.2	65.4	64.4	36.1	38.9	40.3
Indonesia	6.4	6.2	5.2	DNA	DNA	DNA	DNA	DNA	DNA

Russia	71.9	72.1	71.5	43.5	41.4	41.2	28.4	30.7	30.3
Korea RP	71.4	72.5	71	53.2	53.7	56.3	18.2	18.8	14.7
Brazil	32.2	35.4	34.5	20.6	21.2	19.6	11.6	14.2	14.9
<b>Total</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>1088</b>	<b>1017.8</b>	<b>955.3</b>	<b>183.1</b>	<b>186.5</b>	<b>197.3</b>

(Source: WSA)

175. China produces 88.8 Mn MT in excess of demand in China during 2019. Japan, Russia, Korea RP and Brazil produce in excess of their demand by 36.1 Mn MT, 28.4 Mn MT, 18.2 Mn MT and 11.6 Mn MT respectively during the year 2019. The trend is historical as production in excess of demand existed during the previous years also. This shows that they are highly export oriented.

#### iv. Unutilized Capacities

176. As per the information on record, the producers/exporters in subject countries have significant unutilized capacities.

Countries	Capacity			Production			Unutilized Capacity		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
<b>China PR</b>	1152	1128	1164	996.3	920	870.9	156	198	293
<b>Japan</b>	130	130	130	99.3	104.3	104.7	31	26	25
<b>Indonesia</b>	12	11.5	11	6.4	6.2	5.2	5.5	5.5	6
<b>Russia</b>	87	86	86	71.9	72.1	71.5	15	14	15
<b>Korea RP</b>	82	82	82	71.4	72.5	71	11	10	11
<b>Brazil</b>	51	51	51	32.2	35.4	34.5	19	16	17
<b>Total</b>	<b>1502</b>	<b>1477</b>	<b>1513</b>	<b>1277.5</b>	<b>1210.5</b>	<b>1157.8</b>	<b>225.5</b>	<b>268</b>	<b>356</b>

(Source: WSA and OECD)

177. Capacity in the subject countries have increased during 2019 as compared to the previous year. Production has increased at a higher rate than the rate of increase in capacity. The unutilized capacity in the subject countries is 225.5 Mn MT which is far higher than the demand in India.

#### v. Decline in exports from the subject countries

178. As per the information on record, exports from the subject countries have declined during 2019 compared to 2018.

#### vi. Trade Remedial Measures by other countries

179. As per the information on record, there are currently a number of trade remedial measures imposed against the subject countries by other countries besides India.

#### vii. Reduction in Basic Customs Duty

180. The Authority notes that Basic Customs Duty on imports of subject goods has been reduced from 12.5% to 7.5% w.e.f. February 2021. Imports from Korea RP and Japan are subject to 0% basic customs duty due to India-Korea CEPA and India-Japan CEPA.

#### viii. Cyclical nature of Steel price

181. The Authority also notes that steel prices are cyclical in nature and has remained extremely volatile over the years. The prices are subject to significant variations with prices peaking over certain periods followed by crashes. Current steel prices show an upward trend due to supply side shortage and high raw material prices.

Hot Rolled Band (mt)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Apr 2020	May 2021	June 2021	2021 (Q3)	2021 (Q4)	2022	2023 - 2030
World Export Market (FOB)	370	382	530	580	498	487	390	1070	1050	975	750	650	513

(Source: WSD)

**D.3 L. Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury**

182. From an examination of the evidence on record, the Authority notes that dumping has continued from the subject countries, except Brazil and Russia, and the margin of dumping is also significant. Furthermore, the volume of dumped imports from the subject countries except Brazil and Russia have remained significant during the period of investigation despite the existence of an anti-dumping duty. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated during the POI. The Domestic Industry is suffering from continued material injury during the present POI. The evidence on record also shows that export prices from the subject countries to third countries is lower than their prices to India. While there were no imports from Russia and Brazil during the POI, information on record shows that their export price to third countries is lower than the third country export price of subject countries which had exports to India. The subject countries also have surplus production of the subject goods as well as unutilized capacities. Furthermore, a number of third countries have imposed a number of trade remedial measures on the subject countries which has limited other export markets to absorb the surplus production and unutilized capacities existing with the subject countries. Considering the surplus production, unutilized capacities and trade remedial measures imposed by other countries which limit the markets to which the subject countries can export, the Authority notes that the exporters in the subject countries are likely to use such surplus production and unutilized capacities to dump the subject goods in increased quantities from the existing levels which are already very significant. The Authority also notes that the subject countries are likely to divert their exports from other countries, which are being made at lower prices, to India in the event of cessation of ADD. Thus, all these parameters indicate that, in the event of cessation of the existing ADD, the subject countries are likely to intensify exports of the dumped products to India at dumped prices, leading to continuation of dumping and intensified injury to the domestic industry.

**J. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS BY INTERESTED PARTIES****J.1. Submissions by Domestic Industry**

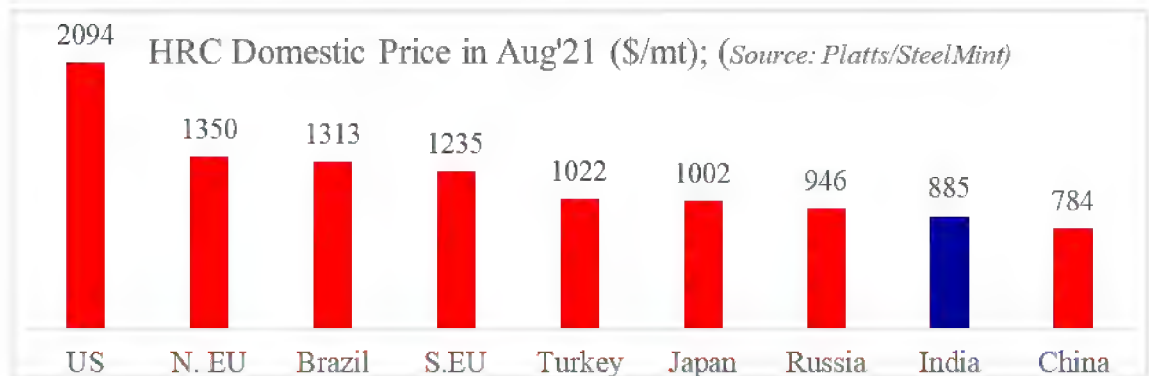
183. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. The domestic producers have either produced the grades against which the interested parties have claimed exclusion or have the capacity to manufacture the same upon order. The interested parties have not claimed that these grades are newly developed or were not in existence when the PUC was being determined under the original investigation.
- ii. It is not sufficient for the respondents to claim that the DI does not have the capability, without spelling out the exact specifications of such grades. Rather, it is for the user industry to claim that the domestic industry is not capable of supplying a product. It is to be demonstrated that an effort to procure the same from DI was made and was met with refusal. No such claim has been made out.
- iii. Hyundai has listed a few grades as easily substitutable but did not seek exclusion of those grades. It is clarified that the DI has the capacity to produce the mentioned grades, and has indeed produced and sold them as evidenced by sales invoice. No proof has been produced by any interested party showing that the DI could not supply any specific grade.
- iv. Schemes such as BIS standards, SIMS, PLI scheme and the steel recycling policy, are targeted towards increasing the efficiency and competitiveness of the domestic industry but

the same cannot shield it against the injurious effects of dumped imports. Since steel prices are cyclical, when steel prices reduce, considering the present degree of dumping by the exporters and producers, import prices of the PUC from the subject countries will also reduce drastically. This would lead to increased injury to the DI.

- v. The interested parties have themselves admitted that the ADD imposed at a reference price basis prevents unnecessary penalization on imports which are being made at a price higher than the NIP of the DI and hence, are not harming the DI. The users of the PUC have admitted that they are not adversely affected.
- vi. With respect to Brazil and Russia, the non-cooperation of producers and exporters establish that there is an imminent threat of resumption of exports to India at dumped prices
- vii. The DA has observed that NSC has sales through a non-cooperative related entity. The DA has observed that such domestic sales are insignificant. It is submitted that noncooperation by a related entity must be viewed seriously and an adverse inference must be drawn in view of the activities carried out by the related selling entity may be wider in scope and may cover transactions other than those that are resold by them and the costs of reselling and other expenses incurred by such related entity may be on the higher side. In both the situations, consideration of whether cost reported by cooperating producer includes whole of cost incurred by related selling entities commensurate with activities carried out by them is necessary. Since the related entities have not cooperated, response of NSC must be rejected.
- viii. With respect to export price determination of NSC, Japan, JFE Steel Corporation, POSCO Korea RP and PT Krakatau POSCO, Indonesia, Authority observed that these entities have exported some quantities through certain entities who have not filed questionnaire responses. However, exports from such entities was considered insignificant. The very fact that certain exporters or related trading companies have not participated is a sufficient ground for rejection of the responses of producers and no individual dumping margin must be determined.
- ix. The price undercutting from the subject countries being negative does not indicate that the imports did not have price suppressing and depressing effects. It is relevant to note that subsidiaries of certain interested parties have resold the PUC at a loss. Such factors are indicative of the fact that the weighted average import prices do not allow a proper comparison of the price suppressing and depressing effects as the imports are being resold at a loss by related entities of the producers in the subject countries to independent buyers.
- x. While the average import prices may show a lower or negative price undercutting, such practices by producers and their related entities in India result in a much narrower margin of price competition leading to the aforesaid price suppressing and depressing effects. It is submitted that the examination of negative injury margin is also required to be made in the same perspective.
- xi. While the imports from other countries were insignificant, imports from subject countries remained significant at 7% due to dumping practices. Dumping margin was as high as 50% in some cases. This leads to the conclusion that: (i) the Indian industry is competitive and selling goods at far cheaper rates; (ii) had dumping from the subject countries not continued to such a significant degree, price pressure from the subject countries would have been far less felt and domestic industry would have been able to continue supplying users at better rates than that capable of being supplied by producers in the subject countries in absence of unfair competition of dumping.
- xii. Certain parties have stated that as the injury margin is negative, the anti-dumping duties must be discontinued. Various past investigations demonstrate that if there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the anti-dumping duties are continued notwithstanding a negative injury margin.
- xiii. Continuation of the anti-dumping duties would be in public interest as the interested parties have themselves admitted that the present anti-dumping duties imposed on the basis of reference price prevents unnecessary penalization on imports which are being made at a price higher than the NIP of the DI and hence, are not harming the DI.

- xiv. User industry has failed to show, through quantified information, any adverse impact on their operations or the public at large. In most cases, users have imported goods above the reference price and thus, did not incur any ADD.
- xv. Imposition of anti-dumping duties would not affect the availability of the product to the consumers either as the domestic industry has demonstrated that it has the capability of supplying all grades with respect to which the interested parties have raised a claim for exclusion.
- xvi. Steel prices in India have remained lower than international prices despite the ADD imposed. The prices offered by the domestic industry would continue to be the lowest amongst all sources in the absence of unfair dumping.
- xvii. Steel industry is critical for nation building contributing to around 2% of GDP and generates substantial direct (approx. 5 lakhs) and indirect employment (approx. 20 lakhs). The 2015 downward spiral had led to a debt of more than Rs. 2 lac crores, adversely affecting the Indian banking sectors, investors and other stakeholders.
- xviii. Impact of ADD on downstream industries would be negligible, for example, a 20% ADD on HR Steel would cause a 0.17% impact on affordable housing.
- xix. The Authority has made certain adjustments in arriving at the NIP allowed for the product concerned. Adjustments made by the authority are excessive and not in line with the extant rules. The Authority should revise the NIP to the level claimed by the domestic industry.
- xx. The domestic steel prices in India have remained lower than international steel prices despite the existence of the current anti-dumping duties and the global boom.



### **J.2. Submissions by the other interested Parties**

184. The submissions of the other interested parties are as follows:

- i. The Authority should verify whether the domestic industry has actually produced and sold the grades against which exclusion has been sought by NSC.
- ii. The acceptance or rejection of request for exclusion should not be based on a PCN-to-PCN comparison between DI's grades and producer's grades. Rather, the Authority should examine if the relevant grades were produced and sold by the DI in the POI.
- iii. The DGTR should consider the relevant information in questionnaire responses by the users of PUC produced by the Japanese mills.
- iv. The DGCI&S transaction-wise data has not been made available to Japanese mills, despite request for the same.
- v. Since the DGTR has determined dumping and injury margin separately for HR in coils and HR not in coils in the disclosure statement, the DGTR should conduct a separate assessment of domestic industry standing and injury assessment too.
- vi. The existence of SIMS, BIS standards, PLI schemes, steel recycling policy, and other policies aimed at protecting the domestic industry must be taken into account in DGTR's assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping and material injury. If the



domestic industry is being protected by the existing policies, whereby there is no necessity of continuation of anti-dumping duties, it does not justify penalizing the importers / users in India who would be burdened on account of imposition of duties.

- vii. The DGTR in the past investigations has segregated the DGCIS data on PCN basis for average dumping margins. The same should be done for the present investigation.
- viii. The DGTR has adopted an inconsistent/selective approach in its injury analysis. For instance, at Paragraph 130 of the disclosure statement, the DGTR has assessed price suppression / depression comparing the figures in the POI with the base year. Whereas, at Paragraphs 140 and 141, the DGTR has assessed the profitability of the domestic industry by making a comparison of the figures in the POI with previous (instead of the base year). The DGTR must adopt a consistent approach,
- ix. The data considered by the DGTR in its disclosure statement is different from the data filed by the Petitioner previously. The DGTR is accordingly requested to immediately issue a clarification providing the reasons as to why the data provided by the Petitioner is different from that relied upon in the disclosure statement.
- x. The observation of the DGTR that contraction in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry is contradictory, as DGTR has in Para. 134(iii) has noted that the sales and capacity utilization have been impacted due to decline in demand.
- xi. Lower demand and higher finance costs have impacted the performance of the domestic industry. These have been admitted by the DI in its Annual Report.
- xii. According to the World Steel Association (whose members represent around 85% of global steel production), the demand for steel in India reduced by 14.1% in 2020 compared to 2019.
- xiii. The Petitioner's submission on the cyclical nature of steel prices clearly demonstrates that there is no causal link between the performance of the domestic industry and imports from the subject countries.
- xiv. The import prices in the present case are much higher than the reference price, which clearly demonstrates that the price increase is based on commercial considerations and not artificially inflated due to the reference price based anti-dumping duty.
- xv. The prices of hot rolled not in coils exported from Japan to India are significantly higher than that sold to other countries. As per DGTR, since prices in India are higher, the Japanese mills would have already exported significant quantities of hot rolled not in coils to India. It is worth considering that this is not the case because imports are made based on various commercial considerations.
- xvi. The DGTR has not disclosed source for its claim that the production in India is in excess of demand. Further, existence of significant production in excess of consumption does not prove that the subject countries are export oriented. Further, exports to India have decreased while exports to third countries have remained stable, and there is no evidence of unutilized capacities. Therefore, there is no likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury.
- xvii. The DGTR has not disclosed the source of its information for the observation that the capacity utilization in the subject countries is far higher than the demand in India. Assuming there are unutilized capacities which can be utilized towards India, the producers from Japan would have already done the same towards India, which does not appear to be the case in the present case.
- xviii. Between June 2020 to August 2021, the Ministry of Finance has considered it appropriate not to recommend duties in 4 out of 6 cases falling under the category of "steel and other metals" even though the DGTR had recommended the imposition of duties.
- xix. No non-confidential copy of proof that DI is manufacturing HR plates conforming to EN S-355/IS E-350 has been made available to the respondents. Further, while the DI may have submitted proof of its ability to manufacture EN S-355/IS E-350 compliant grades, the plates

manufactured by PTKP are far superior to the mandatory standards prescribed under the Indian and European guidelines.

- xx. While the profit and ROCE have improved from the base year, the same have reduced during the POI. Such change has been on account of slump in demand and effects of COVID-19. The negative growth determined in the POI is also on account of the same.
- xxi. No evidence has been provided to support the claim that unutilized capacity of the respondents would be directed to India. Article 3.2 of the ADA provides that it is only based on positive evidence that a determination of injury can be made. This has been held in the case of *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, where it was held that the existence of surplus capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury. Thus, no likelihood can be made out from excess capacities.
- xxii. Regarding public interest, it is submitted that EN S355 /IS E-350 compliant grades, are suited for windmill construction and major renewable projects. The user industry in the absence of equivalent supply from the DI will have to bear an additional burden of the ADD.

### **J.3. Examination by the Authority**

185. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority are examined below:

- i. As regards the submission of the domestic industry that no individual dumping margin should be granted to the cooperating producers from the subject countries as a number of their related/unrelated traders and exporters have not participated, the Authority notes that exports to India made through noncooperating unrelated parties are very insignificant in terms of total exports to India. For working out export price of the producers, the Authority has considered the actual export price for the chain comprising producers and cooperating traders who had duly participated in the investigation and submitted response in the form and manner prescribed, and export price based on the best available information for the non-cooperating traders who had not filed the information in the form and manner prescribed. Accordingly, dumping margin has been determined taking into account the weighted average export price of all exports' channels to India.
- ii. With respect to the contention of NSC that PCN to PCN comparison of the grades supplied by NSC and that supplied by the domestic industry should not be conducted to adjudicate upon product exclusion as it is not in line with the practice of the DGTR, the Authority notes that a similar PCN to PCN comparison of grades produced by the domestic industry and the exporter was made during the original investigation. The Authority also notes that the submissions of the domestic industry that it has supplied some of the grades was disclosed in the disclosure statement pursuant to which, NSC has requested the Designated Authority to verify the same. The Authority has verified evidence provided by the domestic industry and finds that they have produced some of the grades against which exclusion has been sought. Further, it has been claimed by the domestic industry that it has the capability of producing them if orders are received for the same. In this regard, it is also noted that none of the users have provided any evidence to demonstrate that the domestic industry could not supply any of the grades against which exclusion has been sought by the producers and exporters. The producers and exporters have also not demonstrated that the grades against which exclusion has been sought are not substitutable by any other grade falling within the scope of the PUC. Therefore, the Authority holds that no exclusion is warranted from the scope of the PUC.
- iii. With respect to the contention that no non-confidential copy of proof that DI has been manufacturing HR plates conforming to EN S-355/IS E-350 has been made available, the Authority has verified sales information filed on confidential basis, and has disclosed these facts in the disclosure statement.

- iv. With respect to the claim that DGCI&S transaction-wise data has not been made available to Japanese mills despite a request for the same, the Authority notes that it has provided authorization for obtaining DGCI&S data to all parties who have made a request in the proper format as per Trade Notice No.07/2018.
- v. With respect to the contention that as dumping and injury margin have been calculated separately for HR in coils and HR not in coils and therefore, a separate assessment of domestic industry standing and injury assessment too regarding the same should be conducted separately, the Authority notes that calculation of separate dumping and injury margins with respect to HR in coil and HR not in coil is to ensure a fair comparison between normal value and export price or landed value and NIP. Making such a comparison does not imply that the entire injury analysis needs to be conducted separately. It is also noted that all the applicant domestic producers produce the PUC which includes both HR in Coil and HR not in coil and further, that even in the original investigation, no such separate injury examination was performed.
- vi. With regard to the argument that the existence of SIMS, BIS standards, PLI schemes, steel recycling policy, and other policies aimed at protecting the domestic industry must be taken into account in assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping and material injury since the domestic industry is being protected by the existing policies which does not necessitate penalizing importers / users who would be burdened on account of continuation of duties, the Authority notes that the domestic industry has become more competitive which is evidenced by the fact that despite dumping having continued from the subject countries and the dumping margin also being substantial, the domestic industry has been able to supply the subject goods at prices below the dumped imports. The Authority also notes that since steel prices have historically been cyclical in nature with peaks and slumps witnessed from time to time, such a high margin of continued dumping would cause material injury to the Domestic Industry in the absence of an anti-dumping duty when prices of steel fall again. The Authority also notes that the users and importers have made imports from the subject countries above the reference price of the ADD currently in force and therefore, the same has not impeded them from procuring the subject goods.
- vii. With respect to the contention that submissions of interested parties with respect to likelihood of continuation of injury analysis vis-à-vis statements made by the domestic industry, and various trends and government programs/initiatives in favour of domestic steel industry have not been considered, the Authority notes that it has examined all information provided by the interested parties with respect to the PUC to the extent considered relevant for the examination of continuation or likelihood of recurrence of both dumping and injury.
- viii. With respect to the contention that in the past investigations, DGCI&S data has been segregated on PCN basis for average dumping margins, the Authority notes that the official DGCIS statistics could not be converted in terms of PCN as the description given in the DGCIS data was not sufficient enough to determine the PCN for an overwhelmingly large number of import transactions.
- ix. With respect to the contention that an inconsistent approach has been applied in the injury analysis since price suppression and depression has been compared with the base year whereas profitability has been compared with the previous year, the Authority notes that it has objectively analysed the price effect, and its impact on the domestic industry considering during the entire injury period. It was noted during the examination that prices of the domestic industry increased till 2018-19 when prices of imports were also increasing. Thereafter, when prices of imports declined during the period of investigation, the prices of the domestic industry also declined. However, the decrease in selling price of the domestic industry was more than the decrease in its cost of sales during the POI indicating that its prices were both suppressed and depressed during the POI as compared to previous year. With regards to profits, it was noted that

after imposition of ADD, profit per MT increased significantly till 2018-19. However, profits declined sharply during the POI. A similar trend is seen in respect of PBIT and cash profit.

- x. With respect to the contention that the data considered in the disclosure statement is different from that filed by the Petitioner, it is noted that the said figures have been revised after verification of the information conducted by the Authority.
- xi. Some of the interested parties have raised the argument that the observation of the Authority in the causal link analysis that contraction in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry is contradictory to the observation of the Authority that sales and capacity utilization have been impacted due to decline in demand. In this regard, the Authority notes that the demand during the POI has remained at the same level as the base year i.e., 2016-17. However, while production and sales reduced during the POI from 2018-19, and was at the same level as that of the base year, the domestic industry earned a lower return on capital employed than that of the base year due to the fall in prices of imports.
- xii. With respect to the contention that lower demand and higher finance costs have impacted the performance of the domestic industry, the Authority has verified the information provided with respect to economic parameters of the domestic industry regarding the PUC and has noted that finance cost has actually reduced during the POI compared to the base year and therefore, is not one of the reasons for low profitability of the domestic industry. Furthermore, the Authority notes that while the demand is at the same level as that of the base year, the profitability of the domestic industry has declined to a higher extent.
- xiii. With regards to the claim that according to the World Steel Association, the demand for steel in India reduced by 14.1% in 2020 compared to 2019, the Authority notes that the data on record also establishes that demand has decreased during the POI from that of 2018-19 and reduced to the same level as the base year.
- xiv. With regard to the argument that the cyclical nature of steel prices clearly demonstrates that there is no causal link between the performance of the domestic industry and imports from the subject countries, the Authority notes that while dumping has continued, the current anti-dumping duties have prevented low priced dumped imports from entering the domestic market and causing injury to the domestic industry. However, while the prices of steel are presently high and dumped imports are entering India above the reference price of the ADD currently in force, such dumped imports would cause material injury to the domestic industry when steel prices fall again, in the event of cessation of ADD.
- xv. With respect to the contention that the import prices are much higher than the reference price which demonstrates that price increase is based on commercial considerations and not artificially inflated due to reference price based anti-dumping duty, the Authority notes that dumping has continued from the subject countries to a significant degree, and therefore, the Authority has examined whether continued dumping has led to material injury as well as whether there is a likelihood of recurrence of material injury if the anti-dumping duties are removed.
- xvi. With regard to the argument that prices of hot rolled not in coils exported from Japan to India are significantly higher than that sold to other countries and as such, Japanese mills would have already exported significant quantities of hot rolled not in coils to India but that is not the case because imports are made based on various commercial considerations, the Authority notes that the reference price based ADD has prevented low priced dumped imports from entering the country from the subject countries. The Authority also notes that the ADD currently in force has prevented the subject countries from employing their unutilized capacities to increase imports to India.

- xvii. With respect to the argument that the source for the claim that the production in India is in excess of demand has not been disclosed, it is noted that the total production of the PUC in India is as per the report issued by the Joint Plant Committee and the said figures were contained in non-confidential submissions filed with the Authority which were circulated with all interested parties during the course of the investigation.
- xviii. With respect to the claim that the source of information for the observation that the capacity in subject countries is far higher than the demand in India has not been disclosed, it is noted that the said data is derived from WSA and OECD reports contained in non-confidential submissions filed with the Authority which were circulated with all the interested parties during the course of the investigation.
- xix. With respect to the contention that no evidence has been provided to support the claim that unutilized capacity of the respondents would be directed to India, the Authority notes that as per the information on record, a number of trade remedial measures have been imposed on the subject countries by third countries. This has led to a high volume of unutilized capacities in the subject countries and no evidence has been provided by any interested party to demonstrate that there are other export markets besides the third countries which have imposed anti-dumping duties on the subject countries.
- xx. With respect to the contention that EN S355 /IS E-350 compliant grades are suited for windmill construction and major renewable projects and the user industry will have to bear an additional burden of the ADD in the absence of equivalent supply from the domestic industry, the Authority notes that no information has been filed by any user that anti-dumping duties have been paid on imports of the said grades from the subject countries. Furthermore, the Authority notes that the domestic industry has supplied the same to users in the domestic market.
- xxi. With respect to the claim of the domestic industry that adjustments in arriving at the NIP made by the authority are excessive, the Authority notes that the same has been determined in accordance with Annexure III of the Rules and therefore, no revisions are warranted to the NIP.

#### **K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

- 186. The Authority has considered whether continuation of anti-dumping duty would have adverse public interest. For the same, the Authority has examined whether the continuation of the duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and the interests of various parties, including the domestic industry, importers and users/consumers of the product.
- 187. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, users and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present sunset review investigation, including the possible effect of the continuation of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, reasons for import of the product under consideration, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries and also the product supplied by the domestic industry, effect of the continuation of anti-dumping duty on the consumers, source of imports (whether from related suppliers or unrelated suppliers), profitability statement for their operations etc.
- 188. The Authority notes that following users have filed questionnaire response:
  - i. POSCO-Maharashtra Steel Private Limited.
  - ii. Hyundai Steel Pipe India Pvt. Ltd
  - iii. Hyundai Motor India Limited
  - iv. Nippon steel pipe India private ltd
  - v. Rajasthan Prime steel Processing center Pvt Ltd

189. These users also attended the oral hearing and made submissions, which have been taken into account. The Authority notes that the users who have participated in the present sunset review investigation and submitted user's questionnaire are related to the foreign exporters and are either importing the product under consideration from their related parties or are using the product under consideration supplied by their related parties. These interested parties have not shown with quantified information that the imposition of the reference price based anti-dumping duty had any significant adverse effect either on these users or the public at large. The interested parties have also not shown with quantified information that the continuation of the anti-dumping duty would have a significant adverse effect on their operations in India.
190. From the information on record, it is noted that imports have occurred above the reference price during the period of investigation and no burden of anti-dumping duty has been faced by the users and therefore, it is not possible to quantify the impact of reference price based anti-dumping duty on the users. The Authority notes from the submissions filed by the domestic industry that hypothetically, assuming an anti-dumping duty at the rate of 20% on the PUC, it can be seen that the impact would be negligible i.e. less than 0.17% of the total value of an affordable house of Rs.2 lakhs.
191. The Authority notes that as per information available on record, steel prices in India including for the product under consideration have remained lower than global steel prices even in a situation where there has been an overall increase in global steel prices recently. This shows that the domestic industry in India has not unduly benefited from the anti-dumping duty in force or the recent increase in global prices and as such, the importers/users/consumers of the product under consideration have not been prejudiced due to the existence of the prevailing anti-dumping duty and recent increase in global steel prices.
192. It is noted that the domestic industry is supplying the subject goods at competitive prices is also evidenced by the fact that the price undercutting has been negative from the subject countries throughout the injury analysis period. This means that the domestic selling price has been lower than the landed value of imports from the subject countries throughout the entire injury analysis period including the POI when the dumping margin from the subject countries were very high.
193. The information on record shows that the manufacturing facilities of the domestic industry are underutilized. The domestic producers in India are fully competent to cater to the entire demand of the product under consideration in India.
194. The Authority notes that fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of the anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
195. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of the anti-dumping measures have not restricted imports from the subject countries in any way either and as such, would not affect the availability of the product to the consumers even in a situation where the users choose to source it from the subject countries.
196. The Authority notes that Indian steel industry is critical for Indian economy taking into account its contribution to Indian GDP, direct and indirect employment generation and its support to linked downstream services such as transport services, port facilities etc. Continuation of duty would act as a safety net for the domestic industry from unfair trade practices and the cyclical nature of global steel prices that are projected to decline in near future.
197. Therefore, from the information on record, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest

#### **L. CONCLUSION**

198. After examining the submissions made by the interested parties and the issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a. The applicant domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by the applicant on behalf of domestic producers satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- b. The product produced by the domestic industry is like article to the PUC imported from the subject countries.
- c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review.
- d. The Authority considered a longer period of 18 months from 1st April 2019 to 30th September 2020 as the POI so that it provides enough requisite insight into the current and likely dumping and injury suffered by the domestic industry. Also, a longer POI was deemed appropriate in the present sunset review since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports.
- e. Based on the facts available on record, the normal value, export price and the dumping margin for the subject goods have been determined except in the case of Brazil and Russia, and the dumping margins so determined are significant. There is a continuation of dumping of the subject goods from China, Japan, Korea RP and Indonesia.
- f. Since there were no imports from Brazil and Russia, no dumping margin was determined for the POI. However, the facts on record show that the export prices from Brazil and Russia to third countries were lower than the even the export prices of subject countries who have exports to India. Therefore, there is a likelihood of recurrence of dumping from Brazil and Russia if the duties are withdrawn.
- g. The domestic industry has suffered material injury in view of the following:
  - i. Volume of dumped imports from subject countries have remained significant.
  - ii. While both production and sales of the domestic industry declined during the POI along with imports from the subject countries due to a reduction in demand which came down to the same level as the base year, the decline in prices of imports suppressed and depressed the prices of the Domestic Industry leading to a significant decline on return on capital employed to a level lower than that of the base year.
- h. There is likelihood of continuation and recurrence of injury to the domestic industry due to the following:
  - i. Export prices of the subject countries to third countries are lower than their prices to India which indicates that such exports can be diverted to India if the anti-dumping duties are removed;
  - ii. Subject countries have significant unutilized capacities and excess production compared to the demand in the respective countries;
  - iii. Exports from the subject countries face a large number of trade remedial measures from third countries which limits their potential to export the existing surplus production as well as employ their unutilized capacities.
  - iv. Unutilized capacities and surplus production are likely to be utilized to export to India in the event of cessation of the existing duties
  - v. Basic Customs Duty on imports of subject goods has been reduced from 12.5% to 7.5% w.e.f. February 2021.
  - vi. Historical trend of global steel prices show that steel prices are cyclical in

nature and there is a likelihood of injury to the domestic industry due to imports at low price when there is a decline in global steel prices.

- i. The Authority has considered whether continuation of anti-dumping duty would have adverse public interest. The Authority notes that there is healthy competition in the Indian market and continuation of anti-dumping duty would not lead to monopolistic or oligopolistic situation in the Indian market for the subject goods.

199. In view of the above, the Authority finds that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury upon cessation of the existing anti-dumping duties and recommends continuation of anti-dumping measures for a further period of five years.

## J. RECOMMENDATIONS

200. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on the subject goods from the subject countries.

201. The Authority notes that the producers/exporters from China PR, Korea RP and Japan participated in the original investigation and there was no participation from other countries. However, producers/exporters from China PR have not participated in the present sunset review investigation but producers/exporters from Indonesia have participated in the present sunset review investigation. In such a scenario, the Authority deems it appropriate to prescribe the duty table afresh as given herein below.

202. The Authority recommends continuation of antidumping duty on the imports of the goods described in col.3 of the duty table below originating in or exported from the subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Anti-Dumping duty is recommended as the difference between the landed value of the goods described in Col.3 of the duty table below and the amount indicated in Col.7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col.7. If landed value is more than the value indicated in Col 7, anti-dumping duty will not be applicable. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

### D.4 Duty Table

S.No.	Headingg/ Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7208, 7211, 7225 and 7226	Hot- rolled flat products of alloy or non- alloy steel in coils of a width upto 2100 mm and thickness upto 25mm	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Steel Company	478	MT	US\$
2.	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO	489	MT	US\$
3.	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other than S. No. 1 & 2	489	MT	US\$



4.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Korea RP	Any	489	MT	US\$
5.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	JFE Steel Corporation	489	MT	US\$
6.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	Nippon Steel Corporation	489	MT	US\$
7.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	Any other than S. No. 5 & 6	489	MT	US\$
8.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Japan	Any	489	MT	US\$
9.	- do -	- do -	China PR	Any country including China PR	Any	489	MT	US\$
10.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	ChinaPR	Any	489	MT	US\$
11.	- do -	- do -	Russia	Any country including Russia	Any	489	MT	US\$
12.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Russia	Any	489	MT	US\$
13.	- do -	- do -	Indonesia	Any country including Indonesia	Any	489	MT	US\$
14.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Indonesia	Any	489	MT	US\$
15.	- do -	- do -	Brazil	Any country including Brazil	Any	489	MT	US\$
16.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Brazil	Any	489	MT	US\$

S.No.	Headingg/ Sub heading g	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	7208, 7211, 7225 and 7226	Hot- rolled flat products of alloy or non- alloy steel not in coils (com monl y known as sheet s and plates) of a width upto 4950 mm and thick ness upto 150 mm	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Steel Company	561	MT	US\$
2.	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO	561	MT	US\$
3.	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other than S. No. 1 & 2	561	MT	US\$
4.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti- dumping duty	Korea RP	Any	561	MT	US\$
5.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	JFE Steel Corporation	561	MT	US\$
6.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	Nippon Steel Corporation	561	MT	US\$
7.	- do -	- do -	Japan	Any country including Japan	Any other than S. No. 5 & 6	561	MT	US\$
8.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti- dumping duty	Japan	Any	561	MT	US\$
9.	- do -	- do -	ChinaPR	Any country including China PR	any	561	MT	US\$
10.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti- dumping duty	ChinaPR	Any	561	MT	US\$
11.	- do -	- do -	Russia	Any country including Russia	Any	561	MT	US\$
12.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti- dumping duty	Russia	Any	561	MT	US\$
13.	- do -	- do -	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Krakatau POSCO	561	MT	US\$
14.	- do -	- do -	Indonesia	Any country including Indonesia	Any other than serial no 13	561	MT	US\$

15.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Indonesia	Any	561	MT	US\$
16.	- do -	- do -	Brazil	Any country including Brazil	Any	561	MT	US\$
17.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Brazil	Any	561	MT	US\$

203. The description of goods in the column no 3 in the above duty table does not include the imports of the following:

- a) Hot-rolled flat products of stainless steel.
- b) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc.
- c) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc.
- d) Cladded steel.

#### **M. FURTHER PROCEDURE**

204. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority